R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 I अंक : 15

01 से 15 मई 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

धरती को लील रहा है ग्लोबल वार्मिंग

भारत में 2050 के बराबर
2022 में ही पड़ रही गर्मी

विनाश की राह पर धरती,
बचाने में न हो जाए देर

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

मिसाल

9 | 'स्वच्छ इंदौर' में समाई नंबर-1...

2017 से इंदौर स्वच्छता में लगातार पहले पायदान पर कायम है। लेकिन इसके पीछे अफसरों, कर्मचारियों और इंदौरवासियों की सोच, समझ, समर्पण और सेवाभाव का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छता में इंदौर...

राजपथ

10-11 | भाजपा का मिशन 2023 तैयार

मप्र भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मिशन 2023 की प्लानिंग कर ली है। यह चुनाव उप्र मॉडल पर लड़े जाएंगे। मप्र भाजपा के कोर ग्रुप की केंद्रीय नेताओं के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर...

मप्र कांग्रेस

15 | कांग्रेस में नई जमावट

मप्र में भले ही दो साल पहले असमय कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा हो, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के दिग्गज नेताओं का कद पार्टी हाईकमान के सामने कम नहीं हुआ है। हाल ही के कुछ दिनों को देखें तो मप्र के कांग्रेस नेताओं की दस जनपथ में पूछताछ...

प्रशासनिक

18 | नाफरमान अफसर जाएंगे लूपलाइन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में हैं। वे ताबड़तोड़ निर्णय कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने प्रदेश के नाफरमान और नाकारा अफसरों पर गाज गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को निर्देश दिया है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत सहित दक्षिण एशिया में इस बार रिकार्डतोड़ गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आती जा रही है और इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण भारत में 2022 में ही 2050 के बराबर गर्मी पड़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती विनाश की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी धरती को बचाने के लिए अब केवल 8 साल ही बचे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। वरना धरती झुलस जाएगी।

राजनीति

30-31 | फिर अधर में रह गई कांग्रेस

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर यानी पीके ने जो फॉर्मूला तय किया था, वह कांग्रेस आलाकमान को पसंद नहीं आया। इसलिए पीके ने कांग्रेस को उसी के हाल पर छोड़ दिया है। एक बार फिर कांग्रेस अधर में लटकी नजर आ रही है।

महाराष्ट्र

36 | फंस गई उद्धव सरकार!

एक विज्ञापन में बड़ी ही खूबसूरत लाइन है- 'अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो, दाग अच्छे हैं!' मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी को नफरत की राजनीति से जोड़कर देखा गया, लेकिन उसका असर तो जैसे जनहित में नजर आने लगा है। बेशक राज ठाकरे ने मस्जिदों...

बिहार

38 | बिहार ने बढ़ाई भाजपा की चिंता

बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन की रार के बीच उपचुनाव में भाजपा को मिली हार ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अप्रैल को राबड़ी देवी के बंगले पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होकर प्रदेश...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

आखिर 600 साल बाद समझ में आई कबीर की वाणी

आज से करीब 600 साल पहले संत कबीरदास ने कहा था...

कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय।
ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय॥

लाकन उस समय से लेकर अभी तक संत कबीरदास की उक्त वाणी पर किसी ने गौर नहीं किया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन एक संत की अपील और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार कर साल दर साल मंदिरों और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की संख्या बढ़ती गई और सांप्रदायिकता के डर से सरकारें चुप रहीं। लेकिन इस साल कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि एक योगी (उप्र के मुख्यमंत्री) ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम शुरू की, जिसे सभी ने स्वीकार किया और आज देशभर में सभी धर्मों के लोग अपने धर्मस्थलों से या तो लाउडस्पीकर हटा रहे हैं या फिर उसकी आवाज कम कर रहे हैं। यह मानवजीवन के लिए जरूरी भी था। वर्तमान में अनेक प्रकार के प्रदूषण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इनमें ध्वनि प्रदूषण भी एक है। ध्यातव्य है कि जिस प्रकार देश का संविधान सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण संबंधी विधान भी सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ईश्वर की आराधना में शोर-शराबे और लाउडस्पीकर जैसे आडंबर की क्या आवश्यकता? चिंता की बात यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है जो वास्तव में हमारे सभ्य और शिक्षित समाज में चौंकाने वाला है। चूंकि लाउडस्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र एक हालिया वैज्ञानिक नवाचार है, इसलिए इस तरह के यंत्र के उपयोग का किसी भी पवित्र ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हमें विदित होना चाहिए कि सबसे पहले मनुष्य आया फिर धर्म और उसके बाद लाउडस्पीकर जैसे यंत्र। इसलिए हकीकत है कि लाउडस्पीकर का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह तो हम सबकी मानसिकता ही धीरे-धीरे ऐसी बनती गई कि मानो अब बिना लाउडस्पीकर के ईश्वर की पूजा आराधना ही नहीं की जा सकती। शायद ही कभी हम सबने सोचा हो कि लाउडस्पीकर किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार में बाधा भी डालता है। मालूम होना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है और संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार वहीं रुक जाता है, जहां दूसरे व्यक्ति का अधिकार शुरू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्तव्य और अधिकार साथ-साथ चलते हैं। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)ए और अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन बढ़ता शोर आज मानवजीवन के साथ जीव-जंतु और पेड़-पौधों को भी प्रभावित करने के साथ जीवन के अधिकार में बाधा बन रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2000 के नियम 5/6 के साथ पढ़ने पर यह ध्वनि प्रदूषण संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के हर्जाने की व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने को मंजूरी भी दी है। इतने सारे कानूनी प्रावधानों के बाद भी अभी तक ध्वनि प्रदूषण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का जो अभियान शुरू हुआ है, वह स्वागत योग्य है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 15, पृष्ठ-48, 1 से 15 मई, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

युवाओं को मिलेगा रोजगार

इंदौर-भोपाल रूट प्रदेश का सबसे कमर्शियल और बेहतर रूट है। आष्टा और सोनकच्छ के बीच बनने वाले देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बन जाने से निवेश के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही इसमें लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

● **कमलेश सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

मप्र के गेहूं की मांग बढ़ी

यूक्रेन में युद्ध के कारण भारत से गेहूं निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए यूक्रेन पर निर्भर रहने वाले इजिप्ट जैसे देशों ने गेहूं आयात करने के लिए भारत का रुख किया है। मप्र का शरबती और मालवी गेहूं गुणवत्ता और पोषक तत्वों के मामले में देशभर में मशहूर है।

● **प्रीति राजपूत,** भोपाल (म.प्र.)

प्रदेश में बढ़ेगा निवेश

पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को काफी नुकसान हुआ था। इस पर विपक्ष बेरोजगारी पर मुखर है। इससे उबरने के लिए इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। जिससे प्रदेश में निवेश की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी।

● **सुरभि मेहतो,** इटारसी (म.प्र.)

भाईचारे का संदेश देना होगा

हाल के कुछ सालों में ही सांप्रदायिक घटनाएं अधिक बढ़ गई हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि गंगा-जमुनी तहजीब वाले इस देश में एक साथ रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग एक-दूसरे के दुश्मन बन गए। और तो और देशभर में अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले मप्र के खरगोन जिले में उपद्रव और आगजनी का ऐसा तांडव मचा कि आज तक उसका डर लोगों के मन में समाया हुआ है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज देश जिस हालात में है, उससे किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को समझदारी दिखाकर आगे आना होगा और भाईचारे का संदेश दुनियाभर को देना होगा। जिससे देश में खुशहाली का माहौल बना रहे।

● **राजेश मिश्रा,** सीहोर (म.प्र.)

कांग्रेस को जनाधार बचाने की जरूरत

कांग्रेस के सिकुड़ते जनाधार के लिए केवल गांधी परिवार ही जिम्मेदार है। पार्टी में अन्य वरिष्ठ नेताओं को आगे आना चाहिए, तभी कांग्रेस का जनाधार बच सकता है और कांग्रेस एक बार फिर मजबूत विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आ सकती है। हाल के वर्षों का राजनीतिक रुझान दर्शाता है कि जहां भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंची, वहां वह दोबारा नहीं उभर पाई। दिल्ली इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और अब तक पंजाब भी उसके हाथ से निकल गया है। बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं लग रही है।

● **राहुल साहू,** नई दिल्ली

नक्सलियों पर नकेल जरूरी

मप्र में लाल आतंक का खतरा फिर बढ़ता जा रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के 70 फीसदी इलाके पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। यहां लंबे समय से कोर और बफर में नक्सलियों के विस्तार दलम और खटिया मोचा दलम की मौजूदगी बताई जाती है। नक्सलियों का प्रभाव बढ़ने से पर्यटक भी घट रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे पर्यटक निर्भय होकर घूम सकें। और मप्र की खूबसूरती को देख सकें।

● **गौरव पांडे,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

महाविकास अघाड़ी का बढ़ता संकट

महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। भाजपा आलाकमान का महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य की सत्ता हाथों से निकल जाने का गम ढाई बरस बाद भी हल्का होता नजर नहीं आ रहा है। इस गम का साइड इफेक्ट महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों और इस गठबंधन में शामिल नेताओं पर तेजी से कस रहे कानूनी शिकंजे के रूप में सामने आ रहा है। एक दूसरा साइड इफेक्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एवं राज्य सरकार के मध्य दिनों दिन बढ़ रहे तनाव से समझा जा सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां विशेष रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर मेहरबान हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले की ईडी जांच चल रही है तो आदित्य ठाकरे के कई करीबियों के यहां भी इनकम टैक्स और ईडी दस्तक दे चुकी है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं तो उनकी पार्टी के बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख अलग-अलग मामलों में जेल की यात्रा पर हैं। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत, प्रताप सरनायक, अनिल परब आदि पर भी इन एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर आदर्श सोसाइटी मामले में मुकदमा चल ही रहा है।

तेलंगाना में बढ़ती कांग्रेस की दुविधा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन दिनों विपक्षी दलों के मध्य एकता कायम करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह ही राव भी विपक्षी नेताओं संग ताबड़तोड़ मुलाकातें कर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करने की वकालत करते घूम रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों के लक्ष्य में फर्क सिर्फ इतना है कि ममता ऐसे किसी भी गठबंधन का नेतृत्व स्वयं करना चाहती हैं। ममता किसी भी सूरत में कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो दूसरी तरफ राव का मानना है कि बगैर कांग्रेस ऐसा कोई भी गठबंधन संभव नहीं है। राव खुलकर गांधी परिवार के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के समक्ष भारी संकट आन खड़ा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के नेता तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी का जमकर विरोध करते आए हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से कांग्रेस के लिए काम करने लगे हैं। गत दिनों पीके ने कांग्रेस आलाकमान संग मुलाकात कर संकेत दे डाले हैं कि हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए वह 'संजीवनी' तैयार करने जा रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी पीके की रिइंट्री चलते खासे संशय में हैं क्योंकि पीके चंद्रशेखर राव के लिए भी काम कर रहे हैं।

बिहार में रार-तकरार चरम पर

भाजपा बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के तीन विधायक दल बदलकर भाजपा में शामिल होने के बाद अब विधानसभा में भाजपा के 77 विधायक हैं। जद(यू) के मात्र 45 विधायक हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा के नेताओं का मानना है कि गठबंधन सरकार का नेतृत्व उसके हाथों में होना चाहिए। जद(यू) इसके लिए कतई तैयार नहीं बताई जा रही है। पिछले कुछ अर्से तक यह खबर चर्चा का केंद्र बनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है अथवा उन्हें राज्यसभा सदस्य बना केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर भाजपा राज्य में अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। इन चर्चाओं के जोर पकड़ने पर जद(यू) ने खुलकर ऐसी किसी भी संभावना को तो सिरे से नकारा ही सीधे-सीधे भाजपा पर हमला भी करना शुरू कर दिया है। सम्राट अशोक की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में जद(यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने साफ-साफ कहा कि नीतीश कुमार अपना टर्म पूरा करेंगे और जिन्हें भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना है उन्हें अभी इंतजार करना होगा। इतना ही नहीं बढ़ती महंगाई को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि केंद्र सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए।

कर्नाटक में बिखरती भाजपा

कर्नाटक में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रदेश में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बसवराज बोम्मई को राज्य की सत्ता संभाले अभी एक वर्ष भी नहीं पूरा हो पाया है, लेकिन प्रदेश भाजपा का एक धड़ा उन्हें हटाए जाने की मुहिम शुरू कर चुका है। हिजाब प्रकरण चलते कर्नाटक की छवि पिछले दिनों धूमिल हुई है जिसमें अब एक वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा पर लगे आरोपों ने इजाफा कर डाला है। बोम्मई सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा पर एक ठेकेदार ने प्रताड़ित करने, रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगा खुदकुशी कर डाली है। इस आत्महत्या ने राज्य में भारी राजनीतिक बवाल पैदा कर मुख्यमंत्री बोम्मई की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। किसी भी कीमत पर इस्तीफा न देने पर अड़े ईश्वरप्पा ने हालांकि भाजपा आलाकमान के निर्देश पर त्यागपत्र तो दे दिया है लेकिन उनके इस त्यागपत्र ने भाजपा समर्थक ओबीसी वोट बैंक को नाराज कर डाला है। ईश्वरप्पा ओबीसी नेता हैं और उनका इस वोट बैंक में खासा प्रभाव बताया जाता है।

दरार बरकरार

आजम और अखिलेश के रिश्तों में चल रही तल्खी किसी से छिपी नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव के सहयोगी दल रालोद के जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम खान के विधायक पुत्र से मुलाकात की थी, जिसके निहितार्थ अखिलेश की तरफ से नाराजगी दूर करने की कवायद के तौर पर निकाले जा रहे हैं। शिवपाल यादव अपना भाजपा प्रेम छिपा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंतनगर में हुए समारोह में योगी आदित्यनाथ के प्रति अपने मोह को सार्वजनिक करने में गुरेज नहीं किया। फरमाया कि योगी सरकार छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर अच्छा काम कर रही है। भाजपा में शामिल होने की अटकलों को भी खारिज नहीं किया। मुलायम सिंह यादव के रहते शिवपाल भाजपा में जाने से बच रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव शुरू से ही उन पर शक करते रहे हैं कि वे भाजपा का खेल खेल रहे हैं। अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी उन्होंने इसी वजह से बनाई थी।

मैडम का जलवा

महाकौशल के एक जिले में इन दिनों एक महिला निरीक्षक का जलवा इस कदर कायम है कि उनसे अन्य महिला निरीक्षक जलने लगी हैं। आलम यह है कि उक्त महिला निरीक्षक की चर्चा राजधानी की प्रशासनिक वीथिका में भी होती है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जिले में जब भी कोई नया पुलिस अधीक्षक आता है तो वह उक्त महिला निरीक्षक का कायल हो जाता है और उन्हें उनकी मंशानुसार कमाऊ थाने की कमान सौंप देता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में जब भी नए साहब की आमद होती है, मैडम सबसे पहले उन पर अपना घेरा डाल देती हैं। मैडम का हाव-भाव और स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि कठोर से कठोर दिल वाला अफसर भी उनके सामने पसीज जाता है। फिर मैडम उससे अपना हित साध लेती हैं। अब जिले में ऐसी स्थिति हो गई है कि मैडम से जलने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। सूत्र बताते हैं कि कुछ महिला निरीक्षक तो इस बात की पड़ताल में जुट गई हैं कि आखिरकार इस महिला निरीक्षक में ऐसा क्या है जिसके कारण उसको हर अफसर अधिक भाव दे रहा है। वहीं कुछ खबरचियों ने भी मैडम के चाल, चेहरा और चरित्र की कुंडली बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में इन दिनों मैडम अपने जिले में चर्चा का विषय बन गई हैं। वहीं मैडम को लेकर प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह की कहानियां गढ़ी और कही जा रही हैं।

अहाता प्रेमी मंत्रीजी

प्रदेश में एक तरफ एक पूर्व मुख्यमंत्री शराबबंदी और नशाखोरी के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें अहाते से प्रेम हो गया है। वैसे मंत्रीजी भी नशाखोरी के खिलाफ कई बार लंबा-चौड़ा भाषण पेल चुके हैं। लेकिन प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से ही मंत्रीजी को अहातों से प्रेम हो गया है। मंत्रीजी का प्रेम इतना बढ़ गया है कि विगत दिनों उन्होंने एक कारोबारी को बुलाकर अपना फरमान सुना दिया कि कुछ भी हो जाए शहर के सारे **अहाते** मुझे चाहिए। दरअसल, मंत्रीजी के पास युवाओं की एक ऐसी बड़ी फौज है, जो शहर के सारे गोरखधंधे करते हैं। अभी तक सट्टा, जुआ आदि में हाथ आजमाने वाले शागिर्दों को मंत्रीजी अहातों की जिम्मेदारी देना चाहते हैं।

इसलिए उन्होंने अपने शागिर्दों से कह दिया है कि वे अभी से तैयारी शुरू कर दें, उन्हें जल्द ही पैसा कमाने वाली मशीन यानी अहातों का काम मिल जाएगा। सूत्र बताते हैं कि शागिर्दों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए मंत्रीजी ने अपना फरमान सुना दिया है। अब देखना यह है कि मंत्रीजी को अहातों का काम मिलता है या नहीं। गौरतलब है कि मंत्रीजी युवा हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए वे ऐसे ही रास्ते निकालते हैं।

साहब की बलिहारी...

अभी हाल ही में प्रदेश की एक युवा प्रशासनिक दंपत्ति की गृहस्थी उजड़ने की कगार पर पहुंच गई है। इस दंपत्ति में पति आईएएस और पत्नी आईआरएस हैं। कभी एक-दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने वाली यह दंपत्ति अब एक-दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। प्रदेश प्रशासन में ऐसे कई दंपत्ति रहे हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं। वहीं कईयों के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवदूत बने हैं, जिन्होंने उनके घर को तबाह होने से बचा लिया है। उक्त आईएएस अधिकारी वर्तमान में अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं। बताया जाता है कि उन्होंने कई प्रशासनिक दंपत्ति का परिवार टूटने से बचाया है। ऐसी ही एक दंपत्ति हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सूत्रों का कहना है कि शादी के कुछ साल बाद ही इस दंपत्ति के बीच विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसे में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इनके लिए देवदूत बने और पति-पत्नी दोनों को समझाइश देकर एक किया। इनके अलावा प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में कई और दंपत्ति हैं जिनका संबंध टूट की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन उक्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने उनके परिवार को बिखरने से बचा लिया। यही नहीं ये साहब हमेशा नौकरशाहों की सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। हनीट्रैप में जब कुछ अफसरों का नाम आया तो साहब ने आगे आकर उनकी वकालत की और उन्हें इस भंवर से निकाला।

मंत्री की यारी को लगी नजर

अपनी दिलफेंक करतूतों के लिए ख्यात रहे एक मंत्रीजी को न जाने किसकी नजर लगी है कि इन दिनों उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आलम यह है कि मंत्रीजी के जितने करीबी हैं, वे उनसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक उनकी करीबी को सरकार ने उनकी पहुंच से दूर कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इससे मंत्रीजी काफी व्यथित हो उठे हैं। बताया जाता है कि जिसके वियोग में इन दिनों मंत्रीजी व्यथित हैं, वह नर्मदा किनारे स्थित एक जिले में रेंजर के पद पर पदस्थ थीं। अक्सर मंत्रीजी उक्त जिले में स्थित धार्मिक स्थल पर जाते थे और उक्त रेंजर से मिले बिना नहीं आते थे। यानी मंत्रीजी एक पंथ दो काज वाली कहावत को अपनाते हुए धर्म और कर्म दोनों कराते थे। लेकिन मंत्रीजी के इस मिलन को न जाने किसकी नजर लगी कि सरकार ने उक्त महिला रेंजर को डकैतों के लिए बदनाम रहे क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि मंत्रीजी ने उक्त रेंजर का ट्रांसफर रुकवाने के लिए खूब हाथ-पैर मारे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब देखना यह है कि मंत्रीजी की धार्मिक यात्रा जारी रहती है या फिर डकैतों के क्षेत्र में उनकी जंगली यात्रा।

किसकी लगेगी लॉटरी ?

विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली दरबार से इसके लिए सरकार के मुखिया को फ्रीहैंड दे दिया गया है। ऐसे में कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही मंत्री बनने वाले विधायकों की सक्रियता बढ़ गई है। महीनों तक पार्टी कार्यालय न झांकने वाले विधायक दस्तक देने लगे हैं। कुछ तो समीधा के भी चक्कर लगा रहे हैं। शायद इन विधायकों को यह मालूम नहीं है कि उनके कामों और सक्रियता की सर्वे रिपोर्ट पहले से ही सत्ता, संगठन और संघ के पास है। चुनावी वर्ष होने के कारण **सोशल इंजीनियरिंग** के आधार पर ही मंत्री की कुर्सी मिलेगी। इसलिए जिन विधायकों ने अच्छे काम किए हैं, वे थोड़े सुकून में हैं। उधर, उन मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है जो बार-बार की हिदायत के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस सुधार नहीं पाए हैं। अब देखना यह है कि किसकी कुर्सी जाती है और किसकी लॉटरी लगती है। वैसे चुनावी गणित को देखते हुए सरकार मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार करेगी। इसके लिए बड़े स्तर पर कवायद की जा रही है।

अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में हैं। सपा के कारण ही भाजपा सत्ता में आई क्योंकि सपा के कारण पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है।

● **मायावती**

धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी भी हूं। भारत में जिस तेजी से मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और उन पर बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगाकर अजान की जाती है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। योगी सरकार ने वह कर दिखाया जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही किया करते थे।

● **राज ठाकरे**

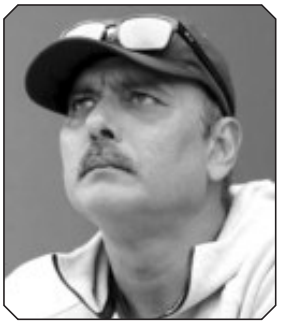

विराट कोहली इस समय खराब फॉर्म के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और उन पर थकान का असर दिख रहा है। इसलिए उन्हें आईपीएल से दूर हो जाना चाहिए। इससे वे दोबारा नई ऊर्जा के साथ भारतीय टीम में पदार्पण कर अपना कमाल दिखा सकते हैं।

● **रवि शास्त्री**

रूस तीसरे विश्व युद्ध की जिद पर अड़ा हुआ है। अपनी जिद के कारण वह यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा विश्व इसे दर्शक बनकर देख रहा है। अगर रूस को नहीं रोका गया तो कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है।

● **वोलोदिमीर जैलेंस्की**

मैं इन दिनों जो कुछ भी कर रही हूं, वह लोगों की डिमांड के अनुसार है। मैं भी एक घरेलू लड़की हूं लेकिन जिस फील्ड में हूं वहां कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। इन दिनों इंस्टाग्राम और ट्विटर का दौर चल रहा है। लोग इन दोनों इंटरनेट प्लेटफार्म पर मेरी तलाश करते रहते हैं। इसलिए मैं उनके इंटरटेनमेंट के लिए अजब-गजब कपड़े पहनती हूं। ये कपड़े भले ही बोल्ड होते हैं, लेकिन हर लड़की ऐसे कपड़े पहनना चाहती है और हर लड़का ऐसे कपड़े में लड़की को देखना चाहता है। फिर ऐसे में मैं कौनसी गलती कर रही हूं।

● **उर्फी जावेद**

वाक्युद्ध

हिंदी के नाम पर करोड़ों कमाने वाले हिंदी से परहेज क्यों कर रहे हैं, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और रहेगी। इसे हर किसी को स्वीकारना होगा। भारत का विकास तभी संभव है जब सब एक भाषा के बंधन में बंधे रहें। भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी जरूरी है।

● **अजय देवगन**

हिंदी कभी भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं रही है और न होगी। यह देश के हर नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह भारत की भाषाई विविधता को सम्मान दे। हर भाषा का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है, जिस पर लोग गर्व करते हैं। मैं एक कन्नड़ होने के नाते कन्नड़ भाषा पर गौरवान्वित महसूस करता हूं। यही सच्चाई है।

● **सिद्धारमैया**

'स्वच्छ इंदौर' में समाई नंबर-1 इंदौर की कहानी

2017 से इंदौर स्वच्छता में लगातार पहले पायदान पर कायम है। लेकिन इसके पीछे अफसरों, कर्मचारियों और इंदौरवासियों की सोच, समझ, समर्पण और सेवाभाव का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छता में इंदौर के नंबर-1 बनने की कहानी को 2001 बैच के आईएएस अधिकारी पी नरहरि ने अपनी किताब 'स्वच्छ इंदौर' में वर्णित किया है। इंदौर के पूर्व कलेक्टर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरहरि की यह किताब सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल को प्रकाशित हुई है। यह किताब इंदौर की स्वच्छता पर आधारित है।

यह किताब बताती है कि कैसे इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। इस किताब की प्रस्तावना देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सचिन तेंदुलकर को स्वच्छ भारत मिशन के पहले नौ में से एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह पुस्तक बताती है कि- वे कौन सी रणनीतियां हैं जिन्होंने इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने में सक्षम बनाया? इंदौर ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिस कारण विदेशी प्रतिनिधियों को भी इंदौर आकर इसकी सफलता की कहानी को प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ा। यह किताब उन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बारे में बताती है जिन्होंने विभिन्न माध्यमों, दक्षता तथा बौद्धिक कौशल के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर की सफलता की कहानी को लिखने में अपना सहयोग दिया। कैसे स्वच्छता का गाना हो हल्ला इंदौर की जनता के लिए एक एंथम बन गया जिसे सुनकर रोज इंदौरवासी उठते थे और इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ बनाने के लिए अपनी सहभागिता निभाते थे। इस गाने को ऋषिकेश पांडे ने लिखा था और इसे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान द्वारा गाया गया था। इसी क्रम में हैट्रिक लगाएंगे, चौका लगाएंगे, स्वच्छता का पंच आदि गानों द्वारा हमारे नागरिकों का प्रोत्साहन बना रहा।

स्वच्छता में सिरमौर इंदौर की सफलता को देश-विदेश में ख्याति प्राप्त हुई और इसे लगातार ट्विटर एवं अन्य माध्यमों से हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा सराहा गया। किताब 'स्वच्छ इंदौर' किसी भी शहर के नागरिकों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं, पत्रकारिता के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के लिए अपने शहरों को लिवेबल (रहने योग्य) बनाने के लिए एक संदर्भ बिंदु बन सकती है। यह राइट टू क्लीनलीनेस को बढ़ावा देगी तथा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। पी नरहरि ने किताब इंदौर के सफाई कर्मियों को समर्पित की है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और इंदौर के पूर्व कलेक्टर पी नरहरि द्वारा लिखी गई किताब में वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह, पूर्व ननि आयुक्त आशीष सिंह, वर्तमान ननि आयुक्त प्रतिभा पाल और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ पर आधारित विशेष चैप्टर हैं। पुस्तक के लेखक पी नरहरि बताते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगर निगम के तीनों पूर्व आयुक्त सहित पूर्व महापौर मालिनी गौड़ पर उनके योगदान पर आधारित विशेष चैप्टर इस किताब में है। साथ में समाज के अनेक नामचीन व्यक्तियों के साक्षात्कार और उनकी राय का उल्लेख भी किताब में है। अंग्रेजी में लिखी गई यह किताब प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शहर अब तक लगातार पांचवीं बार देशभर का सबसे साफ-सुथरे शहरों की लिस्ट में नंबर एक पर रहा है। और अब छठी बार के लिए भी जोरदार तैयारी है। इंदौर ने गीले तथा सूखे कचरे के प्रसंस्करण से शहरी निकाय की मोटी कमाई के टिकाऊ रास्ते खोजना और बड़े पैमाने पर गंदे पानी के उपचार से इसे दोबारा उपयोग किए जाने जैसे कदमों से इस मंजिल को पाया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के सलाहकार असद वारसी ने बताया कि शहर में औसतन 300 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) गंदा पानी उत्सर्जित होता है और अलग-अलग इलाकों में बने विशेष संयंत्रों में इसके उपचार के बाद 110 एमएलडी पानी सार्वजनिक बगीचों, खेतों और निर्माण गतिविधियों में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गंदे पानी के प्रबंधन के **सर्वश्रेष्ठ इंतजामों** के चलते ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर को देश के पहले 'वॉटर प्लस' शहर के खिताब से अगस्त में नवाजा गया था।

● **लोकेंद्र शर्मा**

कुशल प्रशासक, उत्कृष्ट लेखक और गीतकार

एक उल्लेखनीय अधिकारी के रूप में नरहरि व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभावित करने से नहीं चूकते। वह एक उत्कृष्ट लेखक और गीतकार भी हैं। उन्होंने अब तक 'स्वच्छ इंदौर' के अलावा पांच किताबें लिखी हैं जिनमें 'हू ओवन्स मह?', 'द ग्रेट टेल ऑफ हिंदूइज्म' और 'मेकिंग ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना' जैसी चर्चित पुस्तकें भी शामिल हैं। उनकी एक और किताब 'बेटियां' भी हाल ही में आई है और बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह किताब ग्वालियर में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उनके किए गए कामों और सक्रिय खोजी उपकरणों के कार्यों जैसे मुद्दों पर आधारित है। पुस्तकों के अलावा नरहरि ने कुछ लोकप्रिय अभियानों के गीत भी लिखे हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान दो गीत लिखे, जिसमें गायक शान द्वारा गाया गया 'जीना-जीना' भी शामिल है। इसके साथ ही 'जय हो', 'चौका', 'हो-हल्ला' उनके लिखे कुछ अन्य लोकप्रिय गीत हैं।

संघ और भाजपा की प्रयोग भूमि मप्र पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मिशन 2023 के लिए अभी से बिगुल फूंक दिया गया है। भाजपा की राजनीति के चाणक्य और देश के गृहमंत्री अमित शाह के जंबूरी मैदान से चुनावी शंखनाद के बाद संघ और केंद्रीय नेतृत्व ने मप्र की सत्ता और संगठन के साथ दिल्ली में बैठक कर मिशन 2023 की रणनीति पर मंथन किया। जिसमें प्रदेश संगठन और सरकार को निर्देश दिया कि हर वर्ग को साधने के लिए अब पूरी तरह सक्रिय हो जाएं।

भाजपा का मिशन 2023 तैयार

मप्र भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मिशन 2023 की प्लानिंग कर ली है। यह चुनाव उप्र मॉडल पर लड़े जाएंगे। मप्र भाजपा के कोर ग्रुप की केंद्रीय नेताओं के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें मंत्रिमंडल में विस्तार बेहद अहम है। कुछ मंत्रियों के पास अतिरिक्त विभाग हैं, जिन्हें वापस लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद भाजपा की दिल्ली में बैठक को विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी की रणनीति की नजर से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अमित शाह ने अपने दौरे में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी। प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 31 मंत्री हैं, जबकि प्रदेश में 35 मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के पास अतिरिक्त विभाग हैं। गोविंद सिंह राजपूत को ही लो तो उनके पास राजस्व और परिवहन जैसे दो बड़े विभाग है। वहीं, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग का कोई स्वतंत्र मंत्री नहीं है, बल्कि यह विभाग भी मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश शिवराज सिंह चौहान के पास है।

बैठक में सत्ता और संगठन के नेताओं ने आदिवासी और ओबीसी वोटरों को साधने को लेकर भी चर्चा की। नए सिरे से रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में चर्चा है कि सरकार जोबट में कांग्रेस से भाजपा में आई विधायक सुलोचना रावत और गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। सुलोचना ने जोबट विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीता था। प्रदेश के 22 प्रतिशत आदिवासी वोटरों को साधने के लिए जनजागरण अभियान चलाने पर भी सहमति बनी है।

दिल्ली की बैठक में तय हुआ कि मप्र में विधानसभा चुनाव 2023 को हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उप्र विधानसभा चुनावों की तर्ज पर मप्र में भी हिंदुत्व एक प्रमुख मुद्दा होगा। संघ के पदाधिकारियों ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने को कहा है, जिस तरह उप्र में निपटा गया है। उप्र की तरह मप्र में भी लाउडस्पीकर को लेकर नए नियम बनाने पर विचार किया गया है। बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने अधिकारियों की मनमानी का भी मुद्दा उठाया। इसे लेकर बेलगाम अधिकारियों को हटाने पर सहमति बनी है। भाजपा नेताओं की शिकायत पर बेलगाम अधिकारियों की सूची तैयार होगी। ऐसे में साफ है कि अब अफसरों पर सख्ती हो सकती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सानिध्य में आज मप्र भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है। सत्ता और संगठन के समन्वय से विपक्ष पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व और संघ दोनों इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि 2023 में भाजपा 230 में से 200 सीटें जीतकर इतिहास रचे। इसके लिए जहां संघ मैदानी तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं 22 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल का दौरा कर **सत्ता और संगठन** को जीत का मंत्र दिया। शाह के इस दौरे के बाद भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर दिख रहा है।

भाजपा नेतृत्व शिवराज सरकार से खुश!

अमित शाह ने भोपाल दौरे के दौरान जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों की तारीफ की। वहीं संगठन और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान अमित शाह ने संगठन को आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा। शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू कर रही है, वह काबिले तारीफ है। अमित शाह ने जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी आदिवासियों को समृद्ध बना रहे हैं। जब तक जनजातीय भाइयों-बहनों का कल्याण नहीं होता तब तक प्रदेश का कल्याण नहीं होता। पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों के मालिक जनजातीय भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, इसका 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है।

गौरतलब है कि अपनी एक दिनी यात्रा के दौरान जहां शाह ने मप्र को कई सौगातें दीं, वहीं आदिवासी समुदाय को कई सहूलियतें। इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में पार्टी के रणनीतिकारों के साथ करीब दो घंटे तक चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहे दलित, आदिवासियों में भाजपा की पैठ लगातार मजबूत करने के लिए शिवराज और वीडी शर्मा की सराहना की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारियों को अपनी साख के अनुसार काम करने का मंत्र दिया। उन्होंने सत्ता-संगठन के तालमेल की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि आज मप्र देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनकर उभरा है। इसे बरकरार रखना सत्ता और संगठन दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए इस पर और अधिक गौर करने की जरूरत है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों एवं प्रदेश के मंत्रियों से कहा कि कांग्रेस की स्थापना किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि एक अंग्रेज अफसर ने एक क्लब के रूप में की थी। जबकि भाजपा 50 के दशक से ही एक विचारधारा पर काम कर रही है। इतने साल बीतने के बाद भी हमारे मूल सिद्धांत, हमारी कार्यपद्धति और संस्कृति वही है, जिन्हें डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने रेखांकित किया है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारें गरीब कल्याण के विचार को जमीन पर उतारने का काम कर रही हैं और हमारा नेतृत्व बेदाग है, जिस पर हमें गर्व है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा और अन्य दलों के बीच के इस फर्क को समझना जरूरी है। शाह ने कहा कि देश के स्वतंत्र होते ही कांग्रेस सत्ता में बैठ गई थी। इस वजह से **कांग्रेस का आंदोलनों से नाता नहीं रहा।** दूसरी तरफ भाजपा राष्ट्र और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर किए गए आंदोलनों की आंच से तपकर निखरी है। सबसे पहले गोवा की स्वतंत्रता, गौहत्या पर प्रतिबंध के लिए आंदोलन किया। 1975 में हम आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन, तिरंगा यात्रा और ऐसे ही अनेक आंदोलन पार्टी ने किए हैं, जो हमारी विचारधारा से प्रेरित और उसी पर आधारित हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आंदोलनों का उद्देश्य पार्टी का विस्तार नहीं था बल्कि इन मुद्दों के प्रति जनता में चेतना लाना और कार्यकर्ताओं को इनसे जोड़ना ही पार्टी का लक्ष्य रहा है।

22 फीसदी वोट बैंक को साधा

अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर 22 फीसदी वोट बैंक को साध गए। शाह ने जंबूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन में आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। शाह ने वन समिति को लाभांश की राशि वितरित की। हरदा की वन समिति को 5 करोड़ दिए गए। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का शुभारंभ किया। प्रदेश के 26 जिलों के 827 गांव अब राजस्व ग्राम होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब सरकार बनी थी तब मोदी जी ने कहा था ये गरीबों की सरकार है। भाजपा की तमाम राज्य सरकार गरीबों के लिए काम कर रही हैं। वहीं 68 करोड़ रुपए तेंदूपत्ता संग्राहक को सीधे खाते में भेजा गया है। हर गरीब को घर देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है। हर घर में नल से जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। कोरोना की वैक्सीन देकर लोगों को सुरक्षित करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। आयुष्मान योजना ने हर बीमारी से लड़ने की शक्ति दी है। 19.7 फीसदी विकास दर हमने हासिल की है। सकल घरेलू उत्पाद में मप्र ने 200 फीसदी वृद्धि की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 250 रुपए प्रति 100 गड्डी के बजाय 300 रुपए प्रति 100 गड्डी दिए जाने की घोषणा भी की।

भाजपा कार्यालय में बैठक के दौरान शाह ने पार्टी नेताओं को उदाहरणों के साथ पार्टी की रीति, नीति और आगामी चुनाव की रणनीति समझाई। शाह ने कहा कि प्रत्येक पार्टी का चरित्र उसकी विचारधारा, कार्यक्रम और नेतृत्व से तय होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण हमारी विचारधारा के मूल हैं। हमारे जैसे नेता किसी पार्टी में नहीं हैं। यह बात हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेतृत्व पर कभी आरोप नहीं लगे और इसलिए हम एक अलग तरह की पार्टी हैं। शाह ने कहा कि हमारे नेता स्व. कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन की नींव रखी थी। उन्होंने मप्र में पार्टी संगठन द्वारा चलाई जा रही बूथ विस्तारक योजना की तारीफ करते हुए कहा कि स्व. ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष पर मप्र में पार्टी संगठन ने बूथ सशक्तिकरण का जो काम हाथ में लिया है वह पूरी तरह सफल रहा है। प्रदेश नेतृत्व ने कार्यक्रमों की जो रूपरेखा बनाई है वह भी बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि बूथ सशक्तिकरण के लिए यह जरूरी है कि पार्टी कार्यकर्ता बूथ पर विचारपूर्वक काम करें। किस बूथ पर हम अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में हैं और वहां मजबूती के लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन-से समीकरण उस बूथ को प्रभावित करते हैं, किस नेता या कार्यकर्ता को वहां भेजा जाना उचित होगा, इन सभी बातों पर विचार करते हुए योजना बनाएं। शाह ने कहा कि पार्टी को बूथ पर मजबूत बनाने के लिए हमें मजदूरी नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करना है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से आव्हान किया कि सभी 10-10 बूथों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें।

केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने की तैयारी में है। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने इस पर सुगबुगाहट शुरू कर दी है। शाह ने कहा कि हमारी पार्टी की केंद्र सरकार ने धारा 370, राम जन्मभूमि, तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जैसे अधिकांश मुद्दों को हल कर दिया है। कॉमन सिविल कोड जैसे जो कुछ बचे हैं, उन्हें भी आने वाले वर्षों में हल कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने मप्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कहा कि कॉमन सिविल कोड का प्रयोग उत्तराखंड में किया जाएगा। वहां, इसे अमल में लाने के बाद हालात का जायजा लेंगे और फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

सरकार की सोशल इंजीनियरिंग

लोकलुभावन योजनाओं को संचालित करने में मप्र भी पीछे नहीं है। किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित अन्य वर्गों को साधने के लिए बजट का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अनुदान में जा रहा है। 22 हजार करोड़ रुपए तो केवल बिजली अनुदान पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 6 हजार करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए हैं। डिफाल्टर किसानों को लगभग 85 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने की घोषणा की जा चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल देने के लिए 400 करोड़ रुपए सालाना व्यय किए जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी, तीर्थदर्शन, कन्यादान, सहरिया, भारिया और बैगा जनजातीय परिवारों को विशेष पोषण भत्ता सहित अन्य योजनाएं संचालित हैं। सरकार सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को साधने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। प्रदेश के पूर्व वित्तमंत्री राघवजी का कहना है कि लोकलुभावन योजनाएं वोट जरूर खींचती हैं पर एक संतुलन होना चाहिए। वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। आय और व्यय में अंतर बढ़ता जाएगा तो आगे चलकर इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सभी राज्य सरकारें इस मामले में जरूरत से ज्यादा आगे जा रही हैं। इससे बचना चाहिए।

गौरतलब है कि प्रदेश में 22 हजार करोड़ रुपए तो केवल बिजली अनुदान पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 6 हजार करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए हैं। डिफाल्टर किसानों को लगभग 85 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने की घोषणा की जा चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल देने के लिए 400 करोड़ रुपए सालाना व्यय किए जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी, तीर्थदर्शन, कन्यादान, सहरिया, भारिया और बैगा जनजातीय परिवारों को विशेष पोषण भत्ता सहित अन्य योजनाएं संचालित हैं।

सरकार सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्गों को साधने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। सबसे बड़ा खर्च बिजली पर दिए जाने वाले अनुदान है। 150 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से मात्र एक रुपए यूनिट की दर से बिल लिया जा रहा है, जबकि इसकी लागत कहीं अधिक होती है। 22 हजार करोड़ रुपए सालाना सरकार बिजली कंपनियों को अनुदान की राशि देती है। कोरोनाकाल में उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पाए तो समाधान योजना लागू करके सरचार्ज पूरा माफ कर दिया। इसके बाद भी वसूली नहीं हुई तो सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपए का बकाया बिल ही माफ कर दिया। किसानों को साधने के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। इसकी प्रतिपूर्ति सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान के रूप में करनी होती है। इस पर प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि, इस वर्ष आधार दर में कमी करने से यह राशि 600 करोड़ रुपए के आसपास रहने की संभावना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना लागू की गई है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रविधान रखा है। इसी तरह शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना में 922 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अब सरकार योजना का दूसरा चरण लागू करने जा रही है।

प्रदेश में कन्यादान निकाह योजना के तहत प्रत्येक विवाह के लिए राशि 51 से बढ़ाकर 55 हजार रुपए की गई। सरकार 540 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लाडली लक्ष्मी योजना पर इस वर्ष 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वृद्धावस्था और नि:शक्तजन पेंशन योजना में सामाजिक सुरक्षा के लिए इन पर कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। लघु उद्योगों को सब्सिडी में इस साल 3390 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जानी है। इसमें 2,890 करोड़ रुपए और निर्यात प्रोत्साहन योजना में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। निर्यात प्रोत्साहन योजना में बड़े उद्योगों को निर्यात प्रोत्साहन के लिए 610 करोड़ रुपए की रियायत दी जानी है। मुख्यमंत्री कर्ज समाधान योजना में 750 करोड़ रुपए और ब्याज अनुदान 600 करोड़ रुपए यानी कुल 1,350 करोड़ कर्ज का समाधान करना है। मुख्यमंत्री सोलरपंप अनुदान योजना में 370 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस तरह इन योजनाओं पर कुल खर्च 40,660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति की महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह विशेष पोषण भत्ता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में प्रति हितग्राही 55 हजार रुपए देने का प्रविधान रखा है। इसी तरह कई अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के खर्च को देखें तो यह कुल बजट का 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का लगभग 25 प्रतिशत होता है।

● **जय सिंह**

मुफ्त की योजनाएं ला सकती हैं आर्थिक तबाही

भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि मुफ्त की योजनाएं राज्यों में आर्थिक तबाही ला सकती हैं। इस रिपोर्ट में मप्र के आर्थिक आंकड़ों का मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योंकि बैंक के पास यहां के आंकड़े नहीं थे। हालांकि जिन मापदंडों के आधार पर राज्यों को वित्तीय तबाही आने की चेतावनी दी गई है, उन्हीं मापदंडों पर मप्र के आर्थिक हालात भी चिंताजनक हैं। राज्य सरकार को मिलने वाले कर राजस्व का बड़ा हिस्सा लोकलुभावनी योजनाओं पर खर्च हो रहा है। इसके चलते राज्य का वित्तीय घाटा 4.56 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। लोकलुभावनी योजनाओं पर सरकार 40,660 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो कमाई का 16.31 प्रतिशत हिस्सा है। इन योजनाओं में धन जुटाने के लिए सरकार के पास बाजार से उधारी उठाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा। जानकार कहते हैं कि सरकार को बाजार से ज्यादा कर्ज उठाने के बजाय कर्ज का बोझ कम करना चाहिए। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सोम्यकांति घोष के अनुसार लोकलुभावनी योजनाएं राज्यों की वित्तीय सेहत बिगाड़ रहीं हैं। ये आर्थिक तबाही ला सकती हैं। अगर सरकार ऐसी योजनाओं में सीमा से अधिक धन खर्च कर रही है और उसका वित्तीय घाटा 4.56 प्रतिशत है तो यह खतरे की घंटी है। हालांकि वित्त विभाग के एसीएस मनोज गोविल कहते हैं कि मप्र की वित्तीय सेहत बेहतर है। मौद्रिक घाटा केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही है। पिछले सालों में हमने पूंजीगत व्यय और निवेश बढ़ाया था। इसलिए हमें बाजार से 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज उठाने की अनुमति मिली थी। केंद्र से स्पेशल इंसेंटिव भी मिले थे।

अफसरों की कार्यप्रणाली अनकंट्रोल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए रात-दिन एक किए हुए हैं, लेकिन अफसर मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों का सही से क्रियान्वयन नहीं करा पा रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में अफसरशाही की कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग का कोई फुलप्रूफ सिस्टम नहीं है। इस कारण अफसरों की मनमानी से शिवराज के सुशासन का सपना चकनाचूर हो रहा है। इससे मुख्यमंत्री चिंतित हैं और उनकी चिंता गत दिनों प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सामने भी आई। इस दौरान मुख्यमंत्री के तेवर काफी तीखे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही स्थान पर पुलिस कर्मियों को ज्यादा समय तक नहीं रखा जाए। देखना है कि मुख्यमंत्री के यह निर्देश इच्छाधारी पुलिसकर्मियों पर लागू होते हैं या नहीं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून-व्यवस्था को लेकर अफसरों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कह दिया कि अफसरों के यहां जो पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी लगे हैं, उन्हें कम करें। उनका जनहित में उपयोग किया जाए, जो नियमानुसार पात्रता है बस उतने ही कर्मचारी अफसरों के यहां काम करें। मैंने मंत्रियों की सलामी बंद कराई है, तो अफसरों के घरों में गुलामी भी नहीं चलेगी। यही नहीं पुलिस विभाग में एक नई प्रथा बन गई है कि अधिकारी जब किसी दूसरे जिले जाता है तो कुछ पुलिस कर्मियों को अपने साथ लेकर जाता है। यही पुलिस कर्मी साहेब की आड़ में जिलों में मनमानी करते हैं। इसकी भी जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मप्र में दंगा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मप्र में मुझे किसी कीमत पर दंगा नहीं चाहिए- नॉट एट ऑल। शरारती तत्वों की जो लोग मदद करते हैं उन पर भी कार्रवाई करें। बीट सिस्टम को मजबूत करें। साधन-संसाधन, योग्य व्यक्ति, जो भी लगाने हो लगाएं, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने एडीजी इंटेलीजेंस से यह भी पूछा कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत करने का प्लान मुझे कब तक दे देंगे? आपकी ड्यूटी है, प्रदेश में शांति बनी रहे। दंगाइयों पर कार्रवाई जारी रखें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में चाक-चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को दंगा रोकने की ट्रेनिंग दें। भारत सरकार या अन्य राज्यों के ऐसे कोई मॉडल है तो उनका अध्ययन करें, नई तकनीकी का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि आप लोग भी सीसीटीवी सिस्टम को और मजबूत करें। लगातार सीसीटीवी के माध्यमों से भी असामाजिक तत्वों एवं अन्य गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने की जो बात आई है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। सीसीटीवी लग जाने से हम अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने हनुमान जयंती के कार्यक्रमों, जुलूस को अच्छे तरीके से हैंडल किया है, ये प्रशंसनीय है। आगे भी आने वाले त्यौहार, परशुराम जयंती और ईद निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए मैदान में डटे रहें। पब्लिक कनेक्ट बनाकर रखें। जिलों में दौरे जरूर करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी फील्ड पर नहीं जा रहे हैं, उनकी सूची बनाकर मुझे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दंगाई या माफिया ने शासन की जमीन पर कब्जा करके रखा है उसे मुक्त कराएं। जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। दबंगों से ली गई जमीन, गरीबों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की तारीफ भी की।

● **राकेश ग्रोवर**

'कमीशनखोरी के नेटवर्क को ध्वस्त करें'

मुख्यमंत्री ने कहा कि कमीशन के नेटवर्क को ध्वस्त करें। जो चल रहा है चलने दो, अगर ये सोचकर आप बैठे हैं तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप पवित्र संकल्प लेकर मैदान में काम करें। बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, ओएसडी योगेश चौधरी समेत पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मप्र में दंगा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मप्र में मुझे किसी कीमत पर दंगा नहीं चाहिए-नॉट एट ऑल। वास्तव में यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति चुस्त-दुरूस्त करना है तो नेता, पुलिस माफिया का गठबंधन तोड़ना होगा। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के मन में फैली इस धारण को भी खत्म करना होगा कि हम जहां व जैसा चाहेंगे वैसी ही नौकरी करेंगे। लंबे समय तक एक स्थान में पदस्थ पुलिसकर्मी नौकरी नहीं हर गोरखधंधे में पार्टनर हो जाते हैं। अवैध रेत उत्खनन, अवैध शराब व ड्रग माफियाओं से पुलिस के इतने गहरे संबंध हो जाते हैं कि कोई कार्रवाई ही नहीं होती। हां यदि पुलिस अफसरों को मनमाफिक सुविधाएं नहीं मिलती तो कार्रवाई जरूर शुरू हो जाती है। जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आईना दिखाया। साथ ही यह भी कहा कि अफसरों को फील्ड में जाना होगा और एक स्थान पर लंबे समय तक किसी को पदस्थ नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन तभी होगा, जब डीजीपी को पदस्थापना और कार्रवाई में फ्री हैंड दिया जाए। कहा जरूर जाता है कि अधिकारियों को फ्री हैंड है, लेकिन क्या वास्तव में कोई एसपी क्षेत्रीय विधायक या सत्ताधारी नेता की अनुमति के बिना किसी टीआई या अन्य पुलिसकर्मी की पदस्थापना कर सकता है। कई ऐसे टीआई व डीएसपी हैं जो क्षेत्रीय विधायकों व नेताओं के इतने करीब हो जाते हैं कि एसपी की पदस्थापना कराने व हटवाने की बातें खुलेआम करते हैं। इसलिए सरकार को पुलिस प्रशासन को राजनीति से मुक्त रखना होगा।

'लुटेरे' अस्पतालों पर चाबुक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के निजी अस्पताल मरीजों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। 2018 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 67 अस्पतालों ने शासन से तय पैकेज के अलावा मरीजों से भी 50 लाख रुपए से ज्यादा वसूल लिए। कुछ अस्पतालों ने तो आईसीयू में भर्ती मरीजों से 3 लाख रुपए से भी ज्यादा ले लिया। मरीजों की शिकायत, फीडबैक से मिली जानकारी और ऑडिट के बाद इसका पर्दाफाश हुआ। इस पर आयुष्मान भारत मिशन मप्र ने इन अस्पतालों से दंड के साथ वसूली की। अस्पतालों ने मरीजों से जितनी राशि ली थी, दंड के साथ इससे तीन गुना ज्यादा राशि इन अस्पतालों से ली गई। बड़ी बात यह है कि इन 67 अस्पतालों में से 29 भोपाल के हैं। इंदौर के 4, ग्वालियर के 9 और जबलपुर के 10 अस्पताल शामिल हैं।

बता दें कि इस योजना में चिन्हित परिवार के लोगों का हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क किया जाता है। लेकिन अस्पताल ऐसे मरीजों को भर्ती करने के बाद तरह-तरह के बहाने करते हैं। मरीजों को कहते हैं कि उन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, जो योजना के पैकेज में शामिल नहीं है। कुछ अस्पताल कहते हैं कि शासन से पैसा देरी से आता है, इस कारण ज्यादा राशि देनी होगी। बता दें कि इस योजना में प्रदेश के करीब 1 करोड़ 40 लाख परिवार शामिल हैं। प्रदेश में जिन अस्पतालों ने आयुष्मान धारियों से पैसा वसूला हैं उनमें ग्वालियर के एसएसआईएमएस, कैलाश सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, आरजेएन अपोलो स्पेट्रा हॉस्पिटल, बीआईएमआर हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, माहेश्वरी नर्सिंग होम, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, शांता नर्सिंग होम, रीवा के सिंगरौली हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर सिंगरौली, वंदना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रीवा, एमपी बिरला हॉस्पिटल सतना, अमृता हॉस्पिटल, इंदौर के मेडिस्क्वॉर, ऑल इज वैल मल्टी स्पेशिलियटी हॉस्पिटल, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल प्रालि, एसएनजी हॉस्पिटल, सागर के सागरश्री हॉस्पिटल एंड रिसर्च इस्टीट्यूट प्रालि, मिशन हॉस्पिटल दमोह, सिटी हॉस्पिटल दमोह, उज्जैन के प्राइम हॉस्पिटल देवास, अजय हॉस्पिटल, गुप्ता नर्सिंग होम, उज्जैन चैरिटेबल, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पाटीदार सेंटर एंड मल्टीस्पेशिलियटी मंदसौर, गीता हॉस्पिटल, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज एंड सीआर गार्डी हॉस्पिटल, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर, सेठ मुन्नुलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल, जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, धर्मलोक हॉस्पिटल प्रालि, शैल्बी हॉस्पिटल, एमजीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कटनी, गैलेक्सी सुपर स्पेशिलियटी हॉस्पिटल, लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल, मोहनलाल हरगोविंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल आदि शामिल हैं।

वहीं राजधानी भोपाल के अस्पताल भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। प्रदेश में सबसे अधिक भोपाल के अस्पताल हैं, जिन्होंने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में मरीजों से वसूली की है। इनमें जेके हॉस्पिटल एंड एलएन हॉस्पिटल, एबीएम हॉस्पिटल, तृप्ति मल्टी स्पेशिलियटी एंड ट्रॉमा सेंटर, श्री सांई हॉस्पिटल, बंसल हॉस्पिटल, एके हॉस्पिटल, उवंतू हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल, गुरु आशीष हॉस्पिटल, नर्मदा ट्रॉमा सेंटर, नागपुर हॉस्पिटल, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्रालि, मिराकल्स हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, मल्टी केयर हॉस्पिटल, निरायम हॉस्पिटल, पालीवार हॉस्पिटल, आराधना मेटरनिटी एंड किडनी हॉस्पिटल, रोशन हॉस्पिटल, एलबीएस हॉस्पिटल, अरेरा ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, चिरायु हॉस्पिटल, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान हॉस्पिटल, मोना हॉस्पिटल, अक्षय हॉस्पिटल आदि शामिल हैं।

मरीजों की शिकायत पर आयुष्मान भारत ने प्रदेश के नामी अस्पतालों से इलाज के नाम पर ली गई राशि को वापस कराया। साथ ही जुर्माना भी ठोका। भोपाल के चिरायु अस्पताल से चार मरीजों को 8 लाख 79 हजार वापस कराए। अपेक्स अस्पताल भोपाल से 3.68 लाख, आरजेएन अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर से 2.33 लाख, ग्वालियर के ही एसएसआईएमएस से 2.80 लाख, सागर के सागरश्री अस्पताल से 4 मरीजों के 6 लाख, उज्जैन के अमलताल हॉस्पिटल से 1.32 लाख, भोपाल के पीपुल्स हॉस्पिटल से 2.10 लाख, एबीएम हॉस्पिटल से 3.52 लाख, मिराकल हॉस्पिटल से 2.31 लाख, निरायम हॉस्पिटल से 1.99 लाख, एबीएस हॉस्पिटल से 2.73 लाख, अपेक्स हॉस्पिटल 3.68 लाख, महावीर मेडिकल कॉलेज से 2 लाख, बंसल हॉस्पिटल से मरीज मुनीष रघुवंशी को 24,473 रुपए वापस कराए जा चुके हैं।

● **विकास दुबे**

अस्पतालों से खत्म क्यों नहीं किया जा रहा अनुबंध?

इन अस्पतालों पर अर्थदंड तो लगा दिया गया है, लेकिन इस तरह से अवैध वसूली के बाद भी इनका अनुबंध समाप्त नहीं किया जा रहा है। इस कारण अस्पताल संचालकों को डर नहीं है। इस संबंध में आयुष्मान भारत योजना के अधिकारियों का तर्क है कि अस्पतालों से अनुबंध खत्म करने से मरीजों को नुकसान होगा। इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ जाएंगे। हां, इलाज में गड़बड़ी करने पर जरूर कुछ अस्पतालों का अनुबंध खत्म किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत मप्र अनुराग चौधरी का कहना है कि 67 अस्पतालों ने मरीजों से ज्यादा राशि ली थी। इन पर तीन गुना जुर्माना लगाकर 1 करोड़ 57 लाख रुपए वसूले गए हैं। मरीज से जितनी अतिरिक्त राशि की वसूली की गई थी, वह उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। शिकायतों के निराकरण में मप्र देश में पहले नंबर पर है।

गुटों में बंटी कांग्रेस मिशन 2023 के लिए धीरे-धीरे एकजुट हो रही है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे दम-खम के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए लामबंद हो रही है। इससे कांग्रेस में नई उमंग देखी जा रही है।

कांग्रेस में नई जमावट

मप्र में भले ही दो साल पहले असमय कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा हो, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के दिग्गज नेताओं का कद पार्टी हाईकमान के सामने कम नहीं हुआ है। हाल ही के कुछ दिनों को देखें तो मप्र के कांग्रेस नेताओं की दस जनपथ में पूछताछ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसमें एक नाम और अब अरुण यादव का जुड़ गया है। दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस के चिंतन शिविर के लिए गठित की गईं कमेटियों में इन दोनों ही नेताओं को जगह दी गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दिल्ली में सोनिया गांधी से मेल-मुलाकात का दौर लगातार जारी है। वे एक हफ्ते में अब तक चार बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इन दोनों ही नेताओं की चल रही मुलाकातों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी वजह है उनका राजनीतिक अनुभव और पार्टी के हिसाब से सियासी समझ और प्रभाव। दरअसल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उन नेताओं में शामिल हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं। इन दोनों नेताओं की यह मुलाकातें ऐसे समय हो रही हैं, जब पार्टी में नई रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है।

माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उधर उनकी इन मुलाकातों को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है की मप्र के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दी गई है। इस रिपोर्ट पर भी इन दोनों नेताओं के साथ सोनिया गांधी द्वारा चर्चा की जा रही है।

उधर, कांग्रेस द्वारा अगले माह तीन दिन के लगाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर के लिए सोनिया गांधी द्वारा अलग-अलग कोआर्डिनेशन पैनलों का व समितियों का गठन किया गया है। इसमें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विषय के पैनल में जहां दिग्विजय सिंह को रखा गया है, वहीं किसान व खेती के मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति में अरुण यादव को शामिल किया गया है। इस समिति में उनके अलावा आठ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा कमलनाथ प्रदेश के ऐसे नेता हैं, जो बीते लंबे समय से अघोषित तौर पर सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में माने जा रहे हैं। बताया जाता है कि सोनिया के साथ कमलनाथ की बैठक करीब एक घंटे तक चली। जिसमें प्रदेश के राजनीतिक मामलों सहित संगठन के विषयों, रणनीति और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान प्रशांत किशोर की रिपोर्ट पर भी बात की गई है। दरअसल पार्टी हाईकमान का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन उसके पहले मप्र सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता भी कांग्रेस हाईकमान को बनी हुई है। यह चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले होना है।

इसको लेकर कई बदलावों की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि मप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही उतरेगी यह पहले ही तय हो चुका है। इसको लेकर पहले ही प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं में सहमति बन चुकी है। चुनाव से पहले कमलनाथ भी सभी दिग्गज नेताओं के बीच हर मामले में सहमति बनाने के लिए लगतार बैठकें कर रहे हैं। उनके द्वारा राजनीतिक फैसलों के लिए एक समिति भी बनाई जा चुकी है। अब इस समिति की बैठक अगले माह प्रस्तावित है। इस समिति में कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया शामिल हैं। दरअसल इस कवायद के पीछे गुटों में बंटी प्रदेश कांग्रेस में नेताओं के बीच एकजुटता दिखाना भी है। पार्टी में तमाम गुटों के नेताओं का अपने-अपने क्षेत्र में प्रभाव है। यही वजह है कि पार्टी का प्रयास है कि सभी नेता एक साथ बैठें, निर्णय सामूहिक हों। कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा कि सभी साथ हैं।

● **अरविंद नारद**

डॉ. गोविंद सिंह को सौंपी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी

कांग्रेस आलाकमान ने नई रणनीति के तहत डॉ. गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे पार्टी ने ग्वालियर-चंबल संभाग में अपनी किले को मजबूत करने की कवायद की है। साथ ही भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए यह बदलाव किया गया है। गोविंद सिंह सात बार से विधायक हैं और कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। कमलनाथ की कोशिश है कि प्रदेश के सभी कद्दावर नेताओं को एकजुट करने के लिए उन्हें कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। वैसे गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह का भी करीबी माना जाता है। इसलिए उनकी नियुक्ति राज्य की राजनीति में कमलनाथ के लिए भी कई समीकरण बदल सकती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास का जो रोडमैप तैयार किया है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है। गत दिनों मुख्यमंत्री नई दिल्ली में जब प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मप्र के विकास में भरपूर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मप्र के विकास को बूस्टर डोज

वर्ष 2018 के उतरार्द्ध से लेकर मार्च 2020 तक की अवधि को छोड़ दिया जाए तो मप्र पिछले 17 साल से विकास के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। उन्होंने अपनी जिद और जुनून से आज प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ला खड़ा किया है। अपनी चौथी पारी में तो शिवराज की कुछ कर गुजरने की ललक इस कदर देखी जा रही है कि वे एक ही दिन में प्रदेश का एक-एक कोना छान लेते हैं। जिसका परिणाम है कि आज मप्र देश के लिए विकास का मॉडल बना हुआ है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी समय-समय पर मप्र के विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं।

23 अप्रैल को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मप्र के विकास पर मंथन किया। इस दौरान शिवराज ने मप्र के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि हम मप्र में रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम दो लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन दिया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से गेहूं के निर्यात को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में इस बार हम 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और निर्यात करेंगे।

गौरतलब है कि मप्र अपनी विकास योजनाओं के साथ ही केंद्र की योजनाओं पर अमल में देश में अग्रणी है। यही कारण है कि देर से ही सही मप्र अपने गठन के समय बूझी गई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले डेढ़ दशक का अरसा इस बात का गवाह रहा है, कि मप्र विकास के पथ पर अब आगे ही आगे है। सुविचारित सोच, सुचिंतित नीतियों, फैसलों और प्रेरणादायी नेतृत्व ने सरकार की नीति और नीयत के फर्क को मिटाकर सच्चे अर्थों में प्रदेश के विकास और लोगों की बेहतरी के कामों की तस्वीर में नए रंग भर दिए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल अपनी बल्कि भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। मप्र की इन्हीं उपलब्धियों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र को भारत की अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग फोर्स बनने की पूरी क्षमता वाला बताया है।

गौरतलब है स्वामित्व योजना में आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को भूमि-स्वामी हक प्रदान करने में मप्र अग्रणी है। इसी साल 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 19 जिलों के 3 हजार ग्रामों के 1 लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए। प्रदेश में अब तक 3 हजार 800 से अधिक गांवों में 2 लाख 71 हजार अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 64.1 स्कोर के साथ मप्र ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड जनरेशन में मप्र पूरे देश में प्रथम है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मप्र देश में प्रथम स्थान पर है। जल जीवन मिशन एक करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार वाले राज्यों में मिशन की इस साल की भौतिक प्रगति में मप्र का देश में चौथा स्थान है। कृषि अधोसंरचना निधि के उपयोग में मप्र देश में पहले स्थान पर है। अब तक 805 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि प्रदेश में हितग्राहियों को कृषि अधोसंरचा के विकास के लिए प्रदाय जारी कर दी गई है। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की

स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे

मप्र में स्टार्टअप बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी स्टार्टअप की पॉलिसी बनाई है। मुख्यमंत्री इस पॉलिसी को प्रधानमंत्री के हाथों लॉन्च करना चाहते हैं। मप्र में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन की जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी। स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित और प्रभावी बनाने के लिए एमपी स्टार्ट-अप नीति और कार्यान्वयन योजना-2022 तैयार की गई है। स्टार्ट-अप्स और इनक्यूबेटर्स को निवेश सहायता, आयोजन सहायता, उन्नयन सहायता और लीज रेन्टल सहायता आदि का प्रावधान किया गया है। स्कूल और महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का प्रावधान भी नीति में है। प्रदेश में 1,900 से अधिक स्टार्टअप इंडिया से अधिमान्य स्टार्ट-अप अब तक स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश में न्यूनतम 1 स्टार्ट-अप को प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रदेश में 2022 में न्यूनतम 2 स्टार्ट-अप को यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप का दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

छलांग लगाकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत पथ-विक्रेताओं को शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण देकर मप्र देश में अव्वल है। जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोजगार दिलाकर मप्र देश में अग्रणी रहा है। सशक्तिकरण के तहत स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण स्वीकृत कराकर देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की लंबाई की उपलब्धि में मप्र पिछले 3 वर्षों से देश के उच्चतम 7 राज्यों की सूची में शामिल है। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता में भी प्रदेश, पिछले 3 वर्षों से देश में प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर प्रदेश, देश में दूसरे और आवासों की संख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर है। ट्रान्सजेंडरों को पहचान-पत्र जारी करने वाला मप्र देश का पहला राज्य है। दिव्यांगजन पहचान-पत्र बनाकर जारी कर देश में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा में मप्र अग्रणी है। कौशल विकास के तहत आईटीआई ग्रेडिंग में मप्र पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश को देश में चौथी रैंकिंग प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही रोजगार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने पर सरकार का फोकस है। प्रदेश में उद्यमी युवाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2022 से हर महीने प्रदेशभर में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अब तक (12 जनवरी, 25 फरवरी, 30 मार्च) कुल 3 रोजगार दिवस कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इन रोजगार दिवसों में 13.6 लाख से अधिक लोगों को लगभग 7.7 हजार करोड़ की राशि का ऋण वितरण किया गया है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 5 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 1815 युवाओं को 112 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। रोजगार दिवस में प्रधानमंत्री मुद्रा

योजना, प्रधानमंत्री निधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, मुख्यमंत्री उद्भव क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं से युवा लाभांवित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि, कम से कम दो लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन दिया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की नीतियों का असर अब पूरी तरह दिखने लगा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास, योजनाओं-परियोजनाओं के क्रियान्वयन और रोजगार सम्मेलनों के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। इसका असर यह पड़ा है कि मप्र में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। मप्र की बेरोजगारी दर 1.4 प्रतिशत हो गई है। देश में इससे कम केवल छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में सरकार ने इस साल अब तक 13,65,000 युवाओं को रोजगार दिया है। जनवरी में 5,26,000 व 16 फरवरी को 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला है। 30 मार्च को 3,35,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की स्थिति देश में सबसे बेहतर बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही। वहीं मप्र दूसरे स्थान पर है। मप्र की बेरोजगारी दर 1.4 प्रतिशत हो गई है। मप्र सरकार का दावा है कि नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर राज्य में उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 3 अप्रैल 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही।

● **कुमार विनोद**

20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और होगा एक्सपोर्ट

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि 1000 रुपए में स्टेट लेवल सिंगल गेहूं एक्सपोटर्स का लाइसेंस 2022-23 में गेहूं निर्यातकों को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना लागू की गई है। गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने निर्यातकों को मात्र 1000 रुपए में प्रदेश स्तरीय एकल लाइसेंस मिलेगा। अब तक 358 निर्यातकों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के निर्यात में 8-10 गुना वृद्धि हुई है। इस साल प्रदेश से गुजरात, आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र की बंदरगाहों से लगे रेलवे रेक पॉइंट्स पर भेजी जा रही गेहूं की रेक संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले 1 माह में प्रदेश से 87 रेक के माध्यम से लगभग 2.4 लाख टन गेहूं बंदरगाहों तक भेजा जा चुका है। कृषि निर्यात प्रकोष्ठ में निर्यातकों की सहायता हेतु एक्सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर 18002333474 जारी किया। 11 अप्रैल 2022 को इजिप्ट के प्रतिनिधिमंडल के इंदौर दौरे के बाद कृषि निर्यात प्रकोष्ठ के अधिकारी लगातार इजिप्ट के आयातकों के संपर्क में हैं। केंद्र और मप्र सरकार मिलकर इजिप्ट को गेहूं निर्यात करने के लिए कांडला और मुंदरा पोर्ट से गेहूं के जहाजों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में कुल पात्र परिवार 1 करोड़ 17 लाख हैं। कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ हैं। प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रदेशव्यापी अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है।

नाफरमान अफसर जाएंगे लूपलाइन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में हैं। वे ताबड़तोड़ निर्णय कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने प्रदेश के नाफरमान और नाकारा अफसरों पर गाज गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को निर्देश दिया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीएस ने नाफरमान और नाकारा अफसरों की कुंडली बनवानी शुरू कर दी है। यह इस बात का संकेत है कि आगामी दिनों में प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश में नाफरमान अफसरों पर चर्चा हुई थी। संघ के राष्ट्रीय सह सर कार्यवाह अरुण कुमार व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कोर कमेटी की बैठक में तीन चार अधिकारियों के नाम का भी उल्लेख किया और कहा कि ये इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं कि मंत्रियों तक के फोन नहीं उठाते। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को निवास पर बुलाकर लंबी चर्चा की। बताया जाता है कि नाफरमान अफसरों पर जल्द ही लगाम लगाई जाएगी और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि विभाग का मुखिया मंत्री होता है, उनकी बात सुने और समन्वय बनाकर कार्य करें।

जानकारी के अनुसार वर्तमान में कई विभागों में हालात यह है कि प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष मंत्रियों के पत्रों का जवाब तक नहीं देते। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के बीच चल रहे विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अति विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर नाफरमान अफसरों को इधर-उधर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दर्जन भर मंत्री अपने प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्षों की कार्यप्रणाली से परेशान हैं। परेशानी का सबसे बड़ा कारण मंत्रियों द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा जवाब भी न देना है। सभी विभागों में तबादलों पर प्रतिबंध है, लेकिन एक विभागाध्यक्ष ने मनमाने तरीके से अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसकी जानकारी मंत्री को मिली तो उन्होंने तबादले निरस्त करने और प्रतिबंध के समय तबादले बिना समन्वय के न करने के निर्देश दिए, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। मंत्री ने इसकी जानकारी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को भी दी है।

कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी उनके विभाग के अफसर तनिक भी नहीं सुन रहे हैं। बताया जाता है कि आदिम जाति व अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह की विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल और आयुक्त जनजातीय विकास संजीव कुमार सिंह से लंबे समय से विवाद चल रहा है। मंत्री का कहना है कि दोनों उनकी बात को तवज्जो नहीं देते। वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी और आयुक्त राजीव दुबे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कई बार तो प्रमुख सचिव फोन भी नहीं उठाती। किसान कल्याण व कृषि विकास मंत्री कमल पटेल के एसीएस अजीत केसरी व संचालक कृषि प्रीति मैथिल नायक, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह की प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई, नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की आयुक्त नगरीय विकास निकुंज श्रीवास्तव, खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रमुख सचिव संजय दुबे, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव तथा आयुक्त नरेगा सूफिया वली से पटरी नहीं बैठ रही है। मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल न होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। बताया जाता है कि विवाद का कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जिन पर मंत्रियों व अफसरों में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसी कारण स्थिति और खराब है। इसके पूर्व कभी इतनी विवाद की स्थिति नहीं बनी।

● **सुनील सिंह**

प्रदेश में 15 मई से तबादलों पर से हटेगा प्रतिबंध

प्रदेश में जल्द ही तबादलों पर से प्रतिबंध हटेंगे। प्रतिबंध हटाने से पहले सरकार कैबिनेट में नहीं तबादला नीति लाने वाली है। इस नीति में कई ऐसे प्रावधान हैं जो तबादलों को पारदर्शी बनाएंगे। जानकारी के अनुसार तबादला नीति में सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति करने ट्रांसफर होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पदों की पूर्ति होने के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पदों को भरा जाएगा। मंत्रालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में संभवतः 15 मई से 15 जून के बीच कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। वर्ष 2022-23 की तबादला नीति अगली कैबिनेट में आने की संभावना है। जीएडी द्वारा तैयार किए गए मसौदे के तहत बड़े विभागों में 5 फीसदी ही तबादले किए जा सकेंगे। सबसे पहले गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही में दोषी कर्मचारियों को हटाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई तबादला नीति में शासकीय सेवक के खिलाफ अत्यंत गंभीर शिकायत, अनियमितता और गंभीर लापरवाही में दोषी पाए जाने पर उन्हें हटाया जाएगा। इनमें कुछ जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, डीएसपी, एसडीएम आदि के नाम शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो इस मामले में मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं कि लापरवाही करने वालों को बख्शें नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले दिनों दिल्ली में बुलाई मप्र भाजपा कोर कमेटी की बैठक में कुछ अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी दर्ज कराई थीं। ऐसे अफसरों को भी सरकार फील्ड से हटाकर मुख्यालय अथवा लूपलाइन में भेज सकती हैं। इनमें कुछ बड़े अफसरों के नाम भी शामिल बताए जाते हैं।

महंगी हुई कपास

कपास किसानों पर बड़ा संकट

आने वाले कुछ वर्षों में भारत सहित दुनियाभर में हो रही 70 फीसदी कपास की खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ सकता है। हाल ही में प्रकाशित कॉटन 2040 इनिशिएटिव की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपास की खेती को बाढ़, सूखा, तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनियाभर में हो रही खेती पर बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, खासकर उन देशों में जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों पर कीटों का प्रकोप भी बढ़ रहा है या आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कपास की खेती पर कभी बाढ़ तो कभी सूखे की मार पड़ी है। कॉटन 2040 इनिशिएटिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती गरमी की वजह से ब्राजील, उप-सहारा अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फसलों पर बीमारियों का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

यह विडम्बना ही है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज किसान तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर कपास की खेती करने वाले किसानों की बात करें, तो इस महत्वपूर्ण खेती से उनका मन ऊब रहा है। इसकी वजह साफ है- कपास की उपज में लागत ज्यादा आ रही है और आमदनी कम हो रही है। कपास की पैदावार करने वाले किसानों का कहना है कि कपास में पाला पड़ने से लेकर कीड़ा लगने तक सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज तक नहीं मिलता है। ऊपर से महंगाई इतनी कि खेती की लागत भी नहीं निकलती। ऐसे में बड़ी संख्या में कपास की खेती करने वाले किसान कपास की वैकल्पिक खेती करने लगे हैं।

कपास की खेती से जुड़े और उसके जानकार डॉ. अमित कुमार कहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मप्र सहित कई राज्यों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती रही है। लेकिन कोरोनाकाल से लेकर कृषि कानूनों को लेकर चले किसान आंदोलन और यूक्रेन-रूस के युद्ध के चलते खेती पर विपरीत असर पड़ा है। इससे कपास की उपज से लेकर कारोबार तक प्रभावित हुआ है। सरकार की ओर से अनदेखी और कोरोना महामारी से कपास की बिकवाली सही तरीके से नहीं हो पाई है। हाल यह है कि कपास में तो किसानों की लागत तक नहीं निकल पाई है। ऐसी स्थिति में किसान कपास की जगह वैकल्पिक खेती करने लगे हैं। डॉ. अमित कुमार का कहना है कि आने वाले दिनों में कपास (रुई) की कमी बाजार में देखने को मिलेगी। इससे कॉटन (सूत) की कमी होगी, जिसका असर कारोबार पर देखने को मिल सकता है। यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते भारत में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारतीय किसानों पर पड़ा है। ऐसे में सरकार किसानों को महंगे उर्वरकों की खरीद से बचाने के लिए सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं दे।

रायपुर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक गजेंद्र कुमार का कहना है कि कपास की खेती करने वालों को इस फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवा का उपयोग करना होता है, जो कि अब बेहद महंगी है। यह दवा इतनी महंगी है कि मध्यमवर्गीय किसान इसे खरीद नहीं पाता है। इसके अलावा खाद, पानी, बीज सब कुछ महंगा है। ऐसे में कपास की फसल को कीड़ों से नष्ट कराने से तो अच्छा है कि दूसरी कोई खेती की जाए। इन्हीं तमाम दिक्कतों के चलते कपास के किसानों ने वैकल्पिक खेती करनी शुरू कर दी है। कपास का भाव बढ़ने का कारण भी उसके उत्पादन में आई कमी है। पिछले दो-तीन साल में भारत में कपास का उत्पादन काफी कम हुआ है, जो अब और कम हो रहा है।

पंजाब के व्यापारी नीरज कुमार अरोड़ा ने बताया कि पंजाब के मालवा को कपास की खेती के नाम से ही जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के किसानों को गत दो वर्षों से कई समस्याओं से जूझना पड़ा है। एक तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में लगे समय और दूसरा उनकी कपास की फसल पर गुलाबी खतरा यानी गुलाबी सूड़ी (पिंक बॉलवर्म) ने इस फसल को चौपट किया है। इससे फसल कमजोर भी हुई है। हालांकि इस बार गत वर्षों की अपेक्षा कपास के काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं। लेकिन लागत के अनुपात में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा है।

बताते चलें कि कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। महाराष्ट्र और गुजरात में एक समय में कपास की खेती में आगे रहने की होड़-सी लगी रहती थी। लेकिन आज दोनों ही राज्यों में कपास का उत्पादन कम हो रहा है। यहां की कपास योग्य काली और देगुड़ मिट्टी वाली जमीन पर देश के बड़े पूंजीपतियों की नजर है। इसकी वजह यह है कि कपास की मांग दुनियाभर में बढ़ रही है, जिसके चलते यह हर साल महंगी हो जाती है। यही वजह है कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है। पूंजीपति पूरी तरह इस फसल पर अपना कब्जा चाहते हैं, ताकि वे इसकी पैदावार से लेकर कपड़ा बेचने तक के कारोबार पर कब्जा करके मोटा पैसा कमा सकें।

इस बारे में किसान नेता चौधरी बीरेंद्र कुमार का कहना है कि कई बार फसल प्राकृतिक कारणों से चौपट होती है, तो कई बार दलालों की वजह से। दरअसल खेती को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है, ताकि किसानों को घाटा हो और दलालों की दलाली चलती रहे। मौजूदा समय में आए दिन कपास के दाम बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि छोटे किसान कपास की फसल संसाधनों के अभाव नहीं कर पा रहे हैं। हाल यह है कि बड़े किसान तक कपास की फसल की लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध और कोरोना महामारी के पीछे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार छिपा हुआ है। इसलिए कपास और सूत से लेकर कपड़ों तक का भाव बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में रुई और कपड़े के दाम और भी बढ़ सकते हैं। कपास की खेती के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देश में लगभग 62 लाख टन कपास का उत्पादन हर सीजन में होता है। दुनियाभर में कपास उत्पादन में भारत का योगदान 38 फीसदी से ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मप्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रमुख कपास उत्पादक प्रदेश हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

प्रधानमंत्री बीमा में भर्राशाही

देश के हर व्यक्ति का बीमा करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की थी। कम राशि के प्रीमियम पर लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लागों ने बीमा करवाया था। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो योजना का क्लेम बैंक और बीमा कंपनी के बीच इस कदर फंस गया कि 6 माह बाद भी क्लेम नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत नियम है कि क्लेम मात्र 15 दिन में क्लीयर होकर आश्रित के बैंक खाते में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई मामलों में तो क्लेम 6 माह बाद भी नहीं आ पा रहा है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर इसकी जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी पर डाल दे रहे हैं और बीमा कंपनी की कोई भी जानकारी आश्रित के पास होती नहीं, क्योंकि बीमा और क्लेम भेजने की जिम्मेदारी बैंक की होती है।

जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था उनके आश्रित बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे ही कई मामले भोपाल के बैंकों में पेंडिंग हैं और कस्टमर 6 माह से ज्यादा की अवधि से बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कोई भी बीमा पॉलिसी लेते समय ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन उसी योजना पर जब क्लेम लेने का समय आता है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम पॉलिसी में तो यह दिक्कतें आती ही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री बीमा योजना को भी बैंक और संबंधित बीमा कंपनी अपनी कार्यप्रणाली से पलीता लगाते जा रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा बैंक द्वारा किया जाता है। प्रीमियम भी बैंक काटती है। क्लेम भी बैंक के माध्यम से जाता है और क्लेम नंबर भी बैंक को ही दिया जाता है। इसके बावजूद बैंक कर्मी क्लेम की देरी पर संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करने के बजाय कस्टमर को संपर्क करने को कह रहे हैं, जबकि कस्टमर के पास बीमा कंपनी की कोई जानकारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के ऐसे ही कई मामले इस समय आईडीबीआई बैंक सहित कई बैंकों में हैं, जहां लोग क्लेम के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। 84 वर्षीय गायत्री ने बताया कि उनके बड़े बेटे की मृत्यु अप्रैल 2021 में कैंसर से हुई। आईडीबीआई बैंक टीटी नगर के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दी गई थी। मेरे दूसरे बेटे ने 21 अक्टूबर 2021 को क्लेम किया। क्लेम के लिए 6 माह तक बैंक के चक्कर लगाने पड़े। आईडीबीआई कस्टमर केयर में कम्पलेंट दर्ज कराई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कस्टमर केयर को प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है और उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मना कर दिया। उन्होंने ब्रांच से ही संपर्क करने के लिए कहा, जहां से हम 6 माह से चक्कर लगा रहे थे। संबंधित बीमा कंपनी हमें कोई जवाब देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि क्लेम बैंक के माध्यम से गया था।

प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अतंर्गत 330 रुपए निवेश करने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। पॉलिसी की शुरुआत 1 जून से होती है और इसकी वैधता 31 मई तक रहती है वहीं, पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट भी कस्टमर के बैंक अकाउंट से हर साल तय तारीख पर खुद ही कट जाता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर पॉलिसी होल्डर को 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। 12 रुपए का प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाता है। इसे रिन्यू भी कराया जा सकता है। एक मामले में आईडीबीआई और एलआईसी कस्टमर केयर में भी सुनवाई नहीं होने पर एलआईसी के चेयरमेन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जब 6 माह तक क्लेम का रुपया नहीं देने के संबंध में मेल किया गया, तब एलआईसी चेयरमेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेल को सभी संबंधित अधिकारियों को फारवर्ड करते हुए टॉप प्रायोरिटी में सुलझाने के निर्देश दिए। मेल करने के दूसरे दिन ही एलआईसी मुंबई ने आईडीबीआई बैंक से पूरी जानकारी ली और तीन दिन के अंदर क्लेम की राशि खाते में ट्रांसफर हो गई, लेकिन सवाल यह है कि हर किसी की पहुंच एलआईसी के चेयरमेन या मेल आदि की जानकारी नहीं होती है और वे इसी तरह से अभी भी बैंक का चक्कर लगा रहे हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

15 दिन में क्लेम मिलने का प्रावधान

प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक के नॉमिनी द्वारा क्लेम करने के 7 दिन के अंदर बैंक को संबंधित बीमा कंपनी के पास आवेदन भेजना होता है। इतना ही समय संबंधित बीमा कंपनी को भी दिया जाता है कि बैंक से क्लेम का दावा मिलने के 7 दिन के अंदर उन्हें क्लेम का भुगतान करना होता है, यदि डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं हो। लेकिन बैंक और संबंधित बीमा कंपनी दोनों ही इस नियम का पालन न करते हुए दावेदार को 6-6 माह तक बैंक के चक्कर लगवाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे परेशान उपभोक्ता के पास फिर बैंकिंग ओम्बुड्समेन के पास आवेदन करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। वहीं आईडीबीआई बैंक भोपाल के रीजनल हेड श्रीकांत त्रिपुरे का कहना है कि हमारे बैंक के जरिए जो प्रधानमंत्री बीमा किया जाता है, अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित द्वारा हमें क्लेम दाखिल किया जाता है। हम उस क्लेम को संबंधित बीमा कंपनी के पास भेज देते हैं। अगर क्लेम देने में बीमा कंपनी लेट होती है तो उसे हम रिमाइंडर भेजते हैं। हमें ग्राहकों की शिकायतें आ रही हैं जिसे हम दिखवा रहे हैं कि क्लेम लेट क्यों मिल रहा है।

करंट के लिए रहें तैयार

अप्रैल में मप्र सरकार ने एक तरफ जहां लाखों बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ कर राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर महंगी बिजली का झटका मिलने जा रहा है। मप्र बिजली नियामक आयोग के 2.64 फीसदी प्रति यूनिट बिल बढ़ाने को हरी झंडी मिलने के बाद बिजली वितरण कंपनी जल्दी ही नए दरों से बिल उपभोक्ताओं को थमाने जा रही है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार बिजली की दरों में 2.64 फीसदी प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि नई दरें कब से लागू होगी, इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। संभवत: इस माह के अंत तक नए टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। नया टैरिफ अप्रैल के बिलों से ही लागू होगा। यानी मई में मिलने वाला बिजली बिल संभवत: जोर का झटका दे सकता है।

नई दरों के अनुसार प्रति यूनिट बिजली 8 पैसे से लेकर 12 पैसे तक महंगी हो जाएगी। वहीं फिक्स चार्ज भी 5 से लेकर 12 रुपए तक बढ़ जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2022-23 के लिए प्रदेश से 45 हजार 971 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है। वर्तमान विद्युत दर में राजस्व अंतर की राशि 1,181 करोड़ रुपए है और उसकी भरपाई के लिए ही बढ़ोतरी की गई है। 50 यूनिट तक की खपत के मौजूदा दाम 4.13 रुपए है, जबकि नए दाम 4.21 रुपए होंगे। फिक्स चार्ज 64 रुपए से बढ़कर 69 रुपए प्रति कनेक्शन हो गया। 51 से 150 यूनिट तक की खपत के दाम 5.05 रुपए से बढ़कर 5.17 रुपए किए गए हैं। फिक्स चार्ज 109 रुपए से बढ़ाकर 121 रुपए प्रति कनेक्शन हो गया है। 150 से 300 यूनिट तक की खपत का मौजूदा दर 6.45 रुपए है और नई दरें 6.55 रुपए हो गई हैं, वहीं फिक्स चार्ज 24 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हुआ। 300 यूनिट से ज्यादा की खपत की दर 6.65 से बढ़कर 6.74 रुपए हो गई है।

उधर, बिजली की कमी ने प्रदेश सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। वैसे तो प्रदेश में 22 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता के दावे किए जा रहे थे लेकिन साढ़े 12 हजार मेगावाट बिजली की मांग पहुंचते ही संकट खड़ा हो गया। बिजली मामलों के जानकार अब सवाल कर रहे हैं कि जब प्रदेश के पास 22 हजार मेगावाट बिजली का करार है तो फिर संकट क्यों हो रहा है। इधर, मप्र पावर जनरेशन कंपनी के तापगृह में भी महज चार दिन का कोयला ही बचा हुआ है। जिससे साफ है कि फुल लोड पर इकाईयां चली तो उन्हें कोयले की कमी के कारण बंद करना पड़ सकता है। बीते 22 अप्रैल को प्रदेश में हर घंटे बिजली की कमी के कारण अघोषित कटौती की गई।

282 से 1600 मेगावाट तक हुई कमी

मप्र में विगत 22 अप्रैल को रात्रि 12 बजे से हर घंटे बिजली की कमी बनी रही। इसमें सिर्फ सुबह 9 बजे 11 बजे के बीच बिजली मांग के अनुरूप मिली। इसके अलावा कमी के दौरान अघोषित कटौती की गई। शाम 7 बजे सबसे कम 282 मेगावाट की कमी बनी रही। उस वक्त 11,138 मेगावाट की मांग प्रदेश में थी। इसके बाद सबसे ज्यादा कमी शाम 4 बजे 1612 मेगावाट की हुई। उस समय बिजली की दिन की सर्वाधिक मांग 12,680 मेगावाट थी। बिजली विभाग के निर्धारित मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कटौती के माध्यम से पूरा किया गया। गांव में बिजली की अघोषित कटौती 4-5 घंटे की हुई।

प्रदेश में बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह कोयला है। माइंस से रेलवे की रैक पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं इस वजह से कमी है। ज्यादातर इकाईयां कोयले से बिजली बनाती है। इसके अलावा बिजली की बैकिंग इस समय होती है क्योंकि रबी सीजन के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। कुछ बिजली को अन्य एक्सचेंज के जरिए बेचा जा रहा है। ऐसे में कृत्रिम बिजली की कमी बनी हुई है।

प्रदेश सरकार के बिजली उपलब्धता के 22 हजार मेगावाट के दावे पर प्रबंध संचालक मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी विवेक पोरवाल ने कहा कि 22 हजार मेगावाट अलग-अलग श्रेणी में बिजली के करार है। कोयला से बनने वाली बिजली का 14 हजार मेगावाट हिस्सा है जिसमें 80 फीसदी ही इकाई से बिजली उत्पादन होता है जो करीब 10-11 हजार मेगावाट है। इसके अलावा हवा, न्यूक्लियर, सोलर से बिजली मिलती है। कई बार मौसम और हवा नहीं चलने से इनका हिस्सा पर्याप्त नहीं मिलता है। विवेक पोरवार के अनुसार प्रदेश में कहीं कोई बिजली का संकट नहीं है। कभी थोड़ी कमी होती है तो एक्सचेंज के जरिए खरीद ली जाती है। उन्होंने माना कि रबी सीजन के लिए प्रदेश में 600 मेगावाट बिजली बैकिंग की जा रही है, वहीं कुछ बिजली बेच रहे हैं। कोयले की कमी को लेकर भी कहा कि इस बारे में उनके पास बहुत बेहतर जानकारी नहीं है लेकिन कोयले की कमी नहीं है।

वहीं मप्र में कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि कुछ परेशानियां हैं जिनका समाधान हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मप्र में कोयले की कोई कमी नहीं है। गर्मी अधिक बढ़ गई है, ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ी है तो उत्पादन भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी मात्रा में कोयला चाहिए उतने कोयले की समय पर व्यवस्था हो जाएगी, प्रदेशवासियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी कोयला संकट को लेकर सवाल खड़े हुए थे हमने तब भी कहा था कि कोयले की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही कहा कि अगर मप्र में प्राकृतिक आपदा आ गई तो बात अलग है, लेकिन हम कमी होने का संकट नहीं होने देंगे। इसको लेकर हमने रेल मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री से बात की है और हम दिन-प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि हमें पर्याप्त कोयला प्राप्त हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी में खपत बढ़ी है जैसे किसी शादी में बारातियों की संख्या 30 के जगह 100 आ जाती है तो उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। अचानक जो मांग बढ़ गई है उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होने देंगे।

● **राजेश बोरकर**

वन समितियों ने किया शानदार काम

मप्र में सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन, संरक्षण एवं सुधार की दिशा में वन समितियों के माध्यम से शानदार काम किया गया है जो पूरे देश में अनूठा है। इन वन समितियों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए हैं। प्रदेश का वनक्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर है जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3 प्रतिशत है। प्रदेश के 79 लाख 70 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन में जन-भागीदारी के लिए 15 हजार 608 गांवों में वन समितियां काम कर रही हैं। पिछले एक दशक में 1552 गांवों में वन समितियों ने 4 लाख 31 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया है। जब पूरी दुनिया में वनों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय इन समितियों ने वन विभाग के साथ मिलकर शानदार काम किया है।

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, वनोपज संग्रह करने वाले परिवारों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। संघ के नवाचारी उपायों से तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। तेंदूपत्ता सीजन में 2021 कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद भी तेंदूपत्ता संग्रहण कराकर दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय परिवारों को 415 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक दिलाया गया और 192 करोड़ का लाभांश भी वितरित किया गया। पुरानी नीति में 70 फीसदी लाभांश संग्राहकों को बोनस के रूप में दिया जाता था। साथ ही 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए और 15 प्रतिशत राशि वन क्षेत्रों में लघु वन उपज देने वाली प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास पर खर्च की जाती थी। अब पेसा अधिनियम की भावना के अनुसार तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का 75 प्रतिशत संग्राहकों को, 10 प्रतिशत राशि संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए और 10 प्रतिशत राशि वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रजातियों के संरक्षण तथा 5 प्रतिशत ग्राम सभाओं को दी जाएगी।

वन विभाग द्वारा नए संकल्प में राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के प्रवेश से मिलने वाली राशि का 33 प्रतिशत वन समितियों को देने का प्रावधान किया गया है। समितियों को आवंटित क्षेत्र में ईको पर्यटन का कार्य संचालित करने के लिए सशक्त किया गया है। इससे होने वाली आय वन समिति को मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के अवसर मिलेंगे। प्रदेश के एक तिहाई गांव वन क्षेत्रों के अंदर या उसके आसपास बसे हैं। वहां के निवासियों की आजीविका वनों पर आधारित है। आत्मनिर्भर मप्र में इस साल के आखिर तक 5 हजार वन समितियों का माइक्रो प्लान तैयार करने का लक्ष्य है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ग्राम समुदाय अपनी आवश्यकता की वनोपज का उत्पादन कर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

वन समितियों को दिए जाने वाले लाभांश में वृद्धि की गई है। पहले जिला स्तर पर शुद्ध लाभ की राशि का 20 फीसदी मिलता था, जिसकी वजह से राशि का वितरण केवल कुछ ही जिलों में हो पाता था। अधिकांश समितियां लाभ से वंचित रह जाती थी। नए संकल्प के अनुसार प्रत्येक समिति को उसके क्षेत्र में से किए गए दोहन से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहले काष्ठ एवं बांस का 50 करोड़ रुपए तक का लाभांश वितरण होता था। अब लगभग 160 करोड़ प्रति वर्ष हो रहा है। वन समितियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का अधिकार अब ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। वन समिति की कार्यकारिणी में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लोगों को शामिल करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में अनेक प्रकार की वनोपज का उत्पादन होता है। इसमें महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और चिरौंजी प्रमुख है। पेसा कानून की भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों का पूरा अधिकार सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जो वन समितियों से जुड़े संग्राहक परिवारों के लिए परिवर्तनकारी साबित हुए हैं। वन समितियों को भरपूर आर्थिक लाभ हुआ है। उदाहरण के लिए 32 वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से करीब 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। तेंदूपत्ता व्यापार के शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत देने से 17 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर में लगातार वृद्धि की गई है। इसी के अनुपात में पारिश्रमिक और बोनस का भुगतान भी किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2005 में प्रति मानक बोरा 400 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा हो गई है। पारिश्रमिक का भुगतान वर्ष 2005 में 67 रुपए करोड़ रुपए होता था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 415 करोड़ रुपए हो गया है। संग्राहकों के बच्चों के लिए एकलव्य शिक्षा योजना पिछले ग्यारह साल से चल रही है, जिससे अब तक 1712 बच्चों को शिक्षा के लिए 2 करोड़ एक लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

वन समितियों के उल्लेखनीय काम

सतना की ग्राम वन समिति गोदीन ने गोंड जनजाति की महिलाओं को सॉफ्ट टॉय बनाने का प्रशिक्षण ग्रीन इंडिया मिशन में दिया है। इसी प्रकार सीधी वन मंडल की ग्राम वन समिति बम्हनमरा ने बिगड़े वन क्षेत्र में काम करना शुरू किया और अवैध कटाई, चराई, अतिक्रमण से जंगलों की सुरक्षा की। समिति को महुआ फूल, गुल्ली, अचार, जलाऊ लकड़ी मिल रही है। बालाघाट की ग्राम समिति अचानकपुर ने बांस-रोपण क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। बांस के दोहन से समिति को एक लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। वन मंडल सीधी की ग्राम वन समिति ने वन विहीन पहाड़ी में काम करना शुरू किया और अपने परिश्रम से इसे सघन सागौन वन में बदल दिया। समिति को सागौन की बल्लियों से आर्थिक लाभ भी हुआ। वन मंडल पश्चिम मंडला की ग्राम वन समिति मनेरी ने वन विहीन पहाड़ी को हरा-भरा बना दिया। इसी प्रकार अन्य समितियां भी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार के सहयोग से शानदार काम कर रही हैं।

बंजर हो रही खेती की जमीन

दलहन और तिलहन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में शुमार बुंदेलखंड के किसानों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। लगातार सूखे और प्राकृतिक आपदाओं की मार सहते हुए बुंदेलखंड की कृषि योग्य जमीन बंजर होने की कगार में पहुंच गई है। पानी की कमी या बढ़ता प्राकृतिक असंतुलन कारण चाहे जो भी हो पर यहां की कृषि योग्य भूमि से अति आवश्यक पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। जिससे न केवल कृषि योग्य भूमि घट रही है बल्कि इससे उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर खेत बंजर हो रहे हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति ऑर्गेनिक कार्बन पर निर्भर करती है और यही यहां पर लगातार कम हो रहा है। इसकी कमी जमीन को बंजर बना देती है।

कृषि मृदा शोध एवं सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक हबीब खान के मुताबिक बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने में सहायक खनिज तत्व अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। जिसके चलते यहां कई क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि बंजर होने लगी है। यह सब किसानों की लापरवाही का नतीजा है, जिन्होंने देसी खादों का प्रयोग पूरी तरह बंद कर सिर्फ रासायनिक खादों को खेती का सहारा मान लिया है। जिसके चलते कृषि योग्य भूमि से पोषक तत्व पूरी तरह नष्ट हो रहे हैं। खान ने बताया कि 2017-2018 में हुए सर्वे के अनुसार ऑर्गेनिक कार्बन 0.8 से घटकर 0.2 से 0.25 फीसदी तक पहुंच गया है। जबकि फास्फेट 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह सिर्फ 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जगह 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्तर तक पहुंच गया है। यह स्थिति खेती के लिए बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। क्योंकि जिस बुंदेलखंड के किसान एक वक्त में दलहन और तिलहन की अच्छी पैदावार करते थे उसमें अब वे काफी पिछड़ चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीज, खाद और पानी के रूप में किसानों का लगाया पैसा भी अब मुश्किल से निकल पा रहा है। हालत इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि किसानों की इनकम बढ़ने की बात छोड़िए उनकी लागत निकाला मुश्किल है। यहां के एक बुजुर्ग किसान संतोष सिंह की मानें तो आज से 15 से 20 साल पहले वो एक बीघा खेत में लगभग 25 मन अनाज पैदा करते थे पर आज यह 10 मन रह गया है। बंजर होती जमीन की वजह से उत्पादन कम हो रहा है। पानी की कमी और रासायनिक उर्वरकों ने खेती की स्थिति खराब कर दी है।

कृषि वैज्ञानिक हबीब खान के मुताबकि फसलों की वृद्धि और अच्छी पैदावार के लिए ऑर्गेनिक कार्बन खेती का जरूरी तत्व है। जो पौधों को खड़ा रहने की ताकत देता है। फास्फेट तत्व पौधे की वृद्धि और उनके निर्माण के लिए आवश्यक है। वहीं पोटाश फसल और उसके बीज व फल में चमक पैदा करता है। मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है। इन तत्वों का जमीन से कम होना परेशानी का सबब है। रासायनिक खाद की जगह धीरे-धीरे जैविक खाद का प्रयोग करें तो 3 से 5 साल में जमीन की स्थिति फिर से सामान्य हो सकती है। किसान ऑर्गेनिक कार्बन को पूरा करने के लिए खेत में हरी खाद का इस्तेमाल करें। इसके लिए वो ढैंचा और सनई बो सकते हैं। ढैंचा का बीज 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। करीब 35 से 40 दिन में खड़ी फसल को जोत कर खेत में पलटकर उसमें पानी भर दें। ऐसा करने से खेती बेहतर होगी। इसी तरह पोटाश की कमी को दूर करने के लिए 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर खाद को जुताई के दौरान शाम को खेतों में डालें या 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें।

जमीन की घटती उत्पादन क्षमता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (पूसा) के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉ. टीपी त्रिपाठी इसे देश और किसानों दोनों के लिए चिंता का विषय बताते हैं। देश के कई हिस्सों में जमीन लैंड माइनिंग हो रही है, मतलब वो ऊपर से ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों को डालकर जमीन का दोहन कर रहे हैं, यही वजह है कि जमीन में कार्बन (जैविक तत्व) और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो बिगड़ गया है। विश्व मृदा दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने एक बयान जारी करके बताया, खेत की मिट्टी से उपज और किसान की आमदनी जुड़ी है, इसलिए उसके खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि खेत की मिट्टी, कृषि-खाद्य उत्पादन का आधार है। मिट्टी पौधों को पोषक तत्वों और जल की आपूर्ति करती है। दुनिया का 95 फीसदी खाद्य पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होता है। स्वस्थ मिट्टी के बिना हम स्वस्थ खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं कर सकते। मृदा केवल खाद्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि ये बारिश के पानी को छानती है और कार्बन को स्टोर करती है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

उप्र में हालत और खराब

देश के सबसे बड़े राज्य उप्र में जमीन की हालत और भी खराब है। उप्र कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले डेढ़ दशक से चल रहे उर्वरता संबंधी अध्ययन के मुताबिक, सहारनपुर से लेकर बलिया तक इंडो गैंजेटिक बेल्ट में खेतों की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में भारी गिरावट आई है। यही नहीं पूर्वी और पश्चिमी उप्र के इलाकों में पिछले 5-6 सालों में फास्फेट जैसे पोषक तत्व में भी जबर्दस्त कमी देखने को मिली है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज आदि भी खेतों से कम होते जा रहे हैं। तिलहनी फसलों की पट्टी के इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, फरुखाबाद और कानपुर जिलों में गंधक तत्व में भी काफी कमी आई है। प्रदेश में खेतों की मिट्टी की उर्वरता परखने के लिए अपनी मिट्टी पहचानों अभियान भी चलाया गया था।

भारत सहित दक्षिण एशिया में इस बार रिकार्डतोड़ गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आती जा रही है और इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण भारत में 2022 में ही 2050 के बराबर गर्मी पड़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती विनाश की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारी धरती को बचाने के लिए अब केवल 8 साल ही बचे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। वरना धरती झुलस जाएगी।

● राजेंद्र आगाल

भारत सहित पूरा दक्षिण एशिया इस साल गर्मी से झुलस रहा है। भारत में तो इस बार गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि इस साल भारत में गर्मी का पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आती जा रही है और इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी के मुताबिक हमारी धरती को बचाने के लिए अब केवल 8 साल ही बचे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। अगर धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए प्रयास नहीं किए गए तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। उधर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान तो बढ़ ही रहा है, इससे कई प्रकार की महामारी और बीमारी भी उत्पन्न हो रही है, जो मानव जीवन के लिए खतरे के संकेत हैं। अगर समय रहते नहीं चेते तो धरती का विनाश हो सकता है।

विनाश की राह पर धरती

धरती के बीते 2000 वर्षों के इतिहास की तुलना में अब बीते कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान बेहद तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कई दशकों से लगातार वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्लोबल वार्मिंग की आग तेजी से धधक रही है। तमाम वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल दुनिया से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जीवाश्म ईंधन खत्म होना तो दूर इसको कम करने के भी आसार साफ नहीं नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि धरती को बचाने के लिए अब सिर्फ 8 साल ही बचे हैं। अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) ने इसी उदासीनता के चलते जलवायु परिवर्तन के आंकलन के लिए अपनी 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट में चेताया है। इसमें कहा गया है कि अगले 8 सालों में यानी 2030 तक दुनिया अगर अपने उत्सर्जन में कटौती को आधा यानी 50 प्रतिशत कम नहीं करती है तो साल 2050 तक उसे नेट जीरो यानी अपने उत्सर्जन स्तर को शून्य पर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 में 1990 के मुकाबले 54 प्रतिशत अधिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन हुआ लेकिन उत्सर्जन के बढ़ने की दर पिछले एक दशक में घटी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 99.9 फीसदी इंसान ही जिम्मेदार हैं। पिछले 8 सालों में हुए 88,125 अध्ययनों के परिणाम इसकी पुष्टि भी करते हैं। 2012 से लेकर 2020 तक अलग-अलग जर्नल्स में पब्लिश हुए 88 हजार से अधिक अध्ययनों को पढ़ा और समझा गया। परिणाम में पुष्टि हुई कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान ही जिम्मेदार हैं।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धरती के तापमान वृद्धि को **डेढ़ डिग्री** तक रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कटौती करनी होगी। साल 2010-2019 में दुनिया का औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मानव इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर था। ऐसे में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को जीरो पर लाना होगा। इस काम के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की आवश्यकता है और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भारी कमी लानी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा, साथ ही स्टोरेज बैटरी की लागत में भारी गिरावट आई है। इससे वह लगभग गैस और कोयले के बराबर (और कुछ मामलों में सस्ते) हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2010 के बाद से लागत में '85 प्रतिशत तक की निरंतर कमी' देखी गई है। ग्लोबल कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार कम हुई है पर उत्सर्जन अब भी 54 प्रतिशत अधिक है। वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे अमीर देश ही अकेले विश्व के कुल उत्सर्जन के आधे के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि दुनिया के सबसे गरीब देशों का हिस्सा सिर्फ 12 प्रतिशत है। वर्तमान में हम वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित करने से बहुत दूर हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा नीतियां सफल भी होती हैं तो वो हमें सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक वार्मिंग की ओर ले जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई नया **जीवाश्म ईंधन विस्तार** न भी किया जाए, फिर भी मौजूदा ढांचे की वजह से 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन 22 प्रतिशत अधिक होगा और 2030 तक 66 प्रतिशत अधिक होगा। साथ ही, मौजूदा ढांचे के चलते दुनिया में 846 गीगा टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होना तय है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कोयले में नए निवेश न करने के साथ ही सभी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को 2040 तक बंद करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2040 तक एक वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का नेट जीरो होना जरूरी है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड को हटाना होगा।

122 वर्षों के इतिहास में सबसे गर्म मार्च

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार यदि मार्च के अधिकतम तापमान के लिहाज से देखें तो इस वर्ष मार्च का महीना इतिहास का सबसे गर्म मार्च था जब अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो कि सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं यदि औसत तापमान के हिसाब से देखें तो मार्च 2022, 2010 के बाद इतिहास का दूसरा सबसे गर्म मार्च था जब तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था। इसी तरह यदि जनवरी से मार्च के औसत वैश्विक तापमान को देखें तो वो सामान्य से 0.88 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था जो उसे रिकॉर्ड का पांचवा सबसे गर्म साल बनाता है। एशिया में भी इन तीन महीनों का औसत तापमान पांचवा सबसे गर्म था। वहीं दक्षिण अमेरिका, यूरोप, कैरिबियन क्षेत्र और ओशिनिया में जनवरी से मार्च का औसत तापमान उसे नौवीं सबसे गर्म अवधि बनाता है। हालांकि अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में तापमान सामान्य से ज्यादा था, लेकिन यह क्रमशः 2012 और 2014 के बाद से उनका अब तक का सबसे ठंडा वर्ष था। यदि आर्कटिक और अंटार्कटिका में जमे बर्फ की बात की जाए तो उनके लिए भी यह महीना अच्छा नहीं रहा। अंटार्कटिका में इस माह समुद्री बर्फ की हद सिर्फ 10.9 लाख वर्ग मील दर्ज की गई थी, जो कि 44 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार है जब मार्च के महीने में बर्फ की सीमा इतनी कम है। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2017 में बर्फ की सीमा इतनी कम थी।

ग्लोबल वार्मिंग में कहां खड़ा है भारत

भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में से 6.8 प्रतिशत का हिस्सेदार है। वर्ष 1990 से 2018 के बीच भारत के ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 172 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 से 2018 के बीच देश

आग में घी डालने का काम कर रहे हैं एयरकंडीशनर

लू के महीनों में बिजली की आधी से ज्यादा मांग के लिए ऑफिसों, दुकानों और घरों में लगने वाले एसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दिल्ली को ठंडा रखने के लिए अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों को जलाया जा रहा है। अप्रैल के महीने में यहां बिजली की एक दिन में औसतन मांग 4,336 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। 2018 में, जब से बिजली की मांग की रीयल-टाइम ट्रैकिंग शुरू हुई है, तब से यह बिजली की सबसे ज्यादा मांग है। यह दो साल पहले यानी अप्रैल 2020 की मांग के लगभग दोगुनी है। राजधानी में बिजली की ज्यादातर मांग, गरमी पैदा कर बनाई जाने वाली बिजली से पूरी की जाती है। इसलिए इस मौसम में ठंडक बनाए रखने के मोह का एक ही उपाय है- ज्यादा ईंधन को जलाना। दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा व्यापक गर्मी और दिल्ली की बिजली की मांग के बीच संबंधों को लेकर किए गए एक मूल्यांकन में पाया गया था कि यहां लू के महीनों में बिजली की आधी से ज्यादा मांग के लिए ऑफिसों, दुकानों और घरों में लगने वाले एसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए एयर कंडीशनरों के प्रति बढ़ती चाहत को दोषी माना जाना चाहिए।

में प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन भी 17 फीसदी बढ़ा है। अभी भी भारत का उत्सर्जन स्तर जी-20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है। भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन आधारित प्लांट्स का योगदान 74 प्रतिशत है। भारत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 11 फीसदी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वर्तमान नीतियां वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप फिलहाल नहीं हैं। इसके लिए भारत को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को 1603 मिलियन टन **कार्बन डाईऑक्साइड** के बराबर (एमटीसीओ2ई) (या वर्ष 2005 के स्तरों से 16 प्रतिशत नीचे) रखना होगा। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का है। अगस्त 2021 तक भारत में 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है। एक और 50 गीगावाट क्षमता अभी निर्माणाधीन है और 27 गीगावाट क्षमता के संयंत्र अभी निविदा के दौर में है। भारतीय रेलवे वर्ष 2023 तक अपने नेटवर्क के विद्युतीकरण की योजना बना रही है और वह वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की राह पर आगे बढ़ रही है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने संबंधी वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य को अब 2025 तक के लिए कर दिया गया है।

उत्सर्जन सीमित करने के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीसरे कार्य समूह के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे विश्व को 2019 और 2030 के बीच अपना उत्सर्जन घटाकर लगभग आधा करने की जरूरत है, ताकि वर्ष 1850 की तुलना में औसत वैश्विक तापमान बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उचित अवसर मिल सकें। उत्सर्जन के मौजूदा स्तर को देखें तो अभी पूरा विश्व 2.5 से 3.4 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ोतरी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस बात से इसके प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं कि बार-बार गर्म हवाएं या लू चलना, चक्रवात आना या ऐसी अन्य जलवायु आपदाएं, जिनका भारत भी सामना कर रहा है, वैश्विक तापमान में सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के नतीजे हैं। आईपीसीसी के मूल्यांकन के अनुसार, इस दशक में और आगे के समय में ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के उपायों में तेजी लाने के लिए कई तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में अगर कार्बन, कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) तकनीक शामिल नहीं है, तो 2030 तक कोयले की वैश्विक खपत को कम से कम 67 प्रतिशत तक घटाना होगा।

अब ग्लोबल वार्मिंग के खतरे

वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि 2021 से 2025 के बीच एक साल ऐसा होगा जो सबसे अधिक रिकॉर्ड गर्मी वाला होगा। 40 फीसदी तक 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने का खतरा है। वो साल 2016 में पड़ी गर्मी को पीछे छोड़ देगा। बढ़ते तापमान से बर्फ पिछलेगी और समुद्र के जल का स्तर बढ़ेगा। इससे मौसम बिगड़ेगा। नतीजा, खाना, सेहत, पर्यावरण और विकास पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि यह समय सतर्क होने का है। दुनियाभर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। कैम्ब्रिज और टबिजेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इंसान की लंबाई और दिमाग को छोटा कर सकता है। पिछले लाखों सालों में इसका असर इंसान की लंबाई-चौड़ाई पर पड़ा है। इसका सीधा कनेक्शन तापमान से है। जिस तरह से साल-दर-साल तापमान में इजाफा हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, उस पर वैज्ञानिकों की यह रिसर्च अलर्ट करने वाली है।

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में मौजूद 40 फीसदी तक शार्क और रे मछलियां विलुप्ति की कगार पर हैं। इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन, जरूरत से ज्यादा मछलियों का शिकार। मछलियों पर 8 साल तक हुई रिसर्च में सामने आया कि 2014 के इनकी विलुप्ति का खतरा 24 फीसदी था जो अब बढ़कर दोगुना हो गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ऐसे मछलियों के लिए समस्या बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ उनके मनमुताबिक आवास के लिए माहौल में कमी आने के साथ समुद्र के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका, चीन समेत दुनियाभर के 10 देशों के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी दक्षिण एशिया में रहती है। यह क्षेत्र पहले से ही सबसे ज्यादा गर्मी की मार झेलता है। ऐसे में बढ़ता तापमान यहां के लिए बड़ा खतरा है। इस क्षेत्र के करीब 60 फीसदी लोग खेती-किसानी करते हैं। उन्हें खुले मैदान में काम करना पड़ता है, ऐसे में उन पर लू का जोखिम बढ़ेगा।

महामारी और सूखा

अंतरराष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के कारण 21वीं सदी के अंत तक पूरे विश्व के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। जिसकी वजह से

2036 से 2065 के बीच में गर्म हवाओं का खतरा बढ़ेगा। आने वाले 100 सालों में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोके जाने पर 3 से 4 मीटर समुद्री जल स्तर बढ़ने का अनुमान है। भारत की कृषि व्यवस्था पर सूखे और अकाल का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिसके बारे में अक्टूबर महीने में जी-20 देशों ने रोम में एक बैठक करते हुए, अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट में कहा था कि जिस तरह कार्बन उत्सर्जन तेजी से पर्यावरण में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक पूरे विश्व के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। जिसका असर सभी देशों पर पड़ेगा और खासकर भारत जैसे देशों में 2036 से 2065 तक के बीच लू (गर्म हवाओं) का कहर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो आज के समय से 25 गुना अधिक होगा। यह रिपोर्ट 40 से भी अधिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा तैयार की गई थी, जो यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए थे। इस रिपोर्ट को मानें तो भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तनों का प्रभाव सभी देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। बता दें कि जी-20 एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी मंच है, जिसमें भारत समेत 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम, वित्तीय स्थिरता और सतत् विकास से जुड़े तमाम आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने का काम करती है।

एनवायर्नमेंटल एंड एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट के अनुसार, 'ग्लोबल वार्मिंग' और 'जलवायु परिवर्तन' शब्दों का उपयोग अक्सर सापेक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन 'जलवायु परिवर्तन' शब्द खासतौर पर मौसम के अलावा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र के तापमान, आदि में लगातार होने वाले परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए काम में लाया जाता है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग शब्द को पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जाना जाता है।

चिंताजनक है समुद्रों का बढ़ता जल स्तर

यह तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 71 प्रतिशत समुद्र का जल फैला हुआ है, इसके अलावा 1.6 प्रतिशत पानी पृथ्वी के अंदर तथा 0.001 प्रतिशत वाष्प और बादलों के रूप में है। वहीं पृथ्वी पर पीने योग्य पानी केवल 3 प्रतिशत है, जिसमें से 2.4 प्रतिशत पानी ग्लेशियर और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के रूप में जमा है, बाकी 0.6 प्रतिशत पानी नदियों और झीलों में है। समुद्रों के बढ़ते जलस्तर की वजह ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान ही है। संपूर्ण विश्व के ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती जा रही हैं।

2030 तक हर साल 560 आपदाओं से जूझना होगा

जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इससे न केवल अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि मानव जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने डराने वाली तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट में इस बात के संकेत हैं कि आने वाले साल धरती के लिए कई तरह की नई आफत लेकर आ सकते हैं। दुनिया को 2030 तक हर साल करीब 560 विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। 2015 में ऐसी आपदाओं की संख्या हर साल करीब 400 थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले वर्षों में धरती पर जो आपदाएं बढ़ेंगी, उनमें जंगलों में आग और बाढ़ जैसी मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके साथ ही महामारी और रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी खतरनाक आपदाएं भी शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु संबंधी खतरों की संख्या, उसकी आवृत्ति, समय और गंभीरता लगातार बढ़ रही है। 1970 से साल 2000 तक दुनिया में हर साल आने वाली आपदाओं की संख्या 90 से 100 थी। साल 2030 में 2001 के मुकाबले लू की आवृत्ति हर साल तीन गुना ज्यादा हो सकती है। सूखे के हालात में भी करीब 30 फीसदी का इजाफा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस दशक में केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही प्रकोप नहीं होगा, बल्कि कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी और खाद्य संकट जैसी मुसीबतें भी दुनिया को घेरेंगी। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कम करने के विभाग की प्रमुख मैमी मिजोतुरी ने कहा कि 1990 तक प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया को हर साल करीब 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब ये नुकसान बढ़कर 170 अरब डॉलर से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने साल 2019 की रिपोर्ट में चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस हिसाब से साल 2100 तक 80 प्रतिशत बर्फ पिघल कर समाप्त हो सकती है। इन ग्लेशियर से निकला पानी सीधे समुद्र में जाता है। जिससे समुद्र के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। 20वीं सदी में दुनियाभर के समुद्रों का जलस्तर लगभग 19 सेमी बढ़ा है। अगर ऐसे ही बर्फ तेजी से पिघलती रही तो आने वाले 100 सालों में समुद्र का जल स्तर 2 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। जिसके कारण समुद्र के किनारे बसे हुए देश और शहर जलमग्न होकर डूब सकते हैं।

आपने कैप्टन अमेरिका फिल्म तो देखी होगी जिसमें कैप्टन कई सालों तक बर्फ में बेहोशी की हालत में जिंदा दबा रहता है। अगर फिल्मों से बाहर निकलें तो यह आप भी अच्छे से जानते हैं कि बर्फ के नीचे कोई चीज सड़ नहीं सकती और वह कई सालों तक सही सलामत रहती है। चाहे वह **कोई वायरस** हो या जीवाणु विषाणु हो। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम तिब्बत पठार के विशाल ग्लेशियर पर रिसर्च करने गई थी। जिनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इन ग्लेशियर के बर्फों में क्या रहस्य छिपा हुआ है। जब वैज्ञानिकों के सामने रिपोर्ट आई तो सब परेशान हो गए क्योंकि 15000 साल पुराने 28 से भी अधिक अलग-अलग तरह के वायरस जिंदा दबे पाए गए, अगर ये वायरस बर्फ से बाहर आ जाते हैं, तो दुनिया के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम कोरोना वायरस को भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं।

भारत पर सबसे बुरा दुष्प्रभाव

दुनिया की जलवायु में बदलाव होने पर इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यहां कई तरह के मौसम भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में कई जलवायु हॉटस्पॉट हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो तीन तरफ समुद्रों से तथा एक तरफ

हिमालय की बर्फ के पहाड़ों से घिरा है। अगर यहां तापमान बढ़ता है, तो भारत की स्थिति बेहद खराब होगी और यहां कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर इन विषयों पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारत में बदलती जलवायु के कारण यहां की स्थिति जल्द ही काफी दयनीय हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार यदि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो भारत में 2036 से 2065 के आसपास लू (गर्म हवाओं) का कहर सामान्य से 25 गुना अधिक समय तक रहेगा। अगर विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ता है तो भी लू का कहर 5 गुना अधिक समय तक रहेगा। अगर इसी तरह देश में गर्मी का कहर बढ़ता रहा तो यह लोगों की आजीविका को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2050 तक कम उत्सर्जन परिदृश्य में और श्रम उत्पादन में करीब 13.4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती हैं, और अगर जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं सोचा गया तो यह आंकड़ा साल 2080 तक बढ़कर 24 प्रतिशत तक जा सकता है। जिसकी वजह से प्राकृतिक वर्षा जल तथा मौसम पर निर्भर किसानों को भयंकर पानी की कमी से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं, विश्व का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की स्थिति में भारत में साल 2050 तक कृषि के लिए पानी की मांग लगभग 29 प्रतिशत बढ़ जाएगी तथा 2036 से 2065 के बीच कृषि संबंधित सूखे के 48 प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। इसी तरह कम उत्सर्जन परिदृश्य में 2050 तक पकड़ी जाने वाली समुद्र की मछलियों में भी 8.8 प्रतिशत की गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो बदलते जलवायु के कारण आने वाले समय में भारत की स्थिति पर काफी बुरा दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है।

खतरे में पहाड़ों की जैव विविधता

पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, बावजूद इसके पृथ्वी पर मानवीय दखल में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। पृथ्वी के संरचनात्मक ढांचे

जैसे जलवायु, जैव विविधता, जल स्रोत, जैव संपदा और पर्यावरण में विगत दशकों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जो पूर्ण रूप से मानव जनित हैं। जैव प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. मणिंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान वैश्विक स्तर पर 2.2 प्रतिशत तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी पाई गई। जबकि पर्यावरण के बिगड़ते हालात में ग्रीन हाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन की भूमिका लगभग 45 प्रतिशत है, जो जैव विविधता, जल स्रोत, ग्लेशियर, कृषि उत्पादकता, मानव जीवन तथा स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

नैनीताल के पटवाडांगर में पाए जाने वाला पटवा (मिजोट्रोपिस पिलेटा) व हल्द्वानी के आसपास में पाया जाने वाला हल्दू (हल्दीना कार्डिफोलिया) के वृक्ष आज ज्वलंत उदाहरणों में से एक हैं। जिनको बदलती जलवायु ने संकटग्रस्त श्रेणी में ला खड़ा किया है। कभी हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में हल्दू के वन बहुतायत में पाए जाते थे, वह आज विलुप्ति के कगार पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीजों से नए पौधों का प्राकृतिक रूप से संवर्धन आसानी से नहीं हो पाना है। हल्दू के बीज बहुत ही माइनर होते हैं, जो वातावरण में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन से उग नहीं पा रहे हैं। इसके बीज अंकुरण के समय ज्यादा पत्तियों से दबे होने के कारण पौधे का रूप लेने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पटवा का भी जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संवर्धन आसानी से नहीं हो पाता। समय रहते यदि कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो शीघ्र ही इन दोनो प्रजातियों को विलुप्तप्राय श्रेणी में आने की संभावना है।

पृथ्वी के बिगड़ते हालात में आज विकास के बजाय पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना ज्यादा हितकर है। पृथ्वी के पुनरोद्धार एवं उसको पुराने रूप में दोबारा स्थापित करने के लिए उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता है, जो पृथ्वी के मुख्य प्राकृतिक घटक है। छोटे जलस्रोतों का जीर्णोद्धार, वनों के अंधाधुन कटान पर रोक, पौधरोपण को बढ़ावा, ग्लोबल वार्मिंग के कारकों पर तत्काल रोक, जैव विविधता के संरक्षण पर जोर, अनियंत्रित विकास पर रोक, प्लास्टिक पर प्रतिबंध आदि क्षेत्रों में धरातल पर कार्य करके कुछ हद तक पृथ्वी के पुराने स्वरूप को धीरे-धीरे दोबारा स्थापित किया जा सकता है।

सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर्स का करीब 64 प्रतिशत हिस्सा पिघल जाएगा

ये हम सब जानते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक बढ़ गई है। कई वैश्विक रिपोर्ट्स में बढ़ते तापमान पर चिंता और इसके दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। ठंडे साइबेरिया में गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह मनुष्य की क्लाइमेट से छेड़छाड़ है। ओशन एंड आइस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक एशिया के ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में स्थित ग्लेशियर्स का करीब 64 फीसदी हिस्सा पिघल जाएगा। हालांकि यह भी बताया गया कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सका तो यह नुकसान करीब 36 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। जो एशिया महाद्वीप के लिए जल सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फर्क पैदा करेगा। आईपीसीसी की महासागर और क्रायोस्फेयर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओशन एंड आइस नामक रिपोर्ट में इन चिंताओं को जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया जलवायु परिवर्तन के कई बड़े प्रभावों के अभूतपूर्व दबावों का सामना करेगा। इनमें जल सुरक्षा में कमी, खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर मंडराते जोखिम, तटीय और सामुद्रिक तंत्रों पर बढ़ता दबाव और बाढ़ तथा नदी के प्रवाह पर असर का कारण बनने वाली चरम मौसमी स्थितियों की तीव्रता में वृद्धि शामिल हैं। इनसे खेती का मिजाज अप्रत्याशित हो जाएगा।

गृह राज्य में नड्डा की परीक्षा

हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व की तरह मुकाबला केवल देश की दो बड़ी पार्टियों, सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस में ही होगा ऐसा नहीं लगता। क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी भी यहां पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राह कुछ मुश्किल जरूर हुई है। बात भाजपा की करें तो इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर चुनावी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वैसे भी उनका गृहराज्य होने की वजह से यहां पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का उन पर काफी दबाव भी होगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल पिछले साल हिमाचल की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बढ़ा था लेकिन उसके लिए राज्य से किसी बड़े नेता का ना होना मुश्किलें पैदा कर सकता है। जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में काफी दिलचस्पी दिखा रही है तभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस महीने दोबारा हिमाचल जा चुके हैं और उनका पहला दौरा तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र मंडी में ही था।

वैसे हाल ही में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उसे बड़ा झटका दिया है लेकिन आपके नेता ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश के लोग उनके साथ हैं और परिवर्तन चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव (2017) में भाजपा ने 68 में से 44 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं। एक सीट सीपीएम को और दो सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे।

अब आम आदमी पार्टी के चुनाव में हिस्सा लेने से परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। ऐसा ही हमने कुछ महीने पहले उत्तराखंड के चुनाव में देखा था जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में काफी जोर दिखया था लेकिन नतीजों में कुछ खास नहीं कर पाई थी, उसका प्रदर्शन हिमाचल में भी वैसा ही रहेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अच्छा करती है तो ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का ही वोट काटेगी जिससे कि भाजपा को फायदा हो सकता है।

हिमाचल में पिछले 4 दशक में कोई भी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में नहीं आई है। राज्य में 1980 के बाद कांग्रेस और भाजपा के हाथों में बारी-बारी से सत्ता रही। हिमाचल से सटे उत्तराखंड में भाजपा दोबारा सत्ता में आई है। 2000 में बने उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार रिपीट हुई हो, नहीं तो वहां भी सत्ता कांग्रेस और भाजपा के हाथों में बारी-बारी से रही। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा आश्वस्त है कि वो हिमाचल में भी ऐसा कर पाएगी।

अपने हाल के दौरों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर खूब हमला किया है। उन्होंने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावे को झूठा बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा जयराम ठाकुर को हटाकर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर को बनाना चाहती है। नड्डा ने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही भाजपा राज्य का चुनाव लड़ेगी। वैसे उनके दावे के बाद चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठने वाले सवालों पर विराम लग गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सक्रियता लगातार बढ़ने से प्रदेश की राजनीति में उनको भाजपा का भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में पार्टी के भीतर गुटबाजी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और खुद अध्यक्ष नड्डा के गुट होने की खबरें चलती रहती हैं। पिछले साल भाजपा को उपचुनावों में मिली हार के पीछे गुटबाजी को बड़ी वजह की तरह देखा गया था। पिछले उपचुनावों में हार के बाद चर्चा थी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है जैसा कि भाजपा ने गुजरात और उत्तराखंड में किया था, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया जिसके पीछे की वजह जयराम ठाकुर की ईमानदार छवि और जेपी नड्डा का करीबी होना माना गया था।

● **अक्स ब्यूरो**

उपचुनावों में हार ने बढ़ाई चिंता

वैसे प्रदेश के उपचुनावों में मिली हार को जेपी नड्डा से ज्यादा जोड़कर नहीं देखा गया था क्योंकि उपचुनाव में नड्डा कैम्पेन के लिए हिमाचल नहीं गए थे और ना ही उनके इलाके में ये चुनाव हुए थे। जानकारों की मानें तो उपचुनाव नतीजों में केवल एक ही फैक्टर काम किया था, वो था-वीरभद्रसिंह। मरणोपरांत भी उन्होंने जनता को प्रभावित किया था। इसलिए तब चर्चा तेज थी कि क्या जयराम ठाकुर आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन भाजपा ने उनको पद पर जारी रखा। हार के बाद अपनी प्रतिक्रिया में जयराम ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जिससे साफ था कि वो हार का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आई। कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जयराम ठाकुर के साथ-साथ भाजपा अध्यक्ष नड्डा के लिए काफी अहम है। क्योंकि जिस तरह गुजरात चुनाव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों से जोड़कर देखा जाएगा इस वजह से कि वो उनका गृहराज्य है, ठीक वैसा ही दबाव इन चुनावों में नड्डा पर भी देखने को मिलेगा।

फिर अधर में रह गई कांग्रेस

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर यानी पीके ने जो फॉर्मूला तय किया था, वह कांग्रेस आलाकमान को पसंद नहीं आया। इसलिए पीके ने कांग्रेस को उसी के हाल पर छोड़ दिया है। एक बार फिर कांग्रेस अधर में लटकी नजर आ रही है।

नेहरू-गांधी परिवार की बलि के बकरे की तलाश अधूरी रह गई। यह परिवार हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिसके सिर नाकामियों का ठीकरा फोड़ा जा सके। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हाथ में आकर भी हाथ से फिसल गए। उन्होंने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रस्ताव बड़ा साफ था-जीते तो हमारी जय-जय और हारे तो तुम्हारी पराजय। प्रशांत किशोर को खेल समझ में आ गया। वह समझ गए कि उनकी दुकान स्थायी रूप से बंद कराने का इंतजाम हो रहा है। यह ऐसा परिवार है जिसे पद चाहिए, लेकिन जवाबदेही नहीं। 5 राज्यों में पार्टी चुनाव हार गई। पांचों राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा हो गया और उन्हें नियुक्त करने वाले राहुल गांधी विदेश छुट्टी मनाने चले गए।

सोनिया, राहुल और प्रियंका की त्रिमूर्ति को चुनाव जिताना भले न आता हो, लेकिन पार्टी पर कब्जा बनाए रखने का मंत्र आता है। इस तिकड़ी को हर वह व्यवस्था मंजूर है, जिससे पार्टी पर उनका कब्जा बना रहे। प्रशांत किशोर बड़ी आदर्श व्यवस्था बना रहे थे। ऐसी व्यवस्था जिसमें परिवार के तीनों सदस्यों के पास सारे अधिकार हों और जवाबदेही भी। यहीं वे चूक गए। परिवार ने हार की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले से ही एक कमेटी का गठन कर दिया। जिसका नाम है- एंपावर्ड एक्शन ग्रुप। प्रशांत किशोर से कहा गया कि इसके सदस्य बन जाएं और रणनीति का जिम्मा लें। प्रशांत किशोर ने बड़े तंज भरे लहजे में कहा कि इतना उदार प्रस्ताव देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति और संगठन में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। राष्ट्रीय दल तो छोड़िए, किसी क्षेत्रीय दल का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। एक चुनाव रणनीतिकार सार्वजनिक रूप से पार्टी में आने का प्रस्ताव ठुकरा कर चला गया। प्रशांत किशोर को भी पता है कि कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस के जरिए वह **अपनी दुकान का विस्तार** करना चाहते थे। उनकी योजना थी कि हार का ठीकरा उनके अलावा बाकी सब पर फूटे। वह इस गुंजाइश को बनाकर रखना चाहते थे कि चुनाव नतीजा आने के बाद कह सकें कि उनकी योजना पर उनके मुताबिक अमल नहीं हुआ।

गांधी परिवार खुश था कि जैसे 2019 के चुनाव में प्रवीण चक्रवर्ती कवच बने थे, वैसे ही अगली बार प्रशांत किशोर बन जाएंगे। 2019 के चुनाव में प्रवीण चक्रवर्ती को डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया था। उन्होंने राहुल गांधी को सपना दिखाया कि कांग्रेस को 180 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हार के बाद सारा जिम्मा उन पर डाला गया। कुछ दिन हाशिये पर रखने के बाद फिर काम पर लगा दिया गया। प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि वह प्रवीण चक्रवर्ती बनें, पर कांग्रेस और प्रशांत किशोर प्रकरण की वास्तविक पटकथा कुछ और ही है। यह पटकथा बता रही है कि गांधी परिवार में राजनीतिक विरासत का जो युद्ध पिछले कुछ सालों से बंद कमरे में चल रहा था, वह खुले में आ गया है। प्रशांत किशोर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और वह इस्तेमाल होने के लिए सहर्ष तैयार भी थे। शर्त इतनी थी कि इस बंटवारे में उन्हें भी केक का बड़ा हिस्सा मिले।

प्रशांत किशोर प्रियंका के साथ मिलकर राहुल गांधी का पत्ता साफ करना चाहते थे। तैयारी थी प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाने की। राहुल गांधी संसदीय दल के नेता बनाए जा रहे थे। संसद में तो उनका पार्टी से भी कम मन लगता है। राहुल गांधी न तो अध्यक्ष बनेंगे और न ही अध्यक्ष पद पर किसी और को बैठने देंगे। इस समय पार्टी पर राहुल और उनकी टीम का कब्जा है। इन सब लोगों को डर था कि प्रशांत किशोर अपनी योजना में सफल हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो तय हुआ कि प्रशांत किशोर को भगाना है, पर ऐसे भी नहीं कि साफ दिखाई दे। तो मुद्दा बनाया गया दूसरे दलों से प्रशांत किशोर के व्यावसायिक संबंध को। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी ने अपनी भद पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत सी पार्टियां चुनाव रणनीतिकारों की सेवाएं लेती हैं, पर सारी बातचीत बंद कमरे में और व्यावसायिक रूप से होती है। कांग्रेस ने ऐसा नजारा पेश किया जैसे प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार न होकर जादूगर पीसी सरकार हों। जो आएंगे और कांग्रेस पार्टी के सारे दुख-दर्द दूर कर देंगे। दरअसल दोनों पक्ष एक-दूसरे को धोखे में रखने की जुगत भिड़ा रहे थे। प्रशांत वही करना चाहते थे, जो राहुल गांधी पिछले 18 सालों से कर रहे हैं। यानी अधिकार सब चाहिए, पर जवाबदेही कोई न हो। वह यह आंकलन करने में चूक गए कि गांधी परिवार को इस मामले में महारत हासिल है। प्रशांत इस खेल के नए खिलाड़ी हैं। वह मात खाने से पहले मैदान छोड़कर भाग गए। इस पूरे खेल में फिर भी फायदे में गांधी परिवार ही रहा। इतने महीनों में जी-23 ने जो दबाव बनाया था, वह हवा में उड़ गया। पार्टी में कोई परिवर्तन न करते

अभिमन्यु नहीं बनना चाहते पीके

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके के कांग्रेस में शामिल होने की तमाम अटकलों और खबरों पर आखिरकार विराम लग गया। दरअसल कांग्रेस में पीके की भूमिका को लेकर तमाम उहापोह थे, तो प्रशांत किसी भी कीमत पर 2017 के उप्र प्रयोग को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। यही वह बिंदु है जहां दोनों के बीच बातचीत बनते-बनते बिगड़ गई। लेकिन पीके और कांग्रेस की बातचीत टूटी है दोस्ती नहीं। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में 2024 लोकसभा चुनावों के लिए एक एम्पार्वड एक्शन ग्रुप बनाकर प्रशांत किशोर को उसका सदस्य बनाकर पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पीके ने इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस में गहराई तक जड़ें जमा चुकीं सांगठनिक समस्याओं को परिवर्तनकारी सुधारों के जरिए सुलझाने के लिए मुझसे ज्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

सोनिया की बनाई समितियां क्या करेंगी?

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6 समितियां बनाई हैं। उनको और इन समितियों के संयोजकों को शायद पता हो कि इन कमेटियों को असल में क्या करना है। लेकिन कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस में जो कहा गया और जो खबर छपी उससे साफ नहीं है कि इनको क्या करना है। कहा जा रहा है कि ये 6 कमेटियां 2024 के आम चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगी। लेकिन सवाल है कि अभी से 2024 की क्या रणनीति बनेगी? किसान व कृषि के मामले में या आर्थिक मामले में कांग्रेस को अभी ऐसा क्या फैसला करना है, जिसके आधार पर उसे अगला आम चुनाव लड़ना है? चुनावी रणनीति बिल्कुल अलग चीज है, जो 6 समितियां अलग-अलग नहीं बना सकती हैं। दूसरे, चुनाव की रणनीति चुनाव से जुड़े 10 तरह के आंकड़ों के आधार पर बनती है। इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 6 समितियां चुनाव की रणनीति बनाएंगी। इनका काम 13 से 15 मई के बीच राजस्थान के उदयपुर में होने वाले नव संकल्प चिंतन शिविर का एजेंडा बनाने का है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। हर बार कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले या कांग्रेस के महाधिवेशन से पहले इस तरह की समितियां बनाई जाती हैं और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। वह रिपोर्ट अधिवेशन में चर्चा के लिए रखी जाती है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस का पिछला अधिवेशन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था तब भी इस तरह की समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी थी।

हुए भी परिवार ऐसा करता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने दूर रहकर अपनी छोटी बहन को बता दिया कि बड़े भाई वही हैं। नुकसान में प्रियंका रहीं, क्योंकि उनकी पार्टी अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा सबके सामने आ गई। जो बात घर के बंद दरवाजों के भीतर थी, वह सार्वजनिक हो गई। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के तीन खेमों में बंटी है। सोनिया गांधी चूंकि बेटे के साथ हैं, इसलिए राहुल का पलड़ा भारी है। प्रशांत कांग्रेस में आते-आते रह गए, लेकिन कांग्रेस को बाय-बाय करने के पहले वह कांग्रेस और कांग्रेसियों को आईना दिखा गए। फिलहाल उन्होंने अपने कपड़े बचा लिए हैं। यह पूरी कहानी देश की सबसे पुरानी और विपक्ष की सबसे बड़ी और एकमात्र राष्ट्रीय विपक्षी दल के पतन की है। आज की कांग्रेस पुरानी कांग्रेस की छाया भी नहीं रह गई है। इसका नया नामकरण सोनिया कांग्रेस के रूप में होना चाहिए। पार्टी हाईकमान 1998 से 2014 तक जो काम अधिकारपूर्वक करता था, अब छल से हो रहा है। इस समय यह तय करना कठिन है कि कांग्रेस में कौन किससे छल कर रहा है? कूटनीति का स्थान कपट ने ले लिया है। ऐसे में पहला शिकार सत्य होता है। कांग्रेस में इस समय जिनके दिल नहीं मिलते, वे भी जोर-जोर से हाथ मिला रहे हैं।

दरअसल, पिछले कई दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की लंबी बातचीत के बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस में प्रशांत की राजनीतिक पारी जल्दी ही शुरू होने वाली है। कांग्रेस के शीर्ष नेता भी मानने लगे थे कि पीके पार्टी में आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कमोबेश सभी बड़े नेताओं की सीधे पीके से बातचीत कराकर यह संदेश दे दिया था कि पीके की कांग्रेस में आने की घोषणा की महज औपचारिकता ही शेष है।

बताया जाता है कि कांग्रेस पीके के तजुर्बे, रणनीतिक कौशल और चुनाव प्रबंधन की कला का पूरा लाभ तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें अपनी कार्ययोजना लागू करने के लिए वह आजादी नहीं देना चाहती है जिसकी प्रशांत किशोर को दरकार है। कांग्रेस चाहती है कि पीके पार्टी में शामिल होकर अन्य नेताओं की तरह सीमित भूमिका और सीमित अधिकारों के साथ काम करें। जबकि प्रशांत अपने काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या बदलाव स्वीकार करने के मामले में एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पीके प्रयोग को लेकर बेहद आशंकित और असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ खुलकर पीके के समर्थन में भी आ गए थे। जी-23 के नाम से जाने जाने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शशि थरूर जैसे कई नेताओं ने पीके से मुलाकात भी की। कई लोगों की उनसे टेलीफोन से भी बात हुई। पीके के समर्थन और विरोध में कांग्रेसियों के बयान भी आने लगे।

बताया जाता है कि इस बीच पीके की कंपनी आईपैक ने तेलंगाना में टीआरएस के चुनाव प्रबंधन का काम संभालने के सिलसिले में बातचीत शुरू की और इसके लिए प्रशांत किशोर खुद हैदराबाद गए और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इसे लेकर भी मीडिया और कांग्रेस के भीतर पीके के इरादों को लेकर सवाल उठे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इसके बावजूद उच्चस्तरीय एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन करने की घोषणा करते हुए प्रशांत किशोर को इसका सदस्य बनने और कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। लेकिन पीके इसके लिए तैयार नहीं हुए। वह कांग्रेस नेताओं के किसी ग्रुप में बंधकर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में उप्र विधानसभा चुनावों में वह कांग्रेस नेताओं के चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु बन चुके हैं।

2017 के उप्र चुनावों के दौरान जब पीके की पूरी कार्ययोजना को बेहद आधे-अधूरे ढंग से लागू करके उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस का जो हश्र हुआ उससे पीके पर ऐसा दाग लगा, जिसे धुलने में उन्हें लंबा वक्त लगा। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर ने तय कर लिया था कि या तो उन्हें अपनी **कार्ययोजना लागू** करने की पूरी छूट मिले और उनके काम में किसी भी नेता का कोई दखल न हो, इसके बाद ही वह कांग्रेस में शामिल होंगे। जबकि कांग्रेस नेतृत्व इसे लेकर उहापोह में था और पीके के कांग्रेस प्रवेश के विरोधी नेता पार्टी नेतृत्व को यह समझाने में सफल हो गए कि पीके या किसी भी एक व्यक्ति को इतनी छूट देना कांग्रेस और नेतृत्व दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। इससे राहुल गांधी की छवि भी प्रभावित होगी और पीके एक नए सत्ताकेंद्र बन जाएंगे। इसलिए बीच का रास्ता निकालकर उन्हें एम्पार्वड एक्शन ग्रुप का सदस्य बनकर पार्टी में काम करने का प्रस्ताव दिया गया जिसे उन्होंने मंजूर करने से इनकार कर दिया।

पीके और कांग्रेस के बीच फिलहाल बात बनते-बनते बिगड़ी है, लेकिन संवाद खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हुए खबरों में बने रहेंगे। इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मुमकिन है कि एक बार फिर उनके और कांग्रेस के बीच मेल मिलाप की नई प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

● **विपिन कंधारी**

देश में इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा जोरों पर है। कई राज्य अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं। ये राज्य भाजपा शासित हैं। उधर, भाजपा शासित राज्यों के इस कदम का अन्य राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल, वोट बैंक के लिए समान नागरिक संहिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब देश एक है तो एक विधान होने में क्या गलत है। वैसे भी वर्षों से नारा दिया जा रहा है एक देश, एक संविधान, एक विधान।

एक विधान से ही बनेगी बात

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम-2005 की वैधता का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। एक हालिया दायर याचिका में इस संबंध में कहा गया है कि यदि इन आधारहीन, अनुचित, अतार्किक और असंवैधानिक अधिनियमों को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो इन प्रविधानों का लाभ उन राज्यों में हिंदुओं को भी मिलना चाहिए, जहां वे 'अल्पसंख्यक' हैं। इस याचिका में संविधान में एक विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और उसकी सुस्पष्ट निर्देशिका-नियमावली बनाने की न्यायसंगत और समीचीन मांग भी की गई है।

दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 में अल्पसंख्यक शब्द प्रयुक्त हुआ है। लेकिन वहां इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के समय वोटबैंक की **मनमानी** राजनीति की। अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों की प्रचलित परिभाषा पर सवाल उठाते हुए अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि प्रचलित परिभाषा के अनुसार तो आज देश में सैकड़ों धार्मिक अल्पसंख्यक समूह और हजारों भाषाई अल्पसंख्यक समूह होने चाहिए। लेकिन यह दर्जा महज कुछ समुदायों को ही क्यों दिया गया है? क्या यह सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति का नायाब उदाहरण नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सेक्शन-2 (सी) के तहत मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। वर्ष 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था।

संबंधित याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ-पत्र दायर करते हुए भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही नहीं है, बल्कि राज्य सरकार भी किसी समुदाय को

जम्मू-कश्मीर की विडंबनापूर्ण स्थिति

इस संदर्भ में जम्मू-कश्मीर का मामला काफी विचित्र और विडंबनापूर्ण है। वहां मुस्लिम समुदाय की संख्या 68.31 प्रतिशत और हिंदू समुदाय की संख्या मात्र 28.44 प्रतिशत है। लेकिन न केवल केंद्र सरकार, बल्कि अब तक की सभी राज्य सरकारों की नजर में वहां का मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है। अब तक वही उपरोक्त दो अधिनियमों के तहत मिलने वाले तमाम विशेषाधिकारों और योजनाओं का लाभ लेता रहा है। हिंदू समुदाय वास्तविक अल्पसंख्यक होते हुए भी संवैधानिक विशेषाधिकारों, संरक्षण और उपचारों से वंचित रहा है। जम्मू-कश्मीर बहुसंख्यकों को 'अल्पसंख्यक' बताने की राजनीति का सिरमौर है। वर्ष 2016 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से कहा था कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, जबकि वास्तविक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय उपेक्षित, तिरस्कृत और प्रताड़ित हो रहा है। उन्होंने मुसलमानों को मिले हुए अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे की समीक्षा करते हुए पूरे भारतवर्ष की जगह राज्य विशेष की जनसंख्या को इकाई मानते हुए अल्पसंख्यकों की पहचान करने और अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति जेएस खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपसी बातचीत द्वारा अविलंब सुलझाने का निर्देश दिया था। लेकिन आज तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

उसकी संख्या और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर यह दर्जा दे सकती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, पंजाब, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं की संख्या काफी कम है। अत: वे अल्पसंख्यक होने की पात्रता को पूरा करते हैं। संबंधित राज्य सरकार चाहे तो अपनी भौगोलिक सीमा में उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करते हुए विशेषाधिकार और संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा देकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसी तरह गुजरात सरकार ने भी अपने यहां जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में 'अल्पसंख्यक' की अधिक समावेशी और तर्कसंगत परिभाषा देते हुए व्यापक नियमावली को बनाना आवश्यक है, ताकि केंद्र, राज्य अपनी मनमानी करते हुए इस प्रविधान का दुरुपयोग न कर सकें। अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर करते हुए 'टीएमए पाइ फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ के 2003 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को आधार बनाया है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है। यहां तक कि अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्रीय कानून बनाने के लिए भी इकाई राज्य होंगे, न कि संपूर्ण देश होगा। इसलिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का नाम-निर्धारण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अर्थात् राज्य विशेष को इकाई मानकर उसके आधार पर होना चाहिए। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह रोचक किंतु विचित्र ही है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या (19.4 करोड़) पाकिस्तान (18.4) से अधिक है। फिर वे अल्पसंख्यक क्यों और कैसे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। मई 2014 में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का कार्यभार संभालते समय नजमा हेपतुल्ला द्वारा दिया गया बयान इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तब कहा था कि भारत में मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।

इसी प्रकार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख करते समय विलुप्तप्राय या संकटग्रस्त समुदायों को अपने धर्म और रीति-रिवाजों के पालन हेतु सुरक्षा और संरक्षण देने की बात की गई है। संविधान में किसी भी समुदाय को कम या अधिक अधिकार देने की बात नहीं की गई है। उसमें सभी समुदायों को समान अधिकार देने की बात की गई है। लेकिन उपरोक्त दो अधिनियमों में संविधान की भावना से इतर मनमाने ढंग से समुदाय विशेष को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर विशेष सुविधाएं, अधिकार और वरीयता देने की गलत परंपरा चल निकली है। गौरतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा और संविधान की भावना के अनुसार क्या मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक का दर्जा पाने का अधिकारी है?

ऐसे में जिस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के निर्धारण में जाति विशेष की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसी तथ्य का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में दिए गए अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और वे ताकतवर भी हैं। अल्पसंख्यक की परिभाषा निर्धारित करते समय और नीति-निर्देशक नियमावली बनाते समय संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है।

ज्ञातव्य है कि कम संख्या अल्पसंख्यक होने का एक आधार है, किंतु एकमात्र आधार नहीं है। सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर संकट और विलुप्ति का खतरा अधिक महत्वपूर्ण आधार है। इस आधार को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय में इन सभी विसंगतियों और विडंबनाओं का सटीक समाधान प्रस्तावित करने की आवश्यकता है, ताकि देश में सबका साथ और सबका विकास हो सके। साथ ही, संवैधानिक प्रविधानों का प्रयोग संबंधित समुदायों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हो, न कि समुदाय विशेष के तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति के लिए हो। निश्चय ही, इतनी बड़ी आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को 'अल्पसंख्यक' का दर्जा दिया जाना संवैधानिक प्रविधानों के दुरुपयोग का अनूठा उदाहरण है। ऐसे प्रविधानों के दुरुपयोग के कारण ही आज समान नागरिक संहिता की मांग बलवती हो उठी है। 'एक देश, एक विधान' ही भविष्य का रास्ता है।

● इन्द्र कुमार

समानता के नाम पर किए कई बदलाव

आजादी के बाद समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले हिंदू समाज के पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकते थे। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। पति-पत्नी को विवाह विच्छेद करके सम्मानपूर्वक एक-दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा शुरू हुई। गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। इनमें कुछ सुधार दूसरे संप्रदायों में पहले से ही थे। मसलन ईसाई समाज में पुरुष एक ही शादी कर सकता था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से पारंपरिक विधि की जगह मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों को तरजीह दी गई, लेकिन वोट बैंक के कारण दूसरे समुदायों में ऐसा नहीं हो सका। आधुनिक सोच का लाभ समाज के केवल एक वर्ग तक ही सीमित न रहे, अपितु वह सभी समुदायों को भी हासिल हो, इसके लिए अदालतें समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए लगातार कोशिश करती रही हैं। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में तय की गई राज्य की जिम्मेदारी अब निर्जीव शब्द समूहों का संग्रह मात्र बनकर रह गई है।

कितनी सफल गोधन न्याय योजना...?

गोठान, गोबर और खाद व आय के संबंध मजबूत करने का दावा करने वाली गोधन न्याय योजना दरअसल गांवों के बजाय शहरों में ही ज्यादा सक्रिय है। गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक और सचिव एस भारती दासन बताते हैं कि राज्य में 8,048 गोठान सक्रिय हैं और पंजीकृत 2,87,473 पशुपालकों में से अब तक 2,04,034 लाभांवित हो चुके हैं। राज्य में 5 फरवरी 2022 तक 62.60 लाख क्विंटल गोबर खरीदी हुई है, जिसके लिए 125 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से 118.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवरधा जिले में भी पनेका पंचायत के संरपंच सुरेश साहू बताते हैं कि अभी उनका गोठान बन नहीं पाया है। इसका काम जारी है। उन्होंने कहा कि गोठान की जमीन कब्जे में थी, जिसे छुड़वाया गया है। अब इसे तैयार किया जाएगा। इसी तरह दुर्ग जिले में भी पाटन क्षेत्र के मोतीपुरा ग्राम पंचायत में गोठान की बाउंड्री के बाहर गाय घूमती हुई मिली। वहीं आसपास की महिलाएं गोठान में लगे हुए नल से पानी भरकर अपने घर ले जाती हैं। मोतीपुरा की सरपंच योगिता साहू हैं, उनके पति देवनारायाण साहू बताते हैं कि नवंबर, 2021 में ही गोठान बना था अभी तक इस गोठान की समिति नहीं बन पाई है। अनुशंसा के लिए विकास खंड में भेजा गया है। 20 जुलाई, 2021 से शुरू की गई गोधन न्याय योजना के तहत प्रत्येक गोठान वाले ग्राम पंचायत में एक 13 सदस्यीय गोठान समिति ही इसका संचालन करती है।

ग्राम सभा बैठक में समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों के नामों की अनुशंसा विकास खंड को भेजी जाती है। वहीं, शहरी क्षेत्र में गोठान समिति जोनवार नगर निगम के अधीन रहती है। समिति के नामों की स्वीकृति के बाद यह गोठान की पूरी व्यवस्था को देखते हैं और इनका लक्ष्य गोठान को स्वावलंबी बनाना है। इस समिति में पशु सखी, कृषि मित्र, युवा, चरवाहा, युवापंच, सचिव और अध्यक्ष होते हैं। समिति का काम है कि वह पंचायत के पशुओं को गोठानों में रखे और गोबर को एकत्र करे। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का काम है कि वह गोबर से कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार करके अपना लाभांश हासिल करे।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर दूर बनचरौदा में गोबर से बिजली बनाने का यह प्रयोग आदर्श गोठान (गायों को रखने की जगह) का हिस्सा है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद करने वाली गोधन न्याय योजना के तहत बिजली बनाने के लिए इस बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। हालांकि, यह मॉडल सिर्फ दिखावे के लिए बचा है। वास्तविकता में यहां बिजली बनाने के लिए रोजाना संयंत्र में गोबर नहीं डाला जा रहा क्योंकि गोठान में बिजली खपत इन दिनों न के बराबर है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच बनचरौदा गोठान में अब तक बायोगैस संयंत्र में पूरी क्षमता के हिसाब से महज 10 दिन का ही (अब तक 4,700 किलो) गोबर डाला गया है। गोठान में स्थापित इस संयत्र को ऑपरेट करने वाले जनक धुवे बताते हैं कि इस वक्त हम रोज जनरेटर नहीं चलाते, इसलिए रोज संयंत्र में गोबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। गोठान पर खरीदे गए गोबर और पशुओं से मिलने वाले गोबर को ही इस संयंत्र में डाला जाता है।

गोबर से बिजली बनाने वाले संयंत्र का तकनीकी पक्ष केरल की अल्ट्राटेक टेक्नोलॉजी देख रही है। कंपनी के इंजीनियर बताते हैं कि यह बायोगैस संयंत्र पुरानी फ्लोटिंग ड्रम तकनीक वाला है, जिसकी गैस भंडारण क्षमता को 10 घनमीटर से बढ़ाकर अब कुल 20 घनमीटर कर दिया गया है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 24 घन मीटर मीथेन गैस पैदा होती है और तीन चरणों का फिल्ट्रेशन करने के बाद करीब 14 घनमीटर (एमक्यूब) गैस बचती है जिससे एक दिन में 25 से 30 यूनिट (किलोवॉट प्रति घंटा) बिजली पैदा की जा सकती है। 30 यूनिट बिजली का इस्तेमाल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कुल 12 पंखे और 24 एलईडी बल्ब को चलाकर किया जा सकता है। या फिर तीन से चार हॉर्स पावर वाली मशीनों से गोबर उत्पादों को भी तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा अब तक हुआ नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा करने वाली गोधन योजना में गोबर से बिजली बनाना एक अहम विस्तार जरूर है लेकिन अभी यह बहुत उम्मीद नहीं जगा रहा। हालांकि, सरकार ने ऐसे ही 5 और गोबर से चलने वाले बिजली संयंत्रों को शुरू करने का दावा किया है।

● रायपुर से टीपी सिंह

7 जिलों में 52 फीसदी गोबर खरीदारी

गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के चार जिलों- रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा और कवरधा के गांवों में कंपोस्ट उत्पादन के साथ उसका इस्तेमाल, गोबर से बिजली बनाने की बात हो, गांवों में पशुओं के फसल चरने की समस्या हो या फिर सड़कों पर आवारा पशुओं की कमी का मामल हो, इनमें योजना का क्रियान्वयन बेहद ढीला है। यहां तक कि गोबर खरीद करने का प्रमुख काम भी अभी राज्य के कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सिमटा हुआ है। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कुल गोठान से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जा चुका है। हालांकि, इसमें कुल 52.76 फीसदी गोबर की खरीद सिर्फ सात जिलों में हुई है, जबकि शेष 47.24 फीसदी गोबर खरीदी राज्य के 21 जिलों से हुई है। वहीं, जिन 7 जिलों में ज्यादा गोबर खरीदी हुई है वहां डेरी ज्यादा हैं। साथ ही राज्य की ज्यादा शहरी आबादी उनमें रहती है। इनमें राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, कोरिया, धमतरी, बालोद शामिल हैं। गांवों में अब भी गोठान बनाने से लेकर उनकी समितियों के गठन और कामकाज का काम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खास और प्रभावी फर्क नहीं डाल रहा। राज्य के कई गोठान बनकर तैयार हैं लेकिन वहां चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी आंकड़ों में दावा है कि गोठानों के लिए अब तक 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2,968 लाख रुपए का पैरादान किया गया है। कई ऐसे गोठान हैं जो मनरेगा फंड के जरिए सिर्फ घेर दिए गए हैं। वहीं, लॉकडाउन के बाद गांव लौटने वाली कई ऐसी श्रमिक महिलाएं हैं जिन्हें अब तक कुछ नहीं हासिल हो सका।

राजस्थान भरोसे कांग्रेस

5 राज्यों में मिली हार और अपनों के साथ छोड़ने से परेशान कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर राजस्थान पर आ टिकी हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हार झेल रही कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी पहली बार राजस्थान में ही मिली थी। जब उपचुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों सहित 3 सीटें जीती थीं। इसके बाद 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर डूबती कांग्रेस का जहाज राजस्थान में आकर किनारा ढूंढ रहा है।

राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में अगले महीने होने वाले चिंतन शिविर में इसका हल खोजेगी। 2 राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस के लिए एक बार फिर राजस्थान उम्मीदों का प्रदेश बनेगा। कांग्रेस राजस्थान की राजनीतिक नीतियों के बूते अपना आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय कर सकती है। नए कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी भी एक बार फिर राजस्थान में ही होने की संभावना है। इससे पहले भी राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान में ही बने थे। वहीं वर्तमान हालातों को देखा जाए तो कांग्रेस के लिए राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। कांग्रेस की राजस्थान पर निर्भरता की कई वजहें हैं।

पिछले कुछ वर्षों में नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो राजस्थान ही वो राज्य है, जहां कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आती है। बहुमत की सरकार होने के साथ-साथ कई छोटी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं। वहीं, राजस्थान ऐसा एकमात्र राज्य है जहां के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं गए हैं। 2013 से 2018 के बीच विपक्ष में रहने और मात्र 21 सीटों पर सिमटने के बावजूद राजस्थान के किसी बड़े चेहरे ने पार्टी नहीं बदली। यहां तक की घनश्याम तिवाड़ी सहित भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कई राज्यों में बनी-बनाई सरकार गंवाई। मप्र और कनार्टक में कांग्रेस सरकार से हाथ धो बैठी। वहीं गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस 2017 में सरकार नहीं बना सकी। 2020 में राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार पर संकट आए। मगर आखिरकार अशोक गहलोत कांग्रेस को इस संकट से उबारने में सफल रहे।

राजस्थान वो राज्य रहा है, जहां से कांग्रेस के कई बड़े नामों को राज्यसभा भेजा गया है। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल हैं। यहां तक की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वर्तमान में राजस्थान से ही राज्यसभा सदस्य हैं। वहीं अब राजस्थान से ही प्रियंका गांधी को अगले चुनावों में राज्यसभा भेजने की तैयारी है। पिछले कुछ समय में राजस्थान के नेताओं पर ही कांग्रेस से जुड़ी देशभर की बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं। विपक्ष में रहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के संगठन महासचिव थे। उस दौरान कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी गहलोत ने संभाली। वहीं इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को विपक्ष में रहते बिहार, सिक्किम सहित कई राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में भी रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वहीं इससे पहले राजस्थान के ही हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया था। वहीं सचिन पायलट किसी पद पर नहीं होते हुई भी हर चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आते हैं। राजस्थान से ही राहुल गांधी के विश्वासपात्र रघुवीर मीणा और भवंर जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी में सदस्य हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञ और सीएसडीएस-लोकनीति से जुड़े प्रोफेसर संजय लोढ़ा कहते हैं कि राज्य में पार्टी की एक स्थिर सरकार है। इसका स्थानीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। राज्य की दलीय व्यवस्था में दो प्रमुख दलों में बारी-बारी से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है। इसीलिए यहां कांग्रेस से नेताओं का कहीं और पलायन नहीं हुआ। बल्कि दूसरे दलों से नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पार्टी का सामाजिक आधार भी सुरक्षित रहा है। मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय नेतृत्व से बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रदेश राजनीति के इन्हीं आयामों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर शहर में हो रहा है।

उधर, राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा गठित समिति के माध्यम से राजस्थान की सरकार में जो कदम उठाए गए, उसी दिशा में आगे काम करने की जरूरत है ताकि अगले साल एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी दायित्व देगा, वह उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन वह सिर्फ यही चाहते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की दशकों पुरानी परंपरा इस बार टूट जाए। गौरतलब है कि सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब एक दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी। गहलोत और पायलट राजस्थान में कांग्रेस के दो विपरीत ध्रुव के तौर पर देखे जाते हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

2023 के चुनाव की तैयारी में कांग्रेस

सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में पिछले 30 सालों से एक परिपाटी है कि एक बार भाजपा सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार। एआईसीसी ने लगभग दो साल पहले जो समिति बनाई थी, उसके माध्यम से हमने सरकार के भीतर कुछ उपयोगी कदम उठाए हैं। उसी पर आगे काम करना है ताकि संगठित होकर 2023 के विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बना सकें। उन्होंने कहा, अच्छी मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिलकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में दायित्व मिलने की संभावना पर पायलट ने कहा, 22 साल से राजनीति में हूं। पार्टी ने मुझे जब-जब कोई जिम्मेदारी दी है, मैंने उसे पूरी निष्ठा से निभाया है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष मुझे जो निर्देशित करेंगी उस काम को करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम राजस्थान में सरकार दोबारा बनाएं। उन्होंने इस बात को दोहराया, हमने एआईसीसी की समिति के माध्यम से कुछ काम किए हैं और मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। मालूम हो कि सचिन पायलट ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की थी।

फंस गई उद्धव सरकार!

एक विज्ञापन में बड़ी ही खूबसूरत लाइन है- 'अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो, दाग अच्छे हैं!' मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी को नफरत की राजनीति से जोड़कर देखा गया, लेकिन उसका असर तो जैसे जनहित में नजर आने लगा है। बेशक राज ठाकरे ने मस्जिदों से अजान के मुकाबले लाउडस्पीकर पर पांचो वक्त हनुमान चालीसा बजाने की धमकी दे रखी हो, लेकिन असर तो मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर पर भी वैसा ही हो रहा है और अगर इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है तो राजनीति का ये अंदाज भी अच्छा कहा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

अब अगर राज ठाकरे की एक राजनीतिक पहल से आम आदमी की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो। किसी की नींद में खलल रुक जाता हो। ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता हो, तो ऐसी राजनीति की तो तारीफ ही करनी चाहिए। जिस तरह से सत्तापक्ष के नेता वैसे तो राज ठाकरे को भाजपा का भोंपू साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लगा नहीं कि सरकार धमकी को गंभीरता से लेगी, लेकिन ये क्या, असर इतना तेज हुआ है जिसकी मनसे नेता को भी शायद ही उम्मीद रही हो। राज ठाकरे की डेडलाइन अभी दूर है, लेकिन खबर है कि मुंबई की मस्जिदों के दो तिहाई लाउडस्पीकर बंद हो गए हैं और बाकियों की आवाज धीमी हो चुकी बताई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक और अन्य शहरों में भी पुलिस की तरफ से ऐसी ही तत्परता देखी जा रही है। वैसे राज ठाकरे की धमकी का महाराष्ट्र में असर होना तो भाजपा की बहुत बड़ी कामयाबी ही समझी जाएगी, क्योंकि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की घोषणा के पीछे भाजपा का ही हाथ माना जा रहा है।

लाउडस्पीकर को लेकर 90 के दशक के आखिर से ही अदालतों से आदेश आने लगे थे। अलग-अलग कई उच्च न्यायालयों की तरफ लाउडस्पीकर से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी को निजात दिलाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन उस पर अमल करने में राजनीतिक नेतृत्व ने न तो दिलचस्पी ली और न ही कभी इच्छाशक्ति दिखाई। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन उस पर अमल आधे-अधूरे मन से ही होता दिखा।

चूंकि राज ठाकरे के तेवर पहले से ही ऐसे रहे हैं कि हर किसी को उनकी हर मुहिम में उनका राजनीतिक स्वार्थ ही नजर आता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राजनीतिक तौर पर अब तक फेल रहने की वजह भी यही लगती है। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में मनसे के पास सिर्फ एक विधायक है। मनसे नेता राज ठाकरे ने 3 मई के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर न उतारे जाने पर धमकी दी थी कि वो हर जगह तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। राज ठाकरे ने ये भी कह रखा है कि जब-जब मस्जिद से अजान होगी, तब-तब हनुमान चालीसा बजेगा। पूरे पांच बार। राज ठाकरे के इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे ने आगे आकर अपने चाचा को महंगाई और देश के सामने छाए हुए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की सलाह दी। आदित्य ठाकरे ने बहाने से ये आरोप भी लगाया कि ये सब महाराष्ट्र में उनके पिता की गठबंधन सरकार को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सबसे असरदार हिस्सेदार एनसीपी नेता शरद पवार ने सलाह दी कि राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि वो तो राज ठाकरे को भी राहुल गांधी की तरह पार्टटाइम पॉलिटिशियन ही करार दिए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तो राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी ही बताने लगे हैं। हालांकि, संजय राउत कहते हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को उनके राजनीतिक विरोधी भाजपा के सबसे बड़े मददगार के तौर पर पेश करते रहे हैं। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया, इसलिए संजय राउत ने मनसे नेता को ही भाजपा का लाउडस्पीकर बता डाला। राज ठाकरे को लेकर संजय राउत के बयान के बाद तो मनसे कार्यकर्ताओं ने शिवसेना मुखपत्र सामना के दफ्तर के बाहर धमकी भरा पोस्टर ही लगा दिया और याद दिलाने लगे कि जैसे एक बार उनकी कार पर हमला हुआ था, वैसे ही सबक सिखाया जा सकता है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन के ऐसे बयानों के बावजूद, महाराष्ट्र में जो असर दिखाई दे रहा है वो बिलकुल अलग है। असर देखकर तो यही लग रहा है कि बयानबाजी अपनी जगह रही, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने राज ठाकरे की तरफ से उठाए गए मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है।

● **बिन्दु माथुर**

क्या उद्धव ठाकरे भाजपा की चाल में फंस गए?

उद्धव ठाकरे के भाजपा के साथ शिवसेना का गठबंधन तोड़ लेने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहने के लिए एक मजबूत पार्टनर की जरूरत रही है। भाजपा नेताओं की तरफ से अक्सर उद्धव सरकार के गिरने के दावे किए जाते रहे हैं और अक्सर उसमें एनसीपी की भूमिका को संदेहास्पद दिखाने की कोशिश रही है। जैसे ही शरद पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेते हैं, ऐसी बातें और जोर-शोर से चर्चाओं में छा जाती हैं। कई तरह की थ्योरी चलने लगती है। समझा जाता है कि भाजपा एक साथ दोनों से मोलभाव कर सकती है। भाजपा को मतलब तो बस इसी बात से है कि चाहे जैसे भी मौजूदा सरकार गिर जाए। ऐसे में कभी भाजपा और शिवसेना की सरकार के कयास लगाए जाते हैं तो कभी भाजपा और शिवसेना के गठबंधन सरकार की। जब भी ऐसी बातें होती हैं एनसीपी और शिवसेना दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं और भाजपा की दाल नहीं गल पाती। मौका देखकर भाजपा ने महाराष्ट्र गठबंधन के खिलाफ राज ठाकरे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। असल में राज ठाकरे घाट-घाट का पानी पीकर थक चुके हैं और उनको पार्टी के साथ-साथ बेटे अमित ठाकरे को भी स्थापित करना है। मुश्किल है कि ये सब करने के लिए पहले खुद को ही खड़ा करना होगा। मौजूदा माहौल में भाजपा के अलावा और किसी से ऐसी मदद तो मिलने से रही।

योगी-राज में सब शांति-शांति है...

देश के कई राज्यों की फिजाएं गर्म हैं लेकिन उप्र में इस हॉट वेदर में भी सब कूल-कूल है। इतिहास गवाह है कि जब भी देश में साम्प्रदायिक तनाव फैला है तो इसकी शुरुआत उप्र से हुई है। लेकिन अब इसके विपरीत पुरानी दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा उल्टी गिनती गिनने लगी है। भले ही देश के तमाम सूबों में साम्प्रदायिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं पर उप्र की योगी सरकार में शांति और अमन का राज कायम है। नवरात्रि-हनुमान जन्मोत्सव और रमजान साथ-साथ मनाया गया, लेकिन टकराव तो दूर कहीं किसी किस्म की तकरार की घटना भी सामने नहीं आई। जबकि यहां मुस्लिम आबादी भी खूब है और दोनों धर्मों की धार्मिक गतिविधियां सिर चढ़कर बोलती हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, मप्र, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों से छुटपुट ही सही पर साम्प्रदायिक घटनाएं चिंता का विषय बनी हैं। उप्र जिसे पूर्व में सबसे संवेदनशील सूबा कहा जाता था देशभर में तनाव के बावजूद यहां सब शांति-शांति है। बेहतर कानून व्यवस्था देने के इनाम में सूबे की जनता ने करीब पौने चार दशक का रिकार्ड तोड़कर योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है।

पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ये भी कहती नजर आई थी कि भले ही महंगाई, बेरोजगारी, खेतों को तबाह करती आवारा पशुओं की समस्याओं से हम परेशान हुए पर बेहतर कानून व्यवस्था और प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी सरकार ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इसलिए वंस मोर योगी। ये सच भी है और आंकड़े भी यही बताते हैं कि जो उप्र हर दौर में दंगों और हिंसा की आग में जलता रहा अब यहां पिछले पांच वर्षों से साम्प्रदायिक दंगा या बड़ी हिंसा की घटना सामने नहीं आईं। जबकि पिछले पांच वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण थे। कई बड़े आंदोलन और अयोध्या मामले में राम मंदिर के हक में फैसला आने के बाद उप्र की कानून व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एनआरसी और सीएए के विरोध में देशभर में हिंसा हुई, दिल्ली में तो साम्प्रदायिक दंगों में दर्जनों लोगों की जान चली गई, पर उप्र सरकार की सख्त कानून व्यवस्था ने हिंसा को पनपने का कोई मौका नहीं दिया।

इसी तरह राम मंदिर का फैसला आने के बाद चुस्त-दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर के होते परिंदा पर भी नहीं मार सका। बताते चलें कि पांच वर्ष पूर्व उप्र के संगठित अपराध और पेशेवर आपराधिक गैंग परवान चढ़ते थे अब सब के सब धराशाई हो गए। अपनी खूंखार आपराधिक प्रवृत्ति से आम नागरिकों का जीना दुश्वार करने वाले दर्जनों दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। जिन माफियाओं और हिस्ट्रीशीटर्स को कुछ राजनीतिक दलों की सत्ता ने संरक्षण दिया और नायक की तरह पेश किया वे सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तमाम क्रिमिनल्स, गुंडे, मवाली और पेशेवर दंगाई उप्र से पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। तोड़फोड़ और दंगे फैलाने की साजिश रचने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ यहां इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि अब ऐसे लोगों को आगे शांतिभंग करने की हिम्मत ही नहीं होती।

शायद योगी की गुड गवर्नेंस का ही असर है कि जहां कई राज्यों में नवरात्रि-हनुमान जन्मोत्सव और रमजान के दौरान टकराव की घटनाएं घटीं, वहीं उप्र में अमन-चैन और शांति से हिंदू और मुस्लिम समाज अपनी-अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। खबरें ये भी आईं कि दिल्ली सहित तमाम राज्यों में हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी से शांति भंग हुई। जबकि देश में साम्प्रदायिक पारा चढ़े होने के बीच ही उप्र के लखनऊ और नोएडा जैसे तमाम शहरों में साम्प्रदायिक सौहार्द की तस्वीरें देखने को मिलीं। यहां रामनवमीं और हनुमान जन्मोत्सव से जुड़े जुलूसों, शोभायात्राएं में एकत्र हिंदू भाईयों का स्वागत करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पानी और शर्बत वितरित किया।

उप्र की तमाम सरकारों और जनता की नब्ज टटोल लेने में माहिर समाजसेवी परवेज अहमद कहते हैं कि उप्र में योगी सरकार रिपीट होने से मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही इतनी तासीर है कि इस सूबे में साम्प्रदायिक दंगों के कुचक्र पर विराम लग चुका है। उप्र दंगा मुक्त हुआ तो इससे सर्वाधिक राहत मुस्लिम समुदाय को मिली, वैसे तो हिंसा या दंगा सबके लिए घातक है किंतु भीड़ की हिंसा में उन्हें जानमाल का अधिक नुकसान होता है जिनकी तादाद कम (अल्पसंख्यक) होती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

न मस्जिद में लाउडस्पीकर बजेगा, न मंदिर में

बीते दिन गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने धार्मिक स्थलों, विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर, डीजे के संबंध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। लाउडस्पीकर को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं वाकई उनका पालन होता है? या फ़िर वो महज सियासत के लिए हैं। इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन जो सूरत-ए-हाल हमें उप्र में दिखाई दे रहा है वहां आदेश के मद्देनजर मंदिर तो बस बहाना हैं। लाउडस्पीकर के संदर्भ में अपनी सुचिता और सुविधा के हिसाब से जो फैसला उप्र सरकार को लेना है वो ले लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन मंदिर-मस्जिद का शोर थमेगा उसी दिन हमें बुनियादी समस्याएं सुनाई देंगी और शायद यही वो वक्त हो जब हमारे वोट के जरिए सदन पहुंचे जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को अमली जामा पहनाएं। बहरहाल शुरुआत में ही जिक्र नोटिस का हुआ है तो ये बताना भी बहुत जरूरी है कि अधिकारियों ने 602 मंदिरों, 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ-साथ 217 बारात घरों, 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल, डीजे संचालक उच्च न्यायालय के ध्वनि संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार ने बढ़ाई भाजपा की चिंता

बिहार में भाजपा और जदयू के गठबंधन की रार के बीच उपचुनाव में भाजपा को मिली हार ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अप्रैल को राबड़ी देवी के बंगले पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होकर प्रदेश की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। इससे भाजपा में बेचैनी है। बिहार के बोचहां उपचुनाव में भाजपा की हार बेइज्जती जैसी है। क्योंकि बोचहां उपचुनाव को छोड़ दें तो बाकी जगह उसी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं जिसकी राज्य में सरकार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में हिस्सेदार कांग्रेस। बोचहां उपचुनाव नीतीश कुमार के लिए होम एक्जाम जैसा ही था और वो फेल हुए हैं। ये चुनाव ऐसे दौर में हुआ है जब नीतीश कुमार को बिहार से हटाए जाने की चर्चा चल रही है, ताकि भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कोई नेता बिठा सके। हार को लेकर जवाबदेही तो नीतीश कुमार की ही बनती है और मानकर चलना होगा भाजपा तो सवाल खड़े करेगी ही। बोचहां उपचुनाव के नतीजों ने तो वीआईपी नेता मुकेश सहनी की दुनिया ही लूट ली है। उप्र चुनाव में मुकेश सहनी की हरकत से खफा भाजपा ने बोचहां उपचुनाव के जरिए ही सबक सिखाने का फैसला किया था।

बिहार भाजपा के नेता बोचहां उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की मांग कर रहे थे। तकरार की शुरुआत भी इसी बात को लेकर हुई। भाजपा ने अपना प्रत्याशी बोचहां में तो खड़ा किया ही, अचानक एक दिन वीआईपी के तीन विधायकों को भाजपा ज्वाइन करा दी। बोचहां में वीआईपी कोटे से चुनाव जीते मुसाफिर पासवान के निधन के कारण ये उपचुनाव हुआ था। अभी मुकेश सहनी प्लान ही कर रहे थे कि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने वीआईपी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली। फिर मुकेश सहनी ने पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे अमर पासवान पिता मुसाफिर पासवान की विरासत अपने पास रखने में सफल रहे। अमर पासवान ने भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36 हजार से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वीआईपी की गीता कुमारी तो तीसरे स्थान पर रहीं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को छठवें स्थान पर भेज दिया। ये हार कन्हैया कुमार के खाते में दर्ज होती है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस की कमान उनको थमाने की चर्चा है, नेतृत्व एक बार विचार तो करेगा ही।

हार में भाजपा के लिए कोई संदेश है क्या?

जैसे तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए एनडीए की टीम ने डेरा डाल रखा था, बोचहां के साथ भी वैसा ही रहा। चूंकि चुनाव भाजपा के हिस्से का रहा, इसलिए पार्टी ने अपनी तरफ से भी कोई कसर बाकी न रहे, ऐसी भरपूर कोशिश की थी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जहां भाजपा के सीनियर नेता अमित शाह के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, बिहार से ही आने वाले एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बढ़-चढ़कर चुनाव कैंपेन में शामिल थे। बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह ने तो नित्यानंद राय पर ही पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी और वो कहीं से भी पीछे नजर नहीं आए।

बोचहां से पहले दो सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान आरजेडी नेता लालू यादव जेल से बाहर थे। तेजस्वी यादव ने लालू यादव को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। लालू यादव ने आरजेडी उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैली तो की, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित नहीं कर सके। बोचहां उपचुनाव से पहले लालू यादव को फिर से जेल चले जाना पड़ा। हाल ही में बिहार में भी लोकल अथॉरिटीज से विधान परिषद् के चुनाव हुए थे और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 24 में से 6 सीटें जीत लीं। एनडीए के हिस्से में 13 सीटें ही आ सकीं। 7 भाजपा के खाते में और 6 जेडीयू के। अव्वल तो बोचहां उपचुनाव की जीत बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खाते में ही दर्ज होगी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि भाजपा की हार को नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जाएगा। इससे पहले बिहार की दो सीटों पर चुनाव हुए थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ये दोनों ही सीटें जेडीयू के हिस्से की रहीं और नीतीश कुमार को पार्टी की सीटें उसके पास बरकरार रखने का क्रेडिट भी मिला था।

उपचुनावों के नतीजे सत्ताधारी दल के पक्ष में ही सामान्यता आते हैं, ऐसी मान्यता रही है और मौजूदा नतीजे भी यही बता रहे हैं। यहां तक कि बिहार में हुए पिछले दो उपचुनावों के नतीजे भी सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में ही पाए गए, फिर तो सवाल उठेगा ही कि ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत दिला दी और बोचहां में भाजपा की हार नहीं बचा सके? थोड़ा पीछे लौटकर बोचहां के नतीजे देखें तो 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की याद दिलाते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के उप्र का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। नतीजे आए तो मालूम हुआ कि भाजपा के उपेंद्र दत्त शुक्ला को समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद ने चुनाव में हरा दिया था।

हार का बदला तो भाजपा ने प्रवीण कुमार निषाद को पार्टी ज्वाइन कराकर और गोरखपुर सीट से भोजपुरी स्टार रवि किशन को सांसद बनाकर ले लिया, लेकिन गोरखपुर सदर सीट पर उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला के प्रदर्शन ने पुराने किस्से ताजा कर दिए थे। सुभावती शुक्ला, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में थीं और अच्छा खासा वोट भी पाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि सपा और बसपा के गठजोड़ को हल्के में ले लिया गया था। हालांकि, तब चर्चा ये भी रही कि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में ज्यादा दिलचस्पी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो उपेंद्र दत्त शुक्ला की जगह किसी और को टिकट दिलाना चाहते थे। क्या नीतीश कुमार का मामला भी वैसा ही लगता है? उम्मीदवार को लेकर तो नीतीश कुमार का कोई रिजर्वेशन नहीं रहा होगा, लेकिन दिलचस्पी लेने की वजह भी नहीं समझ में आती। भला उस भाजपा के उम्मीदवार की जीत के लिए नीतीश कुमार क्यों जी जान लगाएं जो उनकी बिहार से विदाई की रणनीति पर काम कर रही हो?

● **विनोद बक्सरी**

संकट में सोने की लंका

आम भारतीय में रामायण की कथा के कारण श्रीलंका की छवि 'सोने के लंका' के रूप में अंकित रही है। ऐसा नहीं कि श्रीलंका ग़रीब या आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र रहा है; लेकिन वर्तमान में वो गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसी 10 अप्रैल को श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने बेहद कड़े शब्दों में राजपक्षे सरकार को कह दिया कि वह उसके काम में हस्तक्षेप न करे। यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय श्रीलंका के ख़ज़ाने में महज़ 5,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बची थी और ज़रूरत की चीज़ों के बहुत ज़्यादा महँगा होने के कारण जनता सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कई कारण हैं; लेकिन प्रमुख हैं- चीन के क़र्ज़ के जाल में फँसना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह बैन करना और अपनी चादर से ज़्यादा पाँव पसारना।

श्रीलंका का यह संकट कितना गहरा है? यह इस बात से साबित हो जाता है कि राजपक्षे सरकार को हफ़्ते भर के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित करना पड़ा। मार्केट में खाने-पीने की चीज़ों की लूट होने के भय से सेना तैनात करनी पड़ी। विदेशी मुद्रा भण्डार ख़त्म होने के ख़तरे से श्रीलंका सरकार को वैश्विक स्तर पर हाथ पसारने पड़े हैं और उनकी मुद्रा (करेंसी) की क़ीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच चुकी है। श्रीलंका की यह हालत अचानक नहीं हुई है; क्योंकि पिछले कुछ साल से इस संकट के संकेत मिलने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद क़दम उठाने की जगह मनमर्ज़ी के ख़र्चे किये गये और क़र्ज़ उठाया गया। दो साल पहले कोरोना महामारी ने जब दुनिया में तबाही मचानी शुरू की, तो श्रीलंका की अर्थ-व्यवस्था जबरदस्त धक्का लगा। इसका कारण यह है कि श्रीलंका की आर्थिकी कृषि के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटन पर निर्भर है। श्रीलंका सरकार की वेबसाइट के मुताबिक, पर्यटन श्रीलंका की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10 फ़ीसदी का योगदान देता है। कोरोना महामारी के इन दो वर्षों ने इस क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पर्यटक ब्रिटेन, रूस से भारत से आते हैं।

महामारी की पाबंदियों से श्रीलंका में पर्यटकों का आना कमोवेश पूरी तरह बन्द हो गया था। अब जब कुछ समय से महामारी का असर कम हुआ है, श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़ जनता के प्रदर्शनों को देखते हुए बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका जाने से बचने की सलाह दे दी। इससे श्रीलंका आने वाले पर्यटकों की संख्या वहीं-की-वहीं है। कनाडा ने तो करेंसी एक्सचेंज की समस्या का हवाला देकर बाक़ायदा एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिससे श्रीलंका की आय पर ख़राब असर पड़ा है। चीन का विस्तारवाद आर्थिक दरवाज़े से होकर गुज़रता है। वह दूसरे देशों को पैसे (क़र्ज़) के ज़रिये अपने जाल में फँसाने के लिए बदनाम रहा है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद श्रीलंका और नेपाल उसके शिकार हुए हैं। पाकिस्तान अमेरिकी ख़ैरात के सहारे अपना गुज़ारा चलाता रहा है; लेकिन श्रीलंका की हालत ख़राब हो गयी हैं। नेपाल भी आर्थिक संकट के मुहाने पर है। श्रीलंका आज क़र्ज़ के बोझ में दबा पड़ा है और अकेले चीन का ही उस पर पाँच बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क़र्ज़ है। भारत और जापान जैसे देशों के अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का भी उस पर क़र्ज़ है।

श्रीलंका से सरकारी आँकड़ों के मुताबिक मार्च, 2022 तक श्रीलंका पर क़रीब 46 बिलियन डॉलर का विदेशी क़र्ज़ था। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे देश का भारी-भरकम विदेशी क़र्ज़ तो ज्यों-का त्यों ही रहता है; ऊपर से वह जो पैसे जुटाता है, वो क़र्ज़ के ब्याज चुकाने में ही ख़प जाते हैं। इससे उसके हालात और बिगड़े हैं। इसके अलावा हाल के समय में श्रीलंका सरकार ने अचानक केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह बैन कर 100 फ़ीसदी ऑर्गेनिक खेती की नीति लागू कर दी थी। इस अचानक बदलाव ने श्रीलंका के कृषि क्षेत्र को तबाह करके रख दिया। जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस फ़ैसले से श्रीलंका का कृषि उत्पादन घटकर क़रीब आधा रह गया। इसी का नतीजा है कि श्रीलंका में चावल और चीनी की जबरदस्त क़िल्लत पैदा हो गयी है। अनाज की जमाख़ोरी के देश की समस्या को विकराल कर दिया है। सन् 2021 में श्रीलंका सरकार ने जब सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों-रात 100 फ़ीसदी जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा की तो रातों-रात जैविक खादों की ओर आगे बढ़ जाने के इस प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को गम्भीर रूप से प्रभावित किया। यह इस फ़ैसले का ही असर था कि हाल में श्रीलंका के राष्ट्रपति को बढ़ती खाद्य क़ीमतों, मुद्रा का लगातार मूल्यह्रास और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भण्डार पर नियंत्रण के लिए देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इसके अलावा श्रीलंका में भारी बारिशों ने भी किसानों की फ़सलों को बर्बाद कर दिया था, जो अनाज की कमी का एक कारण बना है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

जब श्रीलंका बेहतर था

सन् 2009 में श्रीलंका जब एलटीटीई के 26 साल के गृहयुद्ध से बाहर निकला था, तब भी उसकी जीडीपी वृद्धि दर 7-8 फ़ीसदी की बेहतर स्थिति में थी। यह क्रम सन् 2012 तक चला, जब उसकी जीडीपी वृद्धि दर 9 फ़ीसदी की उच्चतम स्तर पर थी। हालाँकि इसके बाद वैश्विक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट, निर्यात की मंदी और आयात में वृद्धि के साथ सन् 2013 के बाद श्रीलंका की औसत जीडीपी वृद्धि दर आश्चर्यजनक तरीक़े से घटकर आधी रह गयी। ऐसा नहीं कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भण्डार की कमी आज पहली बार हुई है। सन् 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का उस पर बहुत ख़राब असर पड़ा था और उसका विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग ख़त्म हो गया था। इसका कारण यह भी था कि एलटीटीई के गृहयुद्ध के चलते श्रीलंका का बजट घाटा बहुत ऊँचे स्तर पर पहुँच गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका को सन् 2009 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 2.6 बिलियन डॉलर का क़र्ज़ लेना पड़ा। यह सिलसिला चलता रहा और सन् 2016 में श्रीलंका को फिर 1.5 बिलियन डॉलर का क़र्ज़ लेने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा; लेकिन उसकी कठोर शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। इसके बाद श्रीलंका ने इससे उबरने की जब कोशिश की तो उसका कोई नतीजा निकलता उससे पहले ही राजधानी कोलंबो के गिरिजाघरों में अप्रैल, 2019 में बम विस्फोटों में 253 लोगों की मौत का देश के पर्यटन पर पड़ा। इसका सबसे बुरा असर उसके विदेशी मुद्रा भण्डार पर पड़ा और फिर इससे उबरना उसके लिए मुश्किल हो गया।

तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर दुनिया

बच्चे जब जिद पर अड़ते हैं तो उन्हें बहला-फसलाकर, प्यार से मना लिया जाता है, लेकिन यदि राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र सहित दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए जिद पर उतारू हो जाए तो उसे कौन और कैसे समझाए? रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग में यही तो देखने के लिए मिल रहा है। यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। दोनों देशों के हजारों आमलोग और सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद युद्ध रुकने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए कई बैठकें भी हुईं, जो बेनतीजा रहीं। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जैलेंस्की ने रूस से संबंध रखने वाले ग्यारह राजनीतिक दलों की गतिविधियां निलंबित कर दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि तटीय शहर मारीपोल की रूसी सैनिकों द्वारा की गई घेराबंदी को इतिहास में युद्ध अपराध के रूप में जाना जाएगा। जो भी हो, रूस की सामरिक शक्ति को यूक्रेन और नाटो देशों ने जिस तरह से कम करके आंका था, वह उनकी भूल साबित हुई, क्योंकि संयुक्त रूस के अलग-अलग होने के बाद भी उसकी सामरिक शक्ति में कोई कमी नहीं हुई है।

पता नहीं, यूक्रेन किस तरह अन्य देशों और खासकर अमेरिका के बहकावे में आकर रूस से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों को सरकारी अक्खड़पन के कारण अपने जीवन के साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस घमासान में भारत ने तटस्थ की भूमिका का निर्वाह कर बहुत ही उचित कार्य किया है। प्रधानमंत्री सहित विदेश मंत्रालय का यह निर्णय वर्ष 1971 में भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और सोवियत रूस के विदेश मंत्री आइन्द्रे ग्रोमिको द्वारा किए गए समझौता का ही तो पालन करना माना जाएगा। एक वीडियो संदेश द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए जैलेंस्की ने कहा है कि रूस द्वारा शुरू किए गए व्यापक युद्ध तथा उसके साथ कुछ राजनीतिक दलों के संबंध को देखते हुए ऐसे दलों की गतिविधियों को मार्शल कानून की अवधि तक के लिए निलंबित किया गया है। जेलेंस्की कहते हैं, शांतिप्रिय शहर मालीपोल पर हमला करके रूस को क्या मिला? रूस की आलोचना करते हुए जैलेंस्की ने कहा, यह आतंक है, जो सैकड़ों वर्षों तक लोगों को याद रहेगा। काश, जैलेंस्की रूस के साथ युद्ध से पहली ही बैठक में इस बात को समझ लेते तो बेहतर होता।

अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है, क्योंकि न तो नाटो देशों ने और न ही अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में अपनी सेना तथा युद्ध सामग्री को भेजकर युद्ध रूस के खिलाफ लड़ने में मदद कर सका। पिछले हफ्ते करीब 40 हजार लोगों ने मारीपोल से पलायन किया है। यूक्रेन की सांस्कृतिक राजधानी लबीब के लोग भी युद्ध की लपटें महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जीत न मिलने की स्थिति में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन महीनों तक यूक्रेन पर हमले जारी रख सकते हैं। फिर भी यदि युद्ध नहीं संभला तो अंत में उनके परमाणु हथियार तो हाई-अलर्ट पर हैं ही, जिसके बाद उन दोनों देशों के अतिरिक्त कई देश समूल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन, युद्ध काल में उसकी अंतिम विभीषिका की परवाह कौन करता है! हालांकि, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परेशानियां भी कम होती नहीं दिख रही हैं। यूक्रेन में जहां रूसी सैनिकों को युद्ध के लगभग एक महीने बाद भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं राष्ट्रपति पुतिन को अपने जान का खतरा सताने लगा है। शायद यही वजह है कि संभावित परमाणु हमले के डर से उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपने परिवार के सभी सदस्यों को कहीं छिपा दिया है। जबकि, अपने पर्सनल स्टाफ के लगभग 100 लोगों को काम से निकाल दिया है। पुतिन को डर है कि उन्हें जहर देकर मारा जा सकता है।

रूस के कई वरिष्ठ राजनीतिक लोगों ने पुतिन के करीबी लोगों को उनकी हत्या करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यही कारण है कि वह इतने खौफजदा हैं, क्योंकि दक्षिण कैरोलिना के सिनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट कर पुतिन की हत्या करने का आव्हान किया था। लिंडसे ने ट्वीट किया था कि इन सब को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका यही हो सकता है कि पुतिन को बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा आप अपने देश के लिए करेंगे, दुनिया के लिए करेंगे। फ्रांस के एक खुफिया एजेंट का भी यह दावा है कि क्रेमलिन के अंदर के लोग तख्ता पलट कर पुतिन को सत्ता से बेदखल कर हत्या भी कर सकते हैं। जहर की बात इसलिए मजबूत होती है, क्योंकि रूसी सरकार अपने दुश्मनों को जहर देकर मारने के लिए ही जानी जाती है। इस फ्रेंच एजेंट का कहना है कि रशियन इंटेलिजेंस इकलौती ऐसी एजेंसी है जो जहर का इस्तेमाल करती है। विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से होगी कि आखिर युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन समझ में आम लोगों को यह बात नहीं आती कि जब राष्ट्र में कोई मानव जीवित ही नहीं बचेगा तो युद्ध का किसको क्या लाभ मिला?

● **कुमार विनोद**

यूक्रेन का जनजीवन अस्त-व्यस्त

भारत को भी अमेरिकी सरकार द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है कि यदि भारत अपनी तटस्थता की नीति का परित्याग नहीं करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा भी था कि उन्होंने चीनी अपने समकक्ष शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि यदि चीन, यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमले कर रहे हैं और यदि वह रूस को मदद मुहैया कराने का फैसला करता है, तो बीजिंग के लिए इसके कुछ निहितार्थ और परिणाम होंगे। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तहस-नहस कर दिया है जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं, आस-पड़ोस के देशों में पलायन कर चुके हैं। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। जो बाइडेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बातचीत बिल्कुल साफ थी जिसमें बाइडेन ने जिनपिंग को पुतिन के कदमों को लेकर अमेरिकी आंकलन की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने इस बात पर चिंता जताई कि रूस-यूक्रेन में जैविक हथियारों के उपयोग के आशंकाओं को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और वहां धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रूस ने मिसाइलों से स्कूलों, अस्पतालों तक पर हमला बोला है, जिससे कई मासूम बच्चे और नागरिकों की जान चली गई। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैलेंस्की ने कहा कि यूरोप को रूस के साथ पूरा व्यापार रोक देना चाहिए।

विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम

राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का प्रदर्शन कमजोर

महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं व पोषण की उपलब्धता उनके सशक्तिकरण का एक अनिवार्य कारक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। दरअसल महिला सशक्तिकरण के उपायों को एकांगी रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कुल बजट का 3.4 फीसदी है, जबकि भूटान 7.7, नेपाल 4.6 फीसदी बजट स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध गरीबी के रूप में सामने आता है। लैंगिक समानता के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ानी होगी। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण की मांग पर राजनीतिक दलों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। विश्व लैंगिक भेद रिपोर्ट-2021 के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है।

दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महिला आरक्षण विधेयक देश के राजनीतिक परिदृश्य में विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जाहिर है, लैंगिक समानता की इस ठोस कवायद के लिए न सिर्फ सभी राजनीतिक दलों को, बल्कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। विकास को समावेशी आवरण देने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक समानता से अंतर-संबंधित है। हमारे यहां महिलाओं को वैदिक काल से शक्ति का स्रोत माना गया है। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र से लेकर विज्ञान तक में अपनी काबिलियत साबित की है।

मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र के सशक्तिकरण का प्रतीक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भावी नीतियों के निर्माण और योजनाओं को गति देने में महिलाओं की भूमिका को अहमियत दी जा रही है। इसका एक मकसद अर्थव्यवस्था को टिकाऊ स्वरूप देना भी है। यह अर्थ तंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से ही संभव होगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था की उत्पादकता से है। सामाजिक न्याय का कोई भी प्रयास महिलाओं की आत्मनिर्भरता से ही सुदृढ़ होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लैंगिक भेद सूचकांक (जीजीआई-2020) में भारत 112वें पायदान पर है, जबकि 2018 में यह स्थान 108वां था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार देश में महिला श्रमबल की भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 23.3 फीसदी है। श्रम क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी कम होने के प्रभावों को लेकर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट हमें आगाह करती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत के श्रमक्षेत्र में 2019 में महिलाओं का अनुपात 20.3 फीसदी था। यह पड़ोसी देश बांग्लादेश के 30.5 और श्रीलंका के 33.7 फीसदी से काफी कम है। आर्थिक मंदी हो या फिर कोरोना जैसी आपदा, इनका सबसे अधिक असर महिलाओं पर ही पड़ा।

गौरतलब है कि मार्च-अप्रैल 2020 में लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था, जो कुल महिला कार्यबल का 37 फीसदी था। ऐसे में हमें महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को नए सिरे से प्रभावी बनाना होगा। तभी हम लैंगिक असमानता खत्म कर महिलाओं को आगे ला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आधी आबादी की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का कोई भी जतन शिक्षा के जरिए ही पूरा होगा। इसके लिए होने वाले बजटीय आवंटन के समय लैंगिक संवेदनशीलता को वरीयता देनी होगी। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को भी हासिल किया जा सकेगा। हमारे यहां स्कूलों में पुनः नामांकन, उपस्थिति आदि के तथ्यों में पारदर्शिता का नितांत अभाव बड़ी चुनौती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की दर 17.3 फीसदी रही। प्राथमिक स्तर पर यह 4.74 फीसदी रही। कर्नाटक, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है। कोरोना महामारी ने छात्राओं और स्कूलों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार महिलाओं को शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल विकास के नाम पर अब भी हम सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाओं का एक बड़ा अनुपात असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। कुल कामकाजी महिलाओं में से लगभग 63 फीसदी खेती-बाड़ी के काम में लगी हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में महिलाओं की चुनौतियों का परिदृश्य अलग है।

2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार जब कैरियर बनाने का समय आता है, उस समय अधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती है। विश्व बैंक के आंकलन के अनुसार भारत में महिलाओं की नौकरियां छोड़ने की दर बहुत अधिक है। यह पाया गया है कि एक बार किसी महिला ने नौकरी छोड़ी, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों व अन्य कारणों से पुनः श्रमबल का हिस्सा बनना कठिन होता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर रोजगार केंद्रित नीतियों में उद्योग जगत की जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका एक समाधान तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (वैज्ञानिकी) विषयों के अध्ययन के लिए महिलाओं के प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जाता है। देश में उच्च शिक्षा अर्जित करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है। लेकिन विज्ञान व नवाचार से जुड़े विषयों में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व काफी कम है। स्कूली स्तर पर हैकथान कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर शोध व समस्या समाधान के प्रति छात्राओं में नवोन्मेषी दृष्टिकोण विकसित करना होगा।

आज रोजगार के अधिकांश अवसर सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र में उद्यमशीलता के बिना महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2019-20 के अनुसार भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.1 फीसदी हो गया। 2018-19 में यह 26.3 फीसदी था। इस दशक के अंत तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें जीईआर को 50 फीसदी के स्तर पर ले जाना होगा।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

क्या हनुमान जी बंदर थे?

क्या हनुमान जी बंदर थे? ठीक वैसे ही जैसे हम आज के बंदरों को देखते हैं। फिर आज के बंदर हनुमान जी की तरह इंसानों की भाषा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों आज के बंदर पहाड़ को उठा नहीं सकते? क्यों आज के बंदर अपने शरीर को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते? क्यों आज के बंदर समुद्र पार नहीं कर सकते हैं? कुछ विचारवान तार्किकों का मानना है कि हनुमानजी बंदर नहीं थे बल्कि वानर कबीले से आते थे। ये एक कबीला था जो वानरों की तरह दिखता था लेकिन थे ये सभी इंसान ही। कुछ विद्वानों ने आगे जाकर वानर शब्द का संधि विच्छेद भी कर दिया और कहा कि वन+नर=वानर। यानि वन में रहने वाले इंसानों को वानर कहा जाता था। फिर इनसे पूछिए कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग कैसे लगा दी। अगर ये वनों में रहने वाले नर ही थे तो फिर कौन सा इंसान है जो पहाड़ को उठा सकता है, कौन सा इंसान है जो रूप बदल सकता है या फिर समुद्र पार कर सकता है। फिर रावण ने हनुमानजी की पूंछ में आग कैसे लगाई। क्योंकि वानर यानि वन में रहने वाले इंसान की पूंछ तो नहीं होनी चाहिए थी।

दोनों ही तर्कों यानि वानरों को इंसान कहने वाले और हनुमानजी को आज जैसे बंदर कहने वालों के पास जवाब खत्म हो जाते हैं। मेरा मानना है कि हनुमान, सुग्रीव, वालि, अंगद सभी बंदर ही थे, उनकी पूंछ भी थी, लेकिन ये आम बंदरों की तरह नहीं थे। ये देवताओं के अंश पुत्र थे जिन्होंने वानरों का शरीर धारण किया था।

ठीक वैसे ही जैसे विष्णुजी ने कभी मत्स्य, कभी वाराह, कभी कछुए का शरीर धारण किया था लेकिन थे वो मूल रूप से विष्णु। शरीर धारण करने से वो आम कछुए या मछली, या फिर वाराह नहीं माने जा सकते ना। रामायण में तीन कथाएं इस बात का आधार मानी जाती हैं। पहली, ये कि जब कार्तिकेय के जन्म के पहले शिव और पार्वती के मिलन में देवताओं ने अवरोध उत्पन्न कर दिया तो माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया कि वो अपनी पत्नियों और अप्सराओं से संतान पैदा नहीं कर सकते। दूसरे, जब रावण भगवान शिव को चैलेंज देने के लिए कैलाश पर्वत पर जा धमका तो वहां नंदी ने रावण का रास्ता रोक लिया। रावण ने नंदी के वानर जैसे मुख को देखकर उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी ने श्राप दिया कि रावण तेरा वध वानरों की सहायता से होगा। तीसरे, रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसे न तो देवता, न राक्षस और न ही यक्ष या गंधर्व या कोई पशु मार सके। वो ये इंसान को इसमें जोड़ना भूल गया। अब ये तीनों ही स्टोरी के प्लॉट बन गए।

जब दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे तब सभी देवता उनके पास रावण के वध का उपाय पूछने के लिए गए। वहां विष्णुजी ने कहा कि मैं इंसान का शरीर धारण कर दशरथ के चारों पुत्रों के रूप में अलग-अलग अंशों के साथ अवतार लूंगा। श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु के अलग-अलग अंशों के अवतार थे। यानि विष्णु ने इंसान का शरीर धारण कर राम के रूप में अवतार लिया। इस हिसाब से श्रीराम थे तो इंसान ही लेकिन वो मूल रूप से विष्णु ही थे। आम इंसानों से एकदम अलग थे। उनकी पलकें नहीं झपकती थीं जैसे देवताओं की नहीं झपकती। और भी कई विशेषताएं थी जो उन्हें आम इंसानों से अलग करती थीं और देवता साबित करती थीं।

अब बारी थी दूसरे देवताओं की। सभी देवताओं ने धरती पर बंदरों का शरीर धारण किया और अपनी पत्नियों से अपने अंश पुत्रों को जन्म दिया जिनके सिर्फ शरीर बंदरों और रीक्षों के थे। वो मूलत: थे देवताओं के पुत्र। हनुमानजी की मां अंजना दरअसल पुंजिकस्थला नामक अप्सरा थी जिससे वायुदेव ने अपने अंश पुत्र के रूप में बंदर का शरीर देकर हनुमान को जन्म दिया। इसी प्रकार सुग्रीव सूर्य के अंश पुत्र थे, वालि इंद्र के अंश पुत्र था, नील अग्निदेव के पुत्र थे, जाम्बवंत ब्रह्मा के अंश पुत्र थे जिनका शरीर रीक्ष का था। तो ये सभी शरीर से तो बंदर या रीक्ष थे लेकिन मूल रूप से देवताओं के पुत्र थे इसलिए आम बंदरों से एकदम अलग थे। ये देवताओं की तरह इंसानों की भाषा बोल सकते थे, देवताओं की तरह हवा में उड़ सकते थे, देवताओं की तरह रूप बदल सकते थे और देवताओं की तरह ही शक्तिशाली भी थे। लेकिन इनका शरीर बंदरों वाला था।

एक बात और राम और रावण के युद्ध का कोई लेना-देना इंसानों से नहीं था। सिर्फ राम और उनके भाई ही विष्णु के इंसानी अवतार के रूप में इंसान का शरीर लेकर आए थे। बाकि सभी बंदर, भालू देवताओं के पुत्र थे। ये युद्ध देवताओं के अंशपुत्रों और राक्षसों के बीच हुआ था। इंसान सिर्फ इस युद्ध का दर्शक था। ठीक वैसे ही जैसे किसी नाटक में एक्टर्स अलग-अलग रूप धारण कर एक्टिंग करते हैं और फिर नाटक खत्म होते ही अपने असली रूप में सामने आ जाते हैं। जैसे ही राम राज्य की स्थापना हुई, हनुमान, जाम्बवंत, द्विद और मयंद को छोड़कर सभी विष्णु रूप श्रीराम के साथ वैकुंठ चले गए या फिर स्वर्ग चले गए। इन्होंने अपने बंदर शरीर को छोड़ दिया और वापस देवताओं के शरीर को धारण कर लिया। इसीलिए इसे नाटक या लीला कहा जाता है। इसीलिए रामलीला खेली जाती है। क्योंकि ये देवताओं और राक्षसों के बीच आपस का खेल था, मैच था। मैच खत्म और सभी अपने रूप में वापस आ गए। अब बेचारे रह गए सामान्य बंदर जिनमें हम हनुमान जी को तलाशने लगते हैं, सोचते हैं कि ये फिर इंसानों की तरह क्यों बात नहीं कर पाते, ये रूप क्यों नहीं बदल पाते।

● ओम

हम हार न जाएं जीवन में

मन जब अंतर्द्वन्द से घिर जाए,
तब हार न जाएं जीवन में।
हार न जाएं जीवन में।
कोयल सी वाणी
जब कौए की भांति
कानों को चुभ जाए,
हृदय की विदीर्णता पर जब कोई
लेप न लगाए।
टूटती आस जब
बचाने को कोई हाथ
पंख ना बन पाए,
सफलता की राहों में
जब शूल ही शूल
बिछ जाएं,
हम खुद तब हिमालय बन
तूफानों से टकराएं।
जब कोई आलिंगन को
बांह ना फैलाए,
हम हार न जाएं जीवन में,
हम हार न जाएं जीवन में।
रंगीं जीवन जब
धूल-धूसरित बन जाए,
आंगन का पौधा जब
हमीं से बिसरता जाए,
जीवन की नैया जब पतवार का
सहारा न ले पाए,
नाविक बन हम खुद तर जाएं।
जब आस न आए दामन में,
हम हार न जाएं जीवन में,
हम हार न जाएं जीवन में।
कर्म युद्ध में जब
विपदाएं ही हाथ थमाएं,
कोटि जतन जब निमिष भर
काम न आने पाएं,
क्षितिज तक निहारने पर भी,
कोई अपना साथ नजर ना आए,
साथी बन स्वयं ही संघर्ष से
हम निखरते चले जाएं।
जब सांस ना बचे तन-मन में,
हम हार न जाएं जीवन में,
हम हार न जाएं जीवन में।।

- रेखा घनश्याम गौड़

कर्मठ

अक्षरा जैसे ही ऑफिस से आई देखा मम्मा बिस्तर पर सोई हैं। अचानक जाकर सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ, ठीक तो हैं।

तभी दोनों छोटी बच्चियां प्रज्ञा और विद्या भी खेलकर आ गई, क्या हुआ नानी को?

70 वर्षीय नानी अभी तक घर बाहर हर तरफ अपनी रेस जारी रखती थी, तलाकशुदा बेटी नौकरी पर व्यस्त रहती थी। दोनों नातिन प्रज्ञा, विद्या नानी के साथ मस्त रहती थी।

घर की हर छोटी-मोटी चीज खराब होते ही फोन करना, गैस, फ्रीज, वाशिंग मशीन सब नानी के ही जिम्मे था। घर में कोई पुरुष तो था नहीं। बेटी अक्षरा सब जानती थी कि मम्मा ने जवानी में बहुत कष्ट सहा है, पापा चालीस वर्ष के ही थे, और शराब की आदत ने उन्हें खोखला कर दिया और वो स्वर्गवासी हो गए। मम्मा ने कभी किसी से छुपाया नहीं, साफ बोला, उनके जाने के बाद मैंने जाना जीवन की खुशियां क्या होती हैं। उन्होंने तो पत्नी को गुलाम बनाकर रखा था, पर बाद में गजेटेड अफसर बेटी ने मुझे हर खुशी दी।

आज वही अक्षरा की मम्मा बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, पता नहीं कैसे, उनकी छठी इन्द्रिय ने उन्हें इत्तला दी। उन्होंने बेटी को बुलाकर कहा, सुनो, मुझे ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, प्लीज फोन करो।

बेटी ने फोन किया। दो ऑफिसर्स फॉर्म लेकर घर ही आ गए, बहुत देर तक बैठकर पूछताछ करते रहे, उन्होंने अपनी आंखें, लिवर किडनी सब दान करने का फॉर्म भरवा दिया, किसी तरह सिग्नेचर भी कर दिए।

थोड़ा बहुत रात में खाकर सोई और सुबह उनकी आंखें नहीं खुलीं।

अक्षरा मन ही मन सोच रही थी, जीवन भर मम्मा कर्म करती रहीं, अब उनके अंग भी क्रियाशील ही रहेंगे।

- भगवती सक्सेना गौड़

मायका

रमा अपने घर में सबसे छोटी है। दो भाई मयूर और प्रेम बड़े थे। दोनों की शादी हो जाती है।

अब रमा के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था माता-पिता ने उसके लिए। कभी वो कहते हम तुम्हें इसी शहर में शादी करेंगे, हमें तुम्हारी याद आए तो तुमसे मिल सकें।

रमा की शादी उसी शहर में कर दी। वो वहां बहुत खुश थी। एक दिन उसके माता-पिता का कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों चल बसे। रमा बहुत रोती थी उनको याद बहुत करती थी।

दोनों भाई पैसा कमाने के चक्कर में रमा को भी भूल गए। कभी-कभी रमा घर आती तो अपनी भाभियों का व्यवहार देखकर दुखी होती। एक दिन रमा अपने मायके आई हुई थी। दोनों भाभी आपस में बात कर रही थी।

रमा तो आए दिन यहां आती रहती है। हम कब तक इसका बोझ उठाते रहेंगे। आती है तो खर्चा भी होता है। एक शहर में है तो इसका मतलब ये नहीं है जब मन करें आ जाओ।

यह बात सुनकर रमा तेज-तेज रोने लगी और सोचने लगी मेरा घर आंगन तो मम्मी-पापा के साथ ही चला गया। अब ये मेरा घर आंगन नहीं है। मुझे पराया होने का आज अहसास हो गया।

अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगी।

बेटी के मायके में जब माता-पिता होते हैं, तब तक ही मायका है उसके बाद बेटी का घर आंगन छूट सा जाता है।

- पूनम गुप्ता

लाजवाब महिला क्रिकेटर

हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल नहीं धर्म की तरह है। इसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है। तभी तो कई क्रिकेटर भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्रिकेट देखने के लिए लोग अपना बहुत कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। एक तरफ बेंगलुरु में पुरुष क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच खेल रही है, तो दूसरी तरफ महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रही है। वैसे तो पुरुष टीम के मुकाबले महिला टीम की चर्चा लोगों के बीच बहुत कम होती है, लेकिन इस बार तीन महिला खिलाड़ी अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के जरिए सुर्खियों में बनी हुई हैं। इन तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धि ऐसी है कि जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए।

मिताली राज: इन तीनों खिलाड़ियों के बीच सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के बारे में, जो हमेशा की तरह अपने परफॉर्म में नजर आ रही हैं। इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए मिताली ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो बतौर कप्तान सर्वाधिक आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने सेडॉन पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्डकप के तीसरे और ओवरऑल 24वें मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क के नाम था, जिन्होंने 23 वर्ल्डकप मैच खेले थे। क्लार्क ने साल 1997 से 2005 तक के अपने कैरियर के दौरान 21 मैच जीते, एक हारा और एक मैच बेनतीजा रहा था। वहीं अपना आखिरी वर्ल्डकप खेल रही मिताली ने इस मैच को मिलाकर 24 में से 15 मैच जीते हैं, 8 हारे और एक बेनतीजा रहा है।

लेडी सचिन के नाम से मशहूर 39 साल की मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के दौरान लखनऊ में बनाया था। उनसे पहले इंग्लैंड की शॉरलॉट एडवर्ड्स ये कारनामा कर चुकी हैं। मिताली अपना छठा वर्ल्डकप खेल रही हैं। वो साल 2005 के वर्ल्डकप में पहली बार टीम की कप्तान बनी थीं, तब भारतीय टीम उपविजेता रही थी। उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं।

स्मृति मंधाना: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोका है। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में स्मृति मंधाना के बल्ले से निकली शतकीय पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थान पर पहुंचा दिया। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ा स्कोर हासिल करने के लिए एक बड़ी पारी की जरूरत थी, जो मंधाना के शतक की वजह से संभव हो पाया। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 108 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। वर्ल्डकप में मंधाना का ये पांचवां शतक है, जिसमें से दो शतक तो उन्होंने इसी वर्ल्डकप में बनाए हैं। इस तरह महिला वर्ल्डकप के इतिहास में मंधाना के बल्ले से दूसरी बार शतकीय पारी निकली है। इससे पहले उन्होंने साल 2017 के वर्ल्डकप में शतकीय पारी खेली थी। देखा जाए तो इस बार का शतक ऐसे समय लगा है, जब टीम को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी।

साल 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू करने वाली स्मृति मंधाना ने साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। साल 2017 में मंधाना इंग्लैंड के खिलाफ फिर मैदान में उतरीं। इस बार उन्होंने 90 रन बनाए थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्वकप के फाइनल तक पहुंच गई थी। बताते हैं कि स्मृति ने बचपन से ही अपने भाई को क्रिकेट खेलते देखा है। उनके भाई श्रवण महाराष्ट्र के लिए अंडर-15 टीम में खेलते थे। क्रिकेट में भाई की लगन और उनकी बनती पहचान को देख स्मृति मंधाना भी क्रिकेट की ओर आकर्षित हुईं। उन्होंने क्रिकेट में ही कैरियर बनाने की ठान ली। 11 साल की उम्र में स्मृति का अंडर-19 टीम में सिलेक्शन हो गया था। साल 2013 में स्मृति घरेलू मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आई थी। उस दौरान स्मृति ने गुजरात के खिलाफ 150 गेंदों पर 224 रन बनाए थे।

● आशीष नेमा

झूलन गोस्वामी ने लिए वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा विकेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने भी इस वर्ल्डकप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए इतिहास रच दिया है। वर्ल्डकप के 10वें मुकाबले में वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद का विकेट लेने के बाद वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं हैं। उन्होंने वर्ल्डकप में 40 विकेट लिए हैं। चकदा एक्सप्रेस नाम से मशहूर इस गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी लिन फुलस्टन को पछाड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फुलस्टन ने साल 1982 से 1988 के बीच खेलते हुए वर्ल्डकप में कुल 39 विकेट लिए थे। जबकि झूलन को ये रिकॉर्ड बनाने में 20 साल लग गए हैं। उन्होंने साल 2002 में 19 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल के साधारण कस्बे चकदा में पली-बढ़ी हैं। वो भी एक ऐसे परिवार में, जो लड़कियों के खेलकूद की बजाय उनकी पढ़ाई-लिखाई और शादी-विवाह के बारे में ज्यादा सोचता है। 15 साल की उम्र तक झूलन ने सपने में भी क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा नहीं था। वो क्रिकेट की बजाय फुटबॉल की प्रशंसक थीं। लेकिन इत्तेफाक ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में खींच लिया। साल 1997 में महिला क्रिकेट वर्ल्डकप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के इडेन गार्डन में खेला जा रहा था। उस मैच में झूलन भी मैदान पर एक बॉल गर्ल के रूप में मौजूद थीं। यहीं उन्होंने फैसला किया कि वो भी क्रिकेटर बनेंगी। हालांकि, उनकी सोसायटी में लड़कियों का लड़कों के साथ खेलना तक मना था।

अखबार में छपी तस्वीर देखकर मेकर्स ने श्रीनिधि को ऑफर हुई थी केजीएफ

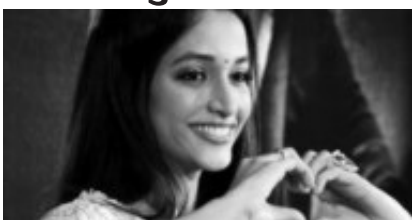

केजीएफ-2 की सफलता के बीच एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने एक इंटरव्यू में खास बातें शेयर कीं। उन्होंने कहा- 2016 में मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और मैं टॉप-3 में रही थी। उसके कुछ फोटो अखबार में आए थे। किस्मत से मेरे जो डायरेक्टर हैं वह उस समय अपनी फिल्म के लिए एक न्यू फेस ढूंढ रहे थे। उन्होंने बहुत सारी प्रोफाइल देखीं, जिनमें कुछ जाने पहचाने लोग भी थे और कुछ नए भी। यह मेरी किस्मत थी की न्यूज पेपर में आई हुई फोटो पर उनकी नजर पड़ी और मुझे 'केजीएफ' में काम करने का मौका मिला।

श्रीनिधि ने कहा- मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस जीरो है। तो प्रशांत मेरे लिए सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है बल्कि मेरे टीचर, मेंटर हैं। जो भी कुछ मैंने सीखा उन्हीं से सीखा और वह भी अपनी पहली मूवी में। उनका विजन बहुत अच्छा है। बहुत सारी गैंगस्टर मूवी आती हैं पर प्रशांत का अपना एक स्टाइल है। उनके काम में जो 70 के दशक वाला फील भी आ जाता है और मॉडर्न फील भी। मुझे यह फिल्म काफी खूबसूरत लगी है। प्रशांत मुझे फ्रेम में रखते थे, सीन सिखाते थे और विजुअल दिखाते थे, यह सब एक जादू से कम नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूं कि वह जादूगर हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि एक ऐसी फिल्म का मैं भी एक हिस्सा हूं।

...जब सेट पर उल्टियां साफ करती थीं रवीना टंडन

रवीना टंडन को फिल्म केजीएफ-2 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए जमकर तारीफें मिल रही हैं। रवीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि एक फिल्मी फैमिली से बिलॉन्ग करने के बाद भी उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत स्टूडियो के फर्श पर उल्टियां साफ करने से की थी। साथ ही रवीना ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेस बन जाएंगी।

रवीना ने बताया कि 10वीं क्लास पूरी करने के बाद वह डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट किया करती थीं। उन्होंने बताया, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत स्टूडियो के फर्श पर पोछा लगाने और उल्टियां साफ करने से की थी। मैं डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट किया करती थी। तब वो मुझसे कहा करते थे कि तुम स्क्रीन के पीछे क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्क्रीन के सामने होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती थी, नो नो मैं एक्ट्रेस? कभी नहीं। मैं इस इंडस्ट्री में इत्तेफाक से हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगी। रवीना ने आगे बताया कि वो फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग किया करती थीं। जब वो कक्कड़ के साथ काम कर रही थीं तब अगर कोई मॉडल सेट पर नहीं पहुंच पाती थी तो डायरेक्टर रवीना को मेकअप करके पोज देने के लिए कहते थे। तब रवीना ने डायरेक्टर के लिए फ्री में मॉडलिंग करने के बजाय इससे कुछ पैसा कमाने का सोचा। इसके बाद रवीना को फिल्मों के ऑफर आने लगे। रवीना ने बताया कि उन्हें उस वक्त न तो एक्टिंग आती थी, ना डांस और ना ही डायलॉग बोलने आते थे। सब उन्होंने काम करते हुए धीरे-धीरे सीखा।

शाहिद कपूर को स्कूल से थी नफरत, एक्टर को किया जाता था परेशान

शाहिद कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि मुंबई में स्कूल के दिनों में उन्हें बुली किया जाता था। एक इंटरव्यू में शाहिद ने बताया कि जब वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए तो उन्हें स्कूल में परेशान किया जाता था। मुंबई में स्कूल के मुकाबले उनकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी। शाहिद ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई की है।

शाहिद, नीलिमा अजीम और एक्टर पंकज कपूर के बेटे हैं। उन्होंने दिल्ली के ज्ञान भारती स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद 10 साल की उम्र में वो मुंबई

शिफ्ट हो गए। मुंबई में शाहिद ने राजहंस विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पूरी की। शाहिद के पेरेंट्स के तलाक के वक्त एक्टर केवल 3 साल के थे।

मुंबई के स्कूल में शाहिद को किया गया था बुली

कर्ली टेल्स के इंटरव्यू में शाहिद ने कहा कि, मुंबई में मुझे अपने स्कूल से नफरत थी, मुझे वहां परेशान और बुरी तरह से ट्रीट किया गया। स्कूल टीचर भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मुझे दिल्ली में अपने स्कूल से बहुत प्यार था, वहां मैं केजी क्लास से था और मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे। मैं मीठीबाई कॉलेज में था, बॉम्बे में मैंने अपने कॉलेज में बहुत मजे किए, लेकिन स्कूलिंग अच्छी नहीं थी।

घुटना-छू, संस्कृति छू

जब चरण-स्पर्श की बात चली है, तो ये जानना भी तो आवश्यक है कि अंततः ऐसा आचरण एक मानुष दूसरे मानुष के साथ क्यों करता है? युग-युग से करता आ रहा है। आज तो उसकी लकीर ही पीटी जा रही है, जो पिटते-पिटते चरणों से जांघों तक की यात्रा कर चुकी है।

अतीत की बात हो गई, जब लोग अपने से ज्ञान, गुण और आयु में बड़े, गुरुजन, माता-पिता, इष्ट देवता आदि के चरण स्पर्श किया करते थे। अब तो पैर छुआने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों-लुगाइयों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। जैसे- नेता, अधिकारी, मंत्री आदि। बहू के द्वारा सास, ससुर, पति, ननद आदि के पैर छूने की परम्परा भी रही। किंतु ज्यों-ज्यों पैर-छुआने वालों की सूची ऊंची होती गई, छूने वालों के हाथ छोटे पड़ते गए। पहले दंडवत प्रणाम किया जाता था, किंतु डंडों की अति बढ़वार ने कुछ ऐसा जुल्म ढाया कि चरण-स्पर्श की ही अंतिम सीमा बन गई। अब दण्डवत प्रणाम इतिहास बनकर रह गया। उसके बाद चरण-स्पर्श का युग आया, जो राजनेताओं की बाढ़ के कारण चरण-चुम्बन में बदल गया।

जब चरण छुआने वालों की सूची ऊंची होने लगी, तो चरण-छुवइया क्या सीढ़ी लगाते चरण छूने के लिए? इसलिए वे मात्र घुटनों तक ही टिककर रह गए। एक औपचारिकता का प्रदर्शनात्मक निर्वाह। उधर जब सब अपने-अपने अहं में सब तने हुए हों तो कौन किसके पैर छुए! इसलिए एक औपचारिकता पूरी कर लो और अपना उल्लू सीधा करने की तजबीज कर डालो। जब घुटने पर घुटने छूते-छूते मात्र घुटन्ना तक ही सीमित हो गए, तो बेचारे घुटने भी घुटन के मारे कब तक बच पाते, वे पिराने लगे, घुटने लगे। उनमें दर्द होने लगे। अब आदमी ऊपर चढ़ते-चढ़ते जांघों तक पहुंच गया है। निरंतर प्रगति हो रही है। अरे भाई! घुटने, जांघें भी तो चरणों का ही हिस्सा हैं। कहीं भी छू डालो, स्पर्श-करंट वहां तक चला ही जाएगा, जहां तक उसे जाना चाहिए। सो सज्जनो! और देवियो!! अब घुटनों और जांघों को आराध्य मानकर इससे ऊपर जाने की कोशिश भी मत करना, अन्यथा आपके ऊपर इंडियन पैनल कोड की धाराएं ही बहती नजर आएंगीं।

जब चरण-स्पर्श की बात चली है, तो ये जानना भी तो आवश्यक है कि अंतत: ऐसा आचरण एक मानुष दूसरे मानुष के साथ क्यों करता है? युग-युग से करता आ रहा है। आज तो उसकी लकीर ही पीटी जा रही है, जो पिटते-पिटते चरणों से जांघों तक की यात्रा कर चुकी है। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक तेज होता है, जो उसके नेत्रों और चेहरे पर चमकता है। किंतु हमें यदि उससे उसके तेज का कुछ अंश चाहिए तो उसके चरण या पैर नहीं, बल्कि उसके चरणों के नाखूनों के अग्रिम भाग का स्पर्श करना चाहिए। इससे चरण छूने वाले के हाथों के माध्यम से उस व्यक्ति के तेज का कुछ अंश उस चरण-स्पर्शक में चला जाता है। जो लोग इस बात को जानते हैं, वे किसी से भी अपने चरण स्पर्श नहीं करवाते। अति महत्वाकांक्षी, दूसरों की दृष्टि में अपने को बड़ा दिखने का प्रदर्शन करने वाले, राजनेता, कुछ तथाकथित रिश्तेदार अपने चरण छुवाकर गौरव की अनुभूति करते हैं। जिन्हें अपना तेज किसी को नहीं देना, वह कोई मूर्ख थोड़े ही है जो, ये काम करवाएगा!

अब आप ये भी न समझें कि आप अपने चरण छुवाना चाहते हैं तो आप मूर्ख हैं। जी नहीं, मूर्ख नहीं, अतिमहत्वाकांक्षी तो निश्चित ही हैं। अब मेरी ये बात जानकर आप अपना निर्णय बदल लें या मेरी बात को मेरी अज्ञानता मानकर इस आंख से देखें और उस आंख से बाहर कर दें, दाएं कान से सुनें और बाएं से बाहर का रास्ता दिखा दें, तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि आज कोई भी किसी से कम ज्ञानी नहीं है। आज की नई युवा पीढ़ी तो कुछ आवश्यकता से भी अधिक ज्ञानी हो रही है, जो किसी ज्ञानी, अनुभवी, बड़े बुजुर्ग की बात मानने और सुनने को भी तैयार नहीं है। अब नहीं है, तो नहीं है कोई क्या कर लेगा उनका। उनका अहंकार और गर्म खून का उबाल पुरानी पीढ़ी, अपने माता-पिता, गुरुजन आदि सबको नकारता है। बस अपने को सही और सबको मूर्ख और अज्ञानी मानता है। इसलिए पांव छुवाने के लालची घर-घर, दर-दर, गांव-गांव, नगर-नगर बिना ढूंढे मिल ही जाएंगे। कोई ज्योति पुंज लेकर ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है।

'घुटना-छू' संस्कृति की बढ़वार ही आ गई है। छूने वालों की भी मजबूरी है कि वे किसी की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए किसी के चरण बनाम घुटने बनाम जांघें छुएं। थोड़ा-सा झुके या बिना ही झुके झट से जांघें छू लीं। जींस और टाइट पेंट धारी नई पीढ़ी झुके भी कैसे? उनकी फटी हुई फैशनी जीन्स से उनके घुटने ही बाहर आ जाएंगे। वे टाइट ही इतनी हैं कि झुकने ही नहीं देतीं। ऐ चरण छूने वालो! हां, इतना ध्यान अवश्य रखना किसी नारी की जांघें मत छूने लग जाना। पता नहीं क्या परिणाम हो। कहीं आपको ही विपरीत न पड़ जाए। इतना अवश्य है कि वर्तमान कालीन 'घुटना-छू संस्कृति' से संस्कृति ही (उड़न) छू होने लगी है। 'नेता युग' में 'नेता- संस्कृति' ही तो पनपेगी। जिसका पोषण नई पीढ़ी बाकायदा घुटने और जांघें छू-छूकर कर रही है।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687